अल।

उप-न्यायिक देयता समिति इत्यादि

बनाम

भारत संघ और अन्य

29 अक्टूबर, 1991

[बी. सी. राय, एल. एम. शर्मा, एम. एन. वेंकटचालिया,

जे. एस. वर्मा और एस. सी. अग्रवाल, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 124 (4) और (5) और 118-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना-राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव और लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और एक समिति का गठन करेंगे न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत जांच और आधारों के प्रमाण के लिए-क्या लोकसभा के भंग होने पर चूक होती है-क्या न्यायाधीश (जांच) अधिनियम अनुच्छेद 124 (5) के तहत कानून होने के नाते चूक के सिद्धांत के संचालन और अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियमों को भी बाहर रखा गया है-क्या अनुच्छेद 124 (5) और 118 विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं प्रश्न यह है कि क्या प्रस्ताव समाप्त हो गया है या नहीं। न कि लोकसभा के विघटन पर।

अनुच्छेद 124 (4) और (5) और 121-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का दायरा और व्याख्या-चाहे न्यायसंगत हो-कानून का अधिनियमन न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 124 (5)-क्या अनिवार्य शब्द 'कब' का अर्थ 'कब' के रूप में लगाया जाए ',

अनुच्छेद 124 (4) और (5) और 32-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना-संवैधानिक प्रक्रिया से अलग, क्या उच्चतम न्यायालय के पास न्यायपालिका है कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करना और संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने से रोकना-क्या यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को कानूनी निर्देश दे सकता है कि वे जांच का सामना कर रहे संबंधित न्यायाधीश को कोई न्यायिक कार्य आवंटित न करें, न्यायिक कार्यों का निर्वहन जारी रखें -

अनुच्छेद 32 जनहित याचिका जांच समिति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कथित कदाचार की जांच करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि समिति अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो और न्यायाधीश को समिति के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान न्यायिक कार्य करने से रोका जाए।सी. आई. ए. एल. जवाबदेही और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुकदमा करेंगे-क्या न्यायालय निष्फलता, औचित्य के आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है।और निरर्थकता-

कानूनी और संवैधानिक स्थिति की घोषणा-का कर्तव्य न्यायालय-राज्य के विभिन्न अंगों के दायरे में मामलों पर विचार करने के लिए उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968:

की संवैधानिक वैधता

धारा 3 और 6-न्यायाधीश को हटाना-प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करना और अध्यक्ष द्वारा गठित समिति लोक सभा कदाचार के आरोपों की जांच करेगी-क्या चूक हुई सदन के विघटन पर-क्या अधिनियम, जिसके तहत कानून बनाया गया हैसंविधान के अनुच्छेद 124 (5) में चूक के सिद्धांत और अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए लोकसभा के लिए प्रक्रिया के नियमों को भी शामिल नहीं किया गया है-अध्यक्ष की कार्रवाई—क्या नोटिस से इनकार करने और निर्णय से पहले के आधार पर दूषित किया गया है संबंधित न्यायाधीश और अध्यक्ष के राजनीतिक संबंध को सुनने का अवसरवैधानिक अपवादों या आवश्यकता का सिद्धांत

संवैधानिक कानूनः

संघीय व्यवस्था के तहत शक्तियों का पृथक्करण-न्यायालय-व्याख्याकार

राज्य के विभिन्न अंगों के अधिकार की सीमाएँ-न्यायिक समीक्षा आकस्मिक

लिखित संविधान की अवधारणा से प्रवाहित और

उच्च कानून।

संविधान की व्याख्याः

ऐसे निर्माण जो संविधान की मौलिक विशेषता को मजबूत करते हैं, उन्हें अपनाया जाएगा-कानून का शासन-चाहे वह एक बुनियादी विशेषता हो-स्वतंत्रता

न्यायपालिका-चाहे कानून के शासन की आवश्यक विशेषता हो।

संविधान सभा की बहसों के निर्माण में सहायता-क्या हो सकती है

निर्भर किया जाए-अन्य देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन

क्या यह उचित परिप्रेक्षय प्रदान करता है-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सहारा लें

चाहे अनुमति हो।

प्रशासनिक कानून प्राकृतिक न्याय-न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत-अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं और दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन करते हैं कि क्या संबंधित न्यायाधीश सुनवाई के पूर्व-निर्णयात्मक अवसर के हकदार हैं।

उप-न्यायिक उत्तरदायित्व पर समिति v. यू. ओ. आई. 3

अभ्यास और प्रक्रिया:

न्यायाधीश को हटाना-बार के सदस्यों के संचालन के लिए लंबित संवैधानिक प्रक्रिया-स्वामित्व के लिए आवश्यक था कि न्यायाधीश को आरोप साबित होने से पहले ही शर्मिंदा नहीं होना चाहिए-अदालत के अंदर और बाहर बहस का स्तर-गरिमापूर्ण और सम्मानजनक होना चाहिए।

शब्द और वाक्यांश: शब्द 'मे'-कब 'विल' के रूप में पढ़ा जा सकता है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उनके द्वारा किए गए कथित कदाचार के लिए उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और इस न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद से मिलकर एक समिति का गठन किया। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2)। इसके बाद, लोकसभा को भंग कर दिया गया और इसका कार्यकाल समाप्त हो गया।

यह समझने पर कि प्रस्ताव के साथ-साथ उस पर अध्यक्ष का निर्णय लोकसभा के विघटन के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था, केंद्र सरकार ने अध्यक्ष के निर्णय की सहायता के लिए कार्य नहीं किया और यह अधिसूचित किया कि समिति में दो वर्तमान न्यायाधीशों की सेवाओं को संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी के पैरा 11 (बी) (i) के अर्थ के भीतर "वास्तविक सेवा" के रूप में माना जाएगा।इसके बाद, न्यायिक उत्तरदायित्व पर एक उप-समिति नामक एक निकाय, न्यायिक उत्तरदायित्व पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा गठित एक उप-समिति होने का दावा करता है ताकि न्यायिक उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाया जा सके।

सम्मेलनों के प्रस्तावों को लागू करने का कार्य, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, व्यापक सार्वजनिक हित में और विशेष रूप से, मुकदमेबाज जनता के हित में मामले पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए, इस न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएं दायर कीं। दोनों याचिकाओं के लिए दो समान प्रार्थनाएँ थीं, पहला, कि भारत संघ को न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाए और दूसरा, कि समिति के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक कार्य करने से रोका जाना चाहिए।

कृत्यों और न्यायिक शक्तियों के प्रयोग से।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि लंबित कार्य सत्रावसान पर समाप्त हो जाता है, और एक सामान्य व्यवहार के रूप में सदन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. था।

2 एस सी आर।

4

आम तौर पर इसे भंग करने से पहले स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन महाभियोग मो

राष्ट्र अपने स्वभाव में सुइ-जेनेरिस थे और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया लैप्स; कि यह सवाल कि क्या कोई गति समाप्त हो गई या नहीं, एक चटाई थी

जिस सदन के कार्य के संचालन से संबंधित

सदन एकमात्र और अनन्य स्वामी था; चटाई का कोई पहलू नहीं था।

एक न्यायाधीश को नोटिस जारी करना चाहिए और उसे पहले पेश होने के लिए कहना चाहिए कि इन कार्यवाहियों को अनुशासनात्मक नहीं माना जा सकता है

या दंडात्मक कार्यवाही और अध्यक्ष कुछ भी तय नहीं करेंगे 'उस स्तर पर न्यायाधीश के खिलाफ और केवल यह तय करेगा कि क्या

मामले की जांच होगी; कि संवैधानिक तंत्र एक न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायपालिका के लिए केवल एक राजनीतिक उपाय था

व्यक्तिगत दुर्व्यवहार और उपलब्ध न्यायिक उपचार को बाहर नहीं किया गया

वादियों को न्यायिक अखंडता सुनिश्चित करने और लागू करने के लिए, कि

मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार था

अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और जिसने अपने व्यापक दायरे में, जैसा कि इसमें विरासत में मिला है, निर्दोष व्यक्तियों के साथ एक निष्पक्ष न्यायपालिका का अधिकार लिया है।

अदालत को स्थानांतरित करना ही बंजर और खोखला हो जाता है, कि अदालत स्वयं के पास अधिकार क्षेत्र था-न कि अखंडता सुनिश्चित करने का कर्तव्य और

इसे बनाने वाले सदस्यों की निष्पक्षता और किसी भी सदस्य को प्रतिबंधित करना।

जिनमे उन आवश्यक गुणों और उपलब्धियों की कमी पाई गई थी

जो जनता के विश्वास का निर्माण करता है।

एक अन्य रिट याचिका एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी

उप द्वारा दायर रिट याचिकाओं में दूसरी प्रार्थना का विरोध करें न्यायिक जवाबदेही समिति और सुप्रीम कोर्ट बार

एसोसिएशन। यह तर्क दिया गया था कि जब तक जांच समिति वास्तव में सहयोगी संबंधित न्यायाधीश को आरोपों का दोषी नहीं पाती, तब तक कोई नहीं होना चाहिए

उसके न्यायिक कार्यों का निषेध और यह कि यदि ऐसा निष्कर्ष दर्ज किया गया था तो उसके बाद उस समय तक जब तक कि प्रस्तुत प्रस्ताव

न्यायाधीश को हटाने के लिए अभिभाषण का निपटारा संसद के सदनों द्वारा किया गया था-जिसमें 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों से अलग होने के लिए कह सकते हैं।

एक अन्य रिट याचिका भी एक अधिवक्ता द्वारा दायर की गई थी।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 100,105,118,121 और 124 (5) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह घोषणा करने की मांग करता है कि प्रस्ताव पहले से लागू है।

108 संसद सदस्यों द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के लिए भेजा गया-न्यायिक उत्तरदायित्व पर समिति v.

यू. ओ. आई. 5

लोकसभा के भंग होने के साथ यह समाप्त हो गया था। याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने और समिति के गठन से पहले संबंधित न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर देने से इनकार करने के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार करने के अध्यक्ष के फैसले को रद्द करने की भी मांग की।

एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय से खुद को वापस लेने की मांग की गई थी।

उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जहां राहत उन लोगों के समान थी जिनके लिए अधिवक्ता द्वारा दायर रिट याचिका में अनुरोध किया गया था। रिट याचिका को उच्चतम न्यायालय में वापस लेने का निर्देश दिया गया था और अन्य रिट याचिकाओं के साथ दाढ़ी थी।

इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले और

जांच के लिए एक समिति का गठन करते हुए, स्वाभाविक न्याय की न्यूनतम आवश्यकता के रूप में, अध्यक्ष पर यह दायित्व था कि वह न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर प्रदान करे क्योंकि इस तरह के निर्णय के न्यायाधीश और समग्र रूप से न्यायिक प्रणाली दोनों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम थे और यह कि एक न्यायाधीश को घेरने के लिए कोई भी राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम न केवल न्यायाधीश को प्रभावित करेगा, बल्कि न्यायाधीश को भी प्रभावित करेगा।

न्याय प्रशासन की पूरी प्रणाली और इसलिए यह न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के उद्देश्यों और उद्देश्यों को बहुत आगे बढ़ाएगा यदि संबंधित न्यायाधीश को इस तरह की सुनवाई दी गई; कि अध्यक्ष ने संवैधानिक प्रथा के विपरीत काम किया था, कि जिस तरह से उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया था, वह दुर्भावनापूर्ण था और चूंकि अध्यक्ष ने उपस्थिति दर्ज नहीं की थी और आरोपों से इनकार किया था, इसलिए उन्हें स्वीकार किया माना जाना चाहिए; कि न्यायालय के निर्णय और उसके रिट को जिस क्षेत्र में काम करना है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को अपने न्यायशास्त्र का प्रयोग करने से इनकार करना चाहिए, और यह कि दिया गया कोई भी निर्णय या जारी किया गया कोई भी रिट अंततः व्यर्थ और निष्फल हो सकता है क्योंकि और

समिति द्वारा जाँच अपने आप में कोई ऐसा अंत नहीं था, और न ही इसका कोई स्वतंत्र कानूनी परिणाम होने का इरादा था, बल्कि केवल एक न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर सदन के विचार-विमर्श से पहले और उससे पहले की कार्यवाही थी, जो निर्विवाद रूप से संसद के सदनों के अनन्य प्रांत के भीतर थी, जिस पर

न्यायालयों ने कोई नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया।भारत संघ की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 107,108 और 109 को एक साथ पढ़ने से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सदन के भंग होने पर सभी विधेयक [1991] एस. यू. पी. पी. होंगे।

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6

केवल अनुच्छेद 108 में निर्धारित अपवाद के अधीन चूक, कि पहले सिद्धांत पर भी यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि सदन के विघटन पर कोई भी प्रस्ताव तब तक नहीं रहना चाहिए जब तक कि प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत अन्य वार निर्धारित नहीं किया गया हो; चूक का सिद्धांत इस विचार का एक आवश्यक सहवर्ती था कि प्रत्येक नवगठित सदन एक अलग इकाई थी जिसका अपना जीवन था जब तक कि पिछले सदन का कार्य क़ानून या प्रक्रिया के नियमों के बल से नहीं किया जाता था और यह सवाल कि क्या प्रस्ताव समाप्त हो गया था या नहीं, मामले का मार्गदर्शन करने वाले कानून के प्रावधानों के आधार पर निर्णय लिया जाना था और सदन स्वयं इसका अंतिम मध्यस्थ नहीं था और अकेले न्यायालय को मामले के कानून की जांच करने और उस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था।

मामलों का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय,

पकड़ना: बहुमत से प्रति रे, जे. (अपने लिए, वेंकटचलैया,

वर्मा और अग्रवाल, जेजे)

1.1 जहाँ एक लिखित संविधान है जो

मौलिक और उस अर्थ में एक "उच्च कानून" और संविधान के तहत अनुदान प्राप्तकर्ताओं के रूप में विधानमंडल और राज्य के अन्य अंगों पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है, संसदीय शासन की सामान्य घटनाएं जहां भी प्राप्त नहीं होती हैं और अवधारणा 'सीमित शासन' में से एक है। न्यायिक समीक्षा एक घटना है और यह इस अवधारणा से प्रवाहित होती है कि मौलिक और उच्च कानून राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमाओं की कसौटी है जो संविधान के तहत शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं और यह कि न्यायिक शाखा

संविधान का दुभाषिया है और इसलिए, राज्य के विभिन्न अंगों के अधिकार की सीमाओं का। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक बन जाती है। एक कानूनी साधन के रूप में संविधान का अंतर दिखावा और इसका दायित्व न्यायालयों का कार्य है। यह जोरदार रूप से प्रांत है और

न्यायिक विभाग का कर्तव्य है कि वह बताए कि कानून क्या है। [51 जी-एच, 52 ए, डीजे

1.2 संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए

न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता के लिए न्यायालय को एक ऐसा संविधान अपनाना चाहिए जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं और मूल संरचना को मजबूत करे। कानून का शासन संवैधानिक ताने-बाने की एक बुनियादी विशेषता है और संवैधानिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है। [31 डी]

1.3 संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ निकालने में, कानून और उप-न्यायिक देयता पर समिति v.

यू. ओ. आई. 7

अन्य देशों में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

विचार समझ और अंतर के लिए एक उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।संवैधानिक योजना का ढोंग। [31 जी-एच]

बैरिंगटन मामला [1830]; टेरेल बनाम। के लिए राज्य सचिव

उपनिवेश और एक अन्य, [1953] 2 क्यू. बी. 482, संदर्भित।

संविधान सभा बोल पर बहस करती है। आई से VI @पीपी 899,900 वॉल्यूम।

VIII @pp। 243-262 , संदर्भित किया गया।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण। खण्ड. पी 1108; शेट्रीट जज ऑन ट्रायल '(1976); पीपी। 404-405 ; रॉडनी ब्रेज़ियर 'संवैधानिक ग्रंथ' (1990) पीपी। 606-607 ; गॉल 'द कैनेडियन लीगल सिस्टम' (1983); पीपी। 184-186 , 189 ; ऑस्ट्रेलियाई संविधान पर लेन की टिप्पणी (1986) पी। 373 ; मैकलेलैंडः ' ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीशों को अनुशासित करना (1990) 64 ए. एल. जे. 388, पी. 403 ; हेनरी जे. अब्राहमः न्यायिक प्रक्रिया, तीसरा संस्करण। पी। 45 ; रॉबर्ट जे. जानोसिकः अमेरिकी न्यायिक प्रणाली का विश्वकोश, खंड II पीपी। 575 578 तक; "संघीय न्यायपालिका का महाभियोग" Wrisley Brown Harvard कानून समीक्षा 1912-1913 684 पर। पृष्ठ 698; 'द

तुलनात्मक परिप्रेक्षय में न्यायिक प्रक्रिया '(क्लेरेंडन प्रेस-ऑक्स

फोर्ड 1989 पृष्ठ 73 पर); (एर्स्किन मे का "कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और संसद का उपयोग" (बीसवां संस्करण लंदन बटरवर्थ्स

1989) ; अभ्यास और प्रक्रिया में एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर

संसद ", संदर्भित।

2.1 यह कहना सही नहीं है कि यह प्रश्न कि प्रस्ताव समाप्त हो गया है या नहीं, प्रस्ताव के संचालन से संबंधित मामला था।सदन का कार्य, जिसमें सदन एकमात्र और अनन्य स्वामी था, और यह कि मामले का कोई भी पहलू न्यायसंगत नहीं था

अदालत। [29 सी, 53 जीजे

2.2 यह प्रश्न कि क्या प्रस्ताव समाप्त हो गया है, संविधान और अनुच्छेद के आधार पर सुनाया जाना है।

नियमों का पालन करें। [53 ई]

2.3 संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की इस तरह की व्याख्या पर, न्यायालय यह घोषणा करने के लिए न्यायपालिका को बनाए रखते हैं कि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव सदन के भंग होने पर समाप्त नहीं होता है। [53 एफ-जी]

ब्रैडलॉफ वी. गोसेट, [1884] 12 क्यू. बी. डी. 271, विशिष्ट।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. 2 एस सी आर।

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, [1950] एससीआर 88 विशेष

संदर्भ मामला, [1965] 1 एस. सी. आर. 413, संदर्भित।

बार्टन वी। टेलर, [1886] 11 एसी 197, रेडिफुसन (हांगकांग) लिमिटेड बनाम। हांगकांग के महान्यायवादी, [1970] एसी 1136, का उल्लेख किया गया है।

3.1 न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया

प्रस्ताव को स्वीकार करने का बिंदु, समिति का गठन और

समिति द्वारा निष्कर्षों की रिकॉर्डिंग, सख्ती से, अनुकूल नहीं है।

संसद के सदनों में बैठक। अध्यक्ष एक वैधानिक है।

अधिनियम के तहत प्राधिकरण। इस बिंदु तक बात नहीं कही जा सकती है।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहना। [66 ई]

3.2 अनुच्छेद 124 (4) और (5) की योजना यह है कि हटाने की पूरी प्रक्रिया दो भागों में है-खंड (5) के तहत पहला भाग।

दीक्षा से लेकर जांच और दुर्व्यवहार या इंका के प्रमाण तक

शांति एक अधिनियमित कानून द्वारा कवर की जाती है, संसद की भूमिका केवल

कानून के अनुसार दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाणखंड (5) के अधीन अधिनियमित। इस प्रकार, पहला भाग पूरी तरह से वैधानिक है,

जबकि दूसरा भाग अकेले संसदीय प्रक्रिया है। [61 डी]

3.3 संदर्भ और सेटिंग जिसमें खंड (5) दिखाई देता है

अनुच्छेद 124 में खंड (4) के साथ इसकी प्रकृति को इंगित करता है और इसे अलग करता है।

अनुच्छेद 118,119 और 121 से, जो सभी संसद में कार्य की प्रक्रिया और संचालन से संबंधित हैं। [61 बी-सी]

3.4 खंड के तहत संसद द्वारा अधिनियमित कानून की वैधता

(5) अनुच्छेद 124 और उस कानून के अनुसार जांच के समापन तक का चरण, जो पूरी तरह से क़ानून द्वारा शासित है, न्यायिक समीक्षा के लिए खुला होगा क्योंकि अनुच्छेद 124 (4) के तहत संसदीय प्रक्रिया केवल इस निष्कर्ष के दर्ज होने के बाद शुरू होती है कि खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के

अनुसार की गई जांच में कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होती है। इस कारण से, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच की प्रक्रिया और प्रगति पर संसद के अधिकार क्षेत्र की विशिष्टता पर आधारित तर्क और इसके परिणामस्वरूप, इस स्तर पर मामले में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार उत्पन्न नहीं होता है। [59 जी-एच, 60 ए]

4.1 अनुच्छेद 121 बताता है कि पार्लिया में चर्चा पर रोक

किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में आदेश 9 पर हटा दिया जाता है।

उप-न्यायिक उत्तरदायित्व पर समिति v. यू. ओ. आई.

राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए एक न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना करने का प्रस्ताव, जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है। 'प्रस्ताव' और 'जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है' शब्द अनुच्छेद 124 के खंड (4) के उद्देश्य के लिए प्रस्ताव के स्पष्ट संदर्भ हैं, जो बदले में, "सिद्ध" दुर्व्यवहार या अक्षमता की अवधारणा को दर्शाता है। जो बात अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध को उठाती है, वह है 'सिद्ध' दुर्व्यवहार या अक्षमता।

अनुच्छेद 124 के खंड (5) में कानून बनाने का प्रावधान है -

'सिद्ध' के आधार पर हटाने के लिए प्रस्ताव के चरण से पहले जांच का उद्देश्य और कदाचार या अक्षमता का प्रमाणखंड (4) के तहत दुर्व्यवहार या अक्षमता। [56 एच, 57 ए-बी]

4.2 एक न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप है

के अनुसार बनाया जाना, जांच की जानी और पाया जाना

अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद द्वारा उस स्तर तक संसद को शामिल किए बिना अधिनियमित कानून; किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता को प्रदान किए गए तरीके से साबित होने पर।उस कानून द्वारा, उस आधार पर न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए एक प्रस्ताव अनुच्छेद 124 (4) के तहत प्रत्येक सदन में पेश किया जाएगा; दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रमाण के बाद इस तरह से प्रस्ताव पेश किए जाने पर और यह एक विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए है।

न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना करते हुए, अनुच्छेद 121 में निहित चर्चा पर प्रतिबंध हटा दिया जाता है और चर्चा हो सकती है

न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में स्थान;

और आगे के परिणाम संसद के किसी सदन में प्रस्ताव के आने के आधार पर सामने आएंगे। तथापि, यदि अधिनियमित कानून में प्रदत्त तंत्र द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यह है कि आरोप साबित नहीं होता है, मामला

समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 124 (4), [57 जी-एच, 58-ए-बी] के अनुसार प्रस्ताव पेश करने का कोई अवसर नहीं है।

4.3 इस प्रकार कानून के अनुसार कदाचार का पूर्व प्रमाण

अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने के खिलाफ अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटाने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है। अनुच्छेद 124 (4) वास्तव में केवल अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाए गए कानून के साथ सार्थक हो जाता है, जिसके बिना, एक न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक राष्ट्रीय योजना और प्रक्रिया अनिश्चित रहती है। [66 एफ]

4.4 अनुच्छेद 121 का प्रतिबंध संसद में चर्चा पर लागू होता है।

लेकिन जांच और कदाचार या अक्षमता का प्रमाण इस तरह की चर्चा को रोक नहीं सकता है। यह इंगित करता है कि निवेश और प्रमाण के लिए तंत्र अनिवार्य रूप से संसद के बाहर होना चाहिए न कि उसके भीतर। दूसरे शब्दों में, सबूत जिसमें न्यायाधीश के आचरण की चर्चा शामिल है, एक ऐसे निकाय द्वारा होना चाहिए जो सीमा से बाहर हो 10

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 121। नीति यह प्रतीत होती है कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के प्रमाण तक का पूरा चरण, जो आरोप लगाए जाने पर जांच की शुरुआत से शुरू होता है, अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा शासित होता है और अनुच्छेद 121 में प्रदान किए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, उस तंत्र को संसद से बाहर होना चाहिए न कि उसके भीतर। संसद की तब तक कोई भूमिका नहीं है जब तक कि कदाचार या अक्षमता साबित नहीं हो जाती और न ही अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून में प्रदान किए गए तंत्र पर उसका कोई नियंत्रण है। संसद तभी सामने आती है जब कोई निष्कर्ष निकाला जाता है।

वह तंत्र जो कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता है

साबित कर दिया। अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 स्वयं इंगित करता है कि संसद ने एकीकृत को इस प्रकार समझा

अनुच्छेद 121,124 (4) और 124 (5) की योजना। अधिनियम की सामान्य योजना इस दृष्टिकोण के अनुरूप है। [58 एच-59: ए-'डी]

4.5 यह अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून नहीं है जो इसे कम करता है।

या संसदीय प्रक्रिया या इसके न्यायशास्त्र की विशिष्टता को कम करता है।

लेकिन स्वयं संवैधानिक योजना, जिसने खंड (4) और (5) को अधिनियमित करके एक साथ संकेत दिया कि खंड (4) का चरण पूरा हो गया है और उसके तहत प्रक्रिया केवल तभी शुरू होती है जब -

खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार वैध दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होती है। तभी संसद में न्यायाधीश के आचरण पर रोक लगाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है और इसलिए, अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटा दिया जाता है। [60 डी-ई]

5.1 यदि हटाने के लिए एक पता प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है

अनुच्छेद 121 और 124 (4) द्वारा 'हमारे गलत अनुभव या अक्षमता' के आधार पर देखा गया है, यह अनुमान लगाता है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता पहले ही साबित हो चुकी है। यह खंड (4) के विशिष्ट संदर्भ के साथ खंड (5) में उपयोग किए गए एक्सप्रेशन 'जांच और सबूत के कारण अधिक है, जो दर्शाता है कि' जांच और दुराचार या अक्षमता का सबूत खंड (4) के भीतर नहीं है, बल्कि खंड (5) के भीतर है। खंड (5) में सत्र के किसी भी संदर्भ के बिना खंड (4) में 'एक ही सत्र' अभिव्यक्ति का उपयोग यह भी इंगित करता है कि खंड (5) के लिए सदन के सत्र का कोई महत्व नहीं है, यानी 'जांच और प्रमाण जो पूरी तरह से अधिनियमित कानून द्वारा शासित होना है और संसद की प्रथा नहीं है जिसे प्रत्येक लोकसभा द्वारा बदला जा सकता है। [61 एफ-एच]।

5.2 एक्सप्रे से पहले 'सिद्ध' शब्द का महत्व

अनुच्छेद 124 के खंड (4) में 'दुर्व्यवहार या अक्षमता' का संकेत तब भी दिया जाता है जब प्रावधान की तुलना अनुच्छेद 317 के साथ की जाती है।

लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने के लिए। अनुच्छेद 317 के खंड (1) में मूल विषय-न्यायिक उत्तरदायित्व पर समिति v का वर्णन करने के लिए प्रयोग की गई अभिव्यक्ति।

यू. ओ. आई. 11

पश्चाताप का आधार 'दुराचार का आधार' है जबकि के खंड (4) में

अनुच्छेद 124, यह 'साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता का आधार' है।

[62 ए]

5.3 खंड (5) में 'मई' शब्द का उपयोग इंगित करता है कि

' पता प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 'यह एक सक्षम प्रावधान हैऔर कानून के अभाव में, सामान्य प्रक्रिया या

सदन द्वारा हल किया गया आवेदन कर सकता है लेकिन 'जांच और सबूत है

अधिनियमित कानून द्वारा शासित होना। खंड (5) में 'मई' शब्द है - इस दृष्टिकोण के लिए कोई बाधा नहीं। जब कोई प्रावधान प्रभावी होने का इरादा हो

यहाँ यह एक संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए है

अनुच्छेद 124 (4) के तहत न्यायाधीश-यहां तक कि अनुच्छेद के रूप में एक प्रावधान

124 (5) जो अन्यथा केवल सक्षम प्रतीत हो सकता है वह मंडा बन जाता है।

टोरी। शक्ति का प्रयोग अनिवार्य बना दिया गया है। इसका उपयोग

'मई' शब्द आवश्यक रूप से यह इंगित नहीं करता है कि संपूर्ण

खंड (5) एक सक्षमकारी प्रावधान है जो इसे संसद पर छोड़ देता है -तय करें कि जाँच और सबूत के लिए भी कोई कानून बनाना है या नहीं।

दुर्व्यवहार या असमर्थता या नहीं। [62 डी, 62 जी, 63 ई-एफ]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। जोगिंदर सिंह, [1964] 2 एससीआर 197 पर

202 ; पंजाब सिख नियमित मोटर सेवा, मौधपारा बनाम। द रे

राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण, रायपुर और अन्र। , [1966] 2 एससीआर 221,

संदर्भित किया गया।

एरेडेरिक गिल्डर जूलियस बनाम। द राइट रेव. द लॉर्ड बिशप ऑफ

ऑक्सफोर्ड; रेव. थॉमस टेलसन कार्टर, [1879-80] 5 ए. सी. 214 पर

244 , संदर्भित किया गया।

5.4 इसी तरह, प्रक्रिया को इंगित करने के लिए 'गति' शब्द का उपयोग

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में जांच और सबूत, क्योंकि

'अध्यक्ष' के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आरोप धारा 6 में उस अभिव्यक्ति के उपयोग के बावजूद इसे 'सदन में प्रस्ताव' नहीं बनाते हैं। अन्यथा, धारा 6 में यह नहीं कहा जाएगा कि 'दोषी नहीं' पाए जाने के मामले में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इसका केवल यह अर्थ है कि जब आरोप साबित नहीं होता है, तो अध्यक्ष को खंड (4) के तहत प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, जो केवल साबित होने की स्थिति में शुरू की जाती है। इसलिए, अध्यक्ष अधिनियम चो सेन के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है क्योंकि आगे की प्रक्रिया संसदीय है और ऐसी शिकायत करने का अधिकार संसद सदस्यों

को दिया जाता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमन अनुच्छेद 124 (5) के दायरे को रोकने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। [64 ए-सी]

6.1 अनुच्छेद 124 (5) अनुच्छेद के समान क्षेत्र में कार्य नहीं करता है।

118 संसद में कार्य की प्रक्रिया और संचालन से संबंधित।

[61 सी] [1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12

6.2 अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को प्रदान करने वाला एक सामान्य प्रावधान है।

सदन पर बाध्यकारी नहीं हैं और सदन द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं किसी भी समय। नियमों का उल्लंघन एक अनियमितता है और यह है

अनुच्छेद 122 को देखते हुए न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। [64 जी)

6.3 अनुच्छेद 124 (5) एक विशेष प्रावधान की प्रकृति में है

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करने की प्रवृत्तिअनुच्छेद 124 (4), जो सामान्य कार्य का भाग नहीं है।

घर लेकिन विशेष व्यवसाय की प्रकृति में है। यह पूरी तरह से शामिल है

न्यायाधीश को हटाने से संबंधित क्षेत्र। अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियम

इस क्षेत्र में कोई आवेदन नहीं है। [64 एच, 65 ए]

6.4 अनुच्छेद 124 (5) की अनुच्छेद 119 से कोई तुलना नहीं है। लेख

118 और 119 एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। , सामान्य व्यवसाय

घर। इसलिए यह विशेष रूप से निर्धारित करना आवश्यक था कि

अनुच्छेद 118 के तहत बनाया गया आदेश। चूंकि अनुच्छेद 118 और 124 (5) काम करते हैं।विभिन्न क्षेत्रों में, अनुच्छेद 119 में निहित एक प्रावधान था

आवश्यक नहीं है और इस तरह के प्रावधान के अभाव में भी, एक कानून

अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाए गए नियम आरती के तहत बनाए गए नियमों पर हावी होंगे।

धारा 118 और संसद के दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी होगी। ए.

इस तरह के कानून का उल्लंघन अवैध होगा और यह नहीं हो सकता है

अनुच्छेद 122 (1) के तहत न्यायिक जांच से मुक्त। [65 बी-सी]

7.1 न ही यह सिद्धांत कि किसी सदन का विघटन एक पारित करता है

संसदीय स्लेट पर स्पंज और न ही संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए किसी भी नियम या नियमों में निहित विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विघटन के प्रभाव को निर्धारित करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 124 (5) और उसके तहत बनाई गई कानून इस क्षेत्र में अनुच्छेद 118 के संचालन को बाहर करती है। [49 एफ]

पुरुषोत्तमन नम्बूदिरी बनाम। केरल राज्य, [1962] पूरक।

1 एस. सी. आर. 753, संदर्भित।

7.2 अनुच्छेद 124 (5) में परिकल्पित कानून संसदीय कानून है।

जो अनुच्छेद 118 के तहत सदन द्वारा अपने लिए बनाए गए नियमों की तुलना में उच्च गुणवत्ता और प्रभावकारिता का है। इस तरह का कानून चूक के सिद्धांत के खिलाफ प्रावधान कर सकता है। [50 एच]

7.3 न्यायाधीश को हटाने के संवैधानिक क्षेत्र में, कानून

अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाए गए नियमों को थोड़ा और आगे ले जाने और अनुच्छेद 118 के तहत नियमों के संचालन को बाहर करने के लिए माना जाना चाहिए और कोई प्रश्न नहीं-न्यायिक देयता पर समिति v।

यू. क्यू. आई 13

घृणा की स्थिति इस हद तक उत्पन्न हो सकती है कि क्षेत्र अनुच्छेद 124 (5) के तहत कानून के दायरे में आता है। [51 सी]

पंजाब राज्य बनाम। सत पाल डांग एंड ओआरएस, [1969] 1 एस. सी. आर. 478, ने भरोसा किया

पर।

8.1 न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 प्रक्रिया के न्यायिक और राजनीतिक दोनों तत्वों के संवैधानिक दर्शन को दर्शाता है।

8.2 अध्यक्ष, एक प्रस्ताव स्वीकार करते हुए और दुर्व्यवहार के कथित आधारों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करते हुए या अक्षमता सदन के हिस्से के रूप में कार्य नहीं करती है। सदन इस स्तर पर तस्वीर में नहीं आता है। न्यायाधीशों के प्रावधान

(जांच) अधिनियम, 1968 असंवैधानिक नहीं है क्योंकि यह सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों को कम करता है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 संवैधानिक है और अधिकार क्षेत्र में आता है। [66 जी-एच]9.1 न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 एक ऐसा कानून है जिसे अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित किया गया है जो चूक के सिद्धांत के खिलाफ प्रावधान करता है।

9.2 न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (1) और (2) और 6 (2) का प्रभाव यह है कि प्रस्ताव को तब तक लंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि

समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। केवल एक प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है जो लंबित रहेगा। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि प्रस्ताव को सदन के विघटन के सामान्य प्रभाव के अधीन लंबित रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए। [50 जी]9.3 अधिनियम की धारा 3 संसद के दोनों सदनों पर लागू होती है। "प्रस्ताव को लंबित रखेंगे" शब्दों के दो अलग-अलग संदर्भों में दो अलग-अलग अर्थ नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि प्रस्ताव पर विचार रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. पी. तक स्थगित कर दिया जाएगा।

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14

समिति का तात्पर्य है कि उस घटना के घटित होने तक प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। इसलिए, ऐसी गति समाप्त नहीं होती हैसंसद के सदन का विघटन। [51 डी]

10. प्रावधानों के स्तर पर जब अध्यक्ष स्वीकार करता है

ऐसा अधिकार। लेकिन यह अध्यक्ष को रोक नहीं सकता है, अगर तथ्य और उसके समक्ष रखी गई परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि न्यायाधीश की सुनवाई

स्वयं अनुचित नहीं हो सकता है, ऐसा कर सकता है। लेकिन एक निर्णय

प्रस्ताव स्वीकार करें और जांच के लिए एक समिति का गठन करें

इस तरह के अवसर को प्रदान करना, अपने आप में और उसके लिए नहीं है

अकेले कारण, निर्णय को दूषित करें। [68 ई-जी]

11.1 यह सच है कि समाज को उच्चतम अपेक्षा करने का अधिकार है

और न्यायिक आचरण में औचित्य के सबसे सटीक मानक, और

कोई भी आचरण जो पुतले में जनता के विश्वास को कम करता है

न्यायालय की योग्यता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता वास्तव में वर्जित है।

लेकिन, यह प्रस्ताव कि, संवैधानिक तंत्र के अलावा

न्यायाधीश को हटाने के लिए, न्यायपालिका के पास स्वयं अधिकार क्षेत्र है और उचित मामलों में यह कर्तव्य है कि वह अपने सदस्यों में से किसी एक की ईमानदारी की जांच करे और न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने से रोके।

गंभीर जोखिमों से घिरा हुआ है। अदालत तब वास्तव में एक के रूप में कार्य करेगी

न्यायाधिकरण एक न्यायाधीश को हटाने के लिए है और यह समाधान करने की उम्मीद से अधिक प्रोब लेम्स का उत्पादक है। [69 सी, 70 एच]

संपत कुमार और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। [1985] 4 एस. सी.

458 , संदर्भित किया गया।

कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, (Vol.48A), संदर्भित।

11.2 न्यायाधीश को रोकने के निर्देश से राहत

न्यायिक कार्यों का निर्वहन नहीं किया जा सकता है। इस पहलू पर विचार करने के उद्देश्य से न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों सहित संपूर्ण संवैधानिक योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूँकि संवैधानिक योजना यह है कि न्यायाधीश के आचरण पर संसद में भी चर्चा नहीं की जा सकती है, जिसे हटाने की मूल शक्ति दी गई है, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित कानून के अनुसार कथित गलत नलिका या अक्षमता 'साबित' नहीं हो जाती है, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि न्यायाधीश के आचरण पर ऐसी कोई चर्चा या उसके विषय के रूप में कोई मूल्यांकन या निष्कर्ष-न्यायिक योग्यता पर समिति v.

यू. ओ. आई. 15

इस उद्देश्य के लिए कानून के तहत गठित जांच समिति के समक्ष अभियोग के दौरान के अलावा कानून के अनुसार योग्यता की अनुमति है। इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अनुच्छेद 121 के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में निहित इस उद्देश्य के लिए संवैधानिक योजना के समानांतर

चलने वाले किसी भी व्यक्ति में कोई अधिकार हो सकता है। कोई भी प्राधिकरण वह नहीं कर सकता जो संविधान द्वारा किया गया है।

आवश्यक निहितार्थ मना करता है। [71 बी-एफ]

12. यहां तक कि याचिका में लगाए गए आरोपों और दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं पर भी, जिन्हें मजबूत आधारों पर स्थापित करने की आवश्यकता है, ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। दुर्भावना का मामला केवल अध्यक्ष की राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भी नहीं बनाया जा सकता है। कि हो सकता हैवर्तमान संदर्भ में यह पर्याप्त आधार नहीं है। सभी घटनाओं में, मामले से निपटने के लिए एकमात्र वैधानिक प्राधिकरण के रूप में, वैधानिक 'अपवादों या आवश्यकता' के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। [74 बी-सी]

13. जनहित की कार्रवाइयों में मुकदमा करने के लिए खड़े होने के बारे में कानून में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एसयूपीपी है।

2 एस सी आर।

16

वर्षों से एक विशाल परिवर्तन हुआ और उदार। लोकस स्टैंडाई निर्धारित करने के लिए मानकों को अब मान्यता दी गई है। वर्तमान मामला ऐसी प्रकृति का है और इस तरह के संवैधानिक मुद्दे हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि बार के सदस्यों और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। सिद्धांतों और पूर्वजों का एक बार फिर से विस्तृत पुनर्मूल्यांकन अनावश्यक है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि किसी भी दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता मुकदमा करने के लिए स्थिति की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। [74 ई-एफ]

एस. पी. गुप्ता और अन्य। आदि। वी. भारत संघ और अन्य। आदि। , [1982] 2 एस. सी. आर. 365, पर भरोसा किया।

14. प्रार्थना पर कुछ प्रस्तुतियाँ पुनः प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ीं

जब तक समिति की कार्यवाहियों का समापन नहीं हो जाता, तब तक न्यायाधीश को कार्य करने से रोका जाता है, जिसमें उतनी ही औचित्य की कमी होती है, जितनी गरिमा और शिष्टाचार की, जिसके न्यायाधीश हकदार हैं। जबकि सदस्यों नेअधिवक्ता लोक हित में कार्य करने का दावा कर सकते हैं, साथ ही, उनका शिष्टाचार और विशेष देखभाल का कर्तव्य है कि आरोप आधारहीन या किसी भी नैतिक पतन को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त पाए जाने की स्थिति में, न्यायाधीश को प्रक्रिया में अपूरणीय रूप से नुकसान नहीं उठाना पड़े। इस दृष्टिकोण की यह आलोचना नहीं होनी चाहिए कि इसकी गणना एक सक्षम और विनम्र न्यायाधीश को सार्वजनिक अपमान के लिए बेनकाब करने के लिए की गई थी, भले ही ऐसा करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम मंच द्वारा आरोपों की जांच की गई हो। न्यायालय के भीतर और बाहर बहस का स्तर अधिक सभ्य और गरिमापूर्ण होना चाहिए था। स्वामित्व

आवश्यक है कि आरोपों को एकमात्र तरीके से साबित करने से पहले भी

जेराव बेखौ फोरमान खालामनो गनायथि होनाय जादों, अब्ला बिजिरगिरिया लाजिफाजाना नाङा। न्यायाधीशों को संवैधानिक संरक्षण उनके लिए नहीं है।

व्यक्तिगत लाभ; लेकिन न्यायपालिका की रक्षा करने के साधनों में से एक है

और इसकी स्वतंत्रता और इसलिए, व्यापक लोक हित में है।

संवैधानिक तरीकों का पालन किया जाना चाहिए यदि प्रणाली

जीवित रहना था। [74 जी, 75 ए-सी]

15.1 इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की व्याख्या

कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के तहत एक प्रस्ताव सदन के भंग होने पर समाप्त नहीं होता है, एक बाध्यकारी घोषणा राशन है। यदि कानून यह है कि प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है, तो सदन के लिए किसी भी समय ऐसा कहने का कोई अवसर नहीं हो सकता है और यह गलत है -

यह मानते हुए कि संसद के सदन इसका उल्लंघन करेंगे

कानून, क्योंकि कानून की व्याख्या अदालतों की अनन्य शक्ति के भीतर है।

[76 ई] उप-न्यायिक योग्यता पर समिति v. यू. ओ. आई. 17

15.2 यदि सदन को इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसदीय प्रक्रिया अपराध साबित होने के बाद ही शुरू हो सकती है, तो व्यर्थ रिट का भी सवाल नहीं उठता है। यह बात कि सदन दोषी पाए जाने के बाद भी निर्णय ले सकता है कि वह न्यायाधीश को हटाने के लिए मतदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, इस मुद्दे पर विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद 124 (4) के तहत संविधान योजना में ही अनुमत है, इस तथ्य के बावजूद कि क्या अनुच्छेद 124 (5) अनुच्छेद 124 (4) के तहत शक्ति के प्रयोग पर केवल एक सक्षम प्रावधान या संवैधानिक सीमा है।

[60 बी-सी]

15.3 केंद्र सरकार ने स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करने और अध्यक्ष के निर्णय पर अपने कार्यों को विनियमित करने के उद्देश्य से वास्तविक स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास किया है। जिसके तहत

कानून की स्थिति ठीक नहीं है। [76 जी]

15.4 निर्देश के किसी विशिष्ट रिट को किसी भी लेखक को जारी करने की आवश्यकता नहीं है। विषय वस्तु की प्रकृति और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो अंततः सेवा करने के लिए अभिप्रेत है, केवल कानूनी और सही संवैधानिक स्थिति की घोषणा करना और राज्य के विभिन्न अंगों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के दायरे में आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए छोड़ना आवश्यक है। [76 एच, 77 ए]15.5 परिस्थितियों में, न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करने का प्रश्न कि निर्णय प्रदान किया गया है

और इसके द्वारा जारी रिट निष्फल नहीं होगा। [31 ए-सी, 77 ए]

प्रति शर्मा, जे. टी. (असहमति);

1.1 संविधान की बारीकी से जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि संविधान को हटाने के संबंध में एक विशेष पैटर्न अपनाया गया है।

राज्य के तीन अंगों के सदस्य-कार्यपालिका, विधानमंडल और उच्चतम स्तर पर न्यायपालिका, और यह योजना

संविधान में जानबूझकर शामिल किए जाने के कारण, इसके प्रावधानों को समझने में ध्यान रखा जाना चाहिए। दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि जब उच्चतम स्तर पर तीनों शाखाओं में से किसी एक के सदस्य को हटाने का प्रश्न हो - अर्थात। राष्ट्रपति; संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य; और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश-उत्पन्न होते हैं, यह निर्णय लेने के लिए उस स्थान के अलावा किसी अन्य अंग पर छोड़ दिया जाता है जहां समस्या उत्पन्न हुई है। इस प्रतिमान के अनुरूप, अनुच्छेद 124 का खंड (4) जोरदार शब्दों में घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा।

संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत को छोड़कर अपने पद से चले गए। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों [1991] एस. यू. पी. पी.

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18

इस प्रकार उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। योजना का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है

राज्य के तीनों अंगों में विश्वास की कमी। और भी हैं।

तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक विचार और

एक लिखित संविधान को अपनाना, जिसमें आश्वासन शामिल है

लोग जो एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की संभावना को धुंधला कर रहे हैं

जहाँ यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, वहाँ इसकी मदद नहीं की जा सकती है और इसे किया जाना चाहिए। आवश्यकता के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा सामंजस्य स्थापित किया गया, जो नहीं है

तत्काल मामले में आकर्षित। [81 एफ-एच, 82 डी-ई, एफ-जी]

1

ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस v. एम. ए. संगमा, [1978] 1 एससीआर

393 411 पर, संदर्भित।

संघीयवादी: हैमिल्टन, संदर्भित।

1.2 इंडे की आवश्यकता पर दो राय नहीं हो सकती हैं।

हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में लटकती और निडर न्यायपालिका,

लेकिन यह आगे के निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है कि स्वतंत्रता

न्यायपालिका खतरे में होगी, जब तक कि हटाने का मामला न हो

उच्चतम स्तर पर भी न्यायाधीश अंतिम निर्णय के अधीन नहीं होते हैं।

न्यायालयों का नियंत्रण। संविधान के निर्माताओं द्वारा इस पहलू पर बहुत ध्यान दिया गया और प्रत्येक से मामले की जांच की गई।

निर्धारित योजना को अपनाने से पहले संभावित कोण। जहाँ तक

जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध है,

ट्रॉल को उच्च न्यायालय में निहित किया गया है, लेकिन जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात आती है, तो यह संविधान को अपनाने और लागू करने के लिए उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त माना जाता था जैसा कि अब पाया जाता है। इस मामले को विशेष रूप से संसद के हाथों में सौंपने में संविधान सभा के विवेक पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और इस बात में संदेह का कोई आधार नहीं है कि संसद के सदस्य या उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष और अध्यक्ष, संवैधानिक प्रावधानों की सच्ची भावना से कार्य नहीं करेंगे। संविधान का अधिदेश सभी के लिए बाध्यकारी है। [100 बी-ई]

2.1 खंड (4) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था

खंड (5) के तहत एक कानून के अधिनियमन पर शर्त, और अनुच्छेद 124 में खंड (5) डालने का कारण केवल प्रावधानों को विस्तृत करने के लिए था। खंड (4) में यह नहीं कहा गया है कि न्यायाधीश के

दुर्व्यवहार या असमर्थता को केवल खंड (5) के तहत संसद द्वारा पारित किए जाने वाले कानून के अनुसार ही साबित करना होगा। खंड (4) किसी भी उप-न्यायिक उत्तरदायित्व पर समिति v के बिना, उद्देश्य की पूर्ति करना जारी रखेगा जैसा कि अब करता है।

" यू. ओ. आई. 19

यह और एक आदेश नहीं। वर्तमान संदर्भ में, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इसका उपयोग इसके असाधारण अर्थ में किया गया है। [88 एफ)3. अनुच्छेद 121 का उद्देश्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में किसी भी चर्चा को रोकना है, सिवाय इसके कि इसे टाला नहीं जा सकता है। अनुच्छेद, तदनुसार, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के प्रस्ताव को छोड़कर ऐसी चर्चा को प्रतिबंधित करता है। [89 बी]

4.1 न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में "प्रस्ताव" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए लोकसभा नियम संविधान का अनुच्छेद "प्रस्तावों" से संबंधित है। राज्यसभा द्वारा अपनाए गए कार्य संचालन के लिए प्रक्रियाओं के अलग-अलग नियम हैं।

अधिनियम की धारा 3 (1) में कहा गया है कि यदि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए "प्रस्ताव" की सूचना दी जाती है, तो

अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद जो वह उचित समझता है, और ऐसी प्रासंगिक सामग्री भी जो उसके पास उपलब्ध हो या तो "प्रस्ताव" को स्वीकार करता है या उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। जिस तरह से इस धारा में पहली बार किसी परिभाषा या परिचय के बिना अधिनियम में "प्रस्ताव" का उल्लेख किया गया है, वह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह उस "प्रस्ताव" का उल्लेख कर रहा है जिसे आम तौर पर संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में समझा जाता है जो अपने-अपने नियमों को आकर्षित करते हैं। धारा 3 में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि "प्रस्ताव" का नोटिस कैसे और किसे संबोधित किया जाना है या किसे सौंपा जाना है और यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि अध्यक्ष अचानक तस्वीर में कैसे आते हैं जब तक कि लोकसभा नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों को लोकसभा के कुछ नियमों के साथ पढ़ना होगा। नियम 185,186 और 187 जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें अधिनियम का पूरक माना जाना चाहिए। [90 डी-जी, 91 बी]4.2 धारा 3 की उप-धारा (2), जो वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है, कहती है कि यदि उप-अनुच्छेद में निर्दिष्ट "प्रस्ताव"

धारा (1) स्वीकार की जाती है, अध्यक्ष "प्रस्ताव को लंबित रखेगा" [1991] एस. यू. पी. पी.

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20 और आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

1

[91 सी]

4.3 जिस स्थिति में "प्रस्ताव" लंबित है, वह लगभग स्पष्ट है।

इस मुद्दे पर विचार करें कि क्या सदन इसे अपने हाथ में लेता है या नहीं। अधिनियम इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि "प्रस्ताव" सदन में लंबित रहता है न कि उसके बाहर। इसकी पुष्टि धारा 3 (2) के परंतुक में उपयोग की गई भाषा से होती है जो उन मामलों से संबंधित है जहां संसद के दोनों सदनों में धारा 3 (1) के तहत एक ही तारीख को "प्रस्ताव" की सूचना दी जाती है। इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में किसी भी समिति का गठन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि "प्रस्ताव" नहीं दिया गया हो।

" दोनों सदनों में स्वीकार किया गया और जहां ऐसा "प्रस्ताव" दोनों सदनों में पेश किया गया है, वहां समिति का गठन अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह सदन में लंबित "प्रस्ताव" के अधिनियम में अनजाने में दिया गया संदर्भ नहीं है: अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में एक "प्रस्ताव" की परिकल्पना की गई है और उस पर विचार किया गया है जो सदन में स्वीकार किया जाता है और वहां लंबित रहता है, जिसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा तारीख तय किए जाने पर फिर से लिया जाएगा।

समिति से। पूरे अधिनियम में इस आधार पर भाषा का लगातार उपयोग किया गया है और यह समझाने या समझाने में सक्षम नहीं है। [91 डी, जी-एच, 92 ए, सी-डी]

4.4 अधिनियम और नियमों का दायरा निवेश तक सीमित है।

अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए गए "प्रस्ताव" के अनुसरण में अनुदान। जाँच के समापन पर समिति को मूल प्रस्ताव की एक प्रति के साथ अध्यक्ष (या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो) को रिपोर्ट भेजनी होती है। यदि निष्कर्ष न्यायाधीश के खिलाफ जाता है, तो प्रस्ताव, वही मूल प्रस्ताव, रिपोर्ट के साथ उस सदन द्वारा विचार के लिए लिया जाएगा जहां प्रस्ताव लंबित है, और संबोधन और प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। अधिनियम और नियम जिस पर विचार करते हैं वह मूल प्रस्ताव है जिसे सदन द्वारा विचार के लिए लिया जाना है, और यदि यह माना जाता है कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने पर समाप्त हो गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिस पर अधिनियम कार्य करेगा। [92 ई, जी. जे.

4.5 इस प्रकार, मूल प्रस्ताव की अवधारणा लंबित है

समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति पर बहस और मतदान के लिए लिया जाने वाला सदन अधिनियम का जीवन और आत्मा है, और यदि वह प्रस्ताव गायब हो जाता है तो अधिनियम को आकर्षित करने के लिए कुछ

भी नहीं बचा है। यह विचार पूरे अधिनियम और नियमों के माध्यम से चलता है, और इसे किसी विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। सदन में लंबित प्रस्ताव का अस्तित्व एक आवश्यक शर्त है जो न्यायिक योग्यता पर उप-समिति v के आवेदन के लिए आवश्यक है।

यू. ओ. आई. 21

अधिनियम। उसी के बिना, अधिनियम जीवित नहीं रहता है। तत्पश्चात, अधिनियम को पढ़ने की अनुमति नहीं है ताकि इसका अर्थ यह हो कि सदन प्रस्ताव से अभिगृहीत नहीं है और जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक समिति के समक्ष लंबित जांच से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यदि अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) को अन्य प्रकार से समझा जाता है, तो अधिनियम को अधिकार से बाहर, या किसी भी स्थिति में, निष्क्रिय और निष्फल के रूप में निरस्त करना होगा और केवल इसी आधार पर, रिट याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं। [92 एच, 93 ए-बी]

5.1 सदन में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा के खिलाफ संविधान का जनादेश सभी के लिए सम्मान करने के लिए है, और इसे लागू करना अध्यक्ष का बाध्य कर्तव्य है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुच्छेद 121 का संदर्भ और भावना से पालन किया जाए। सदन में प्रस्ताव का लंबित होना अनुच्छेद 121 का उल्लंघन करने का आधार नहीं हो सकता है, और यह आशंका कि यदि प्रस्ताव को सदन में लंबित रखा जाता है, तो इसे स्वीकार करने पर, अनुच्छेद 121 का उद्देश्य विफल हो जाएगा, गलत धारणा है। [93 सी, एफ]

5 : 2 यह व्यापक प्रस्ताव कि सदन को इस मामले को इतने प्रभावी ढंग से लिया गया था कि प्रत्येक सदस्य को किसी भी स्तर पर सदन में चर्चा की मांग करने का अधिकार दिया गया था, न केवल अनुच्छेद 121 का उल्लंघन करेगा, बल्कि 1968 के अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन करेगा। संक्षेप में यह कहना सही नहीं है कि यदि व्यक्तिगत सदस्य के तत्काल चर्चा पर जोर देने के अधिकार से इनकार किया जाता है, तो इसका परिणाम प्रस्ताव के नियंत्रण से संसद को वंचित करना होगा। अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर सकता है, और ऐसा करते समय वह सदन के सदस्यों से भी परामर्श कर सकता है, लेकिन सदन में चर्चा की अनुमति दिए बिना। परामर्श, जिसकी अधिनियम अनुमति देता है, निजी प्रकृति का है, जो सार्वजनिक चर्चा के बराबर नहीं है, जबकि अनुच्छेद 121 का उद्देश्य सार्वजनिक बहस को रोकना है। अध्यक्ष के लिए यह भी खुला हो सकता है कि वह किसी कानूनी मुद्दे पर सदन से परामर्श करे जिसका उत्तर प्रश्नगत न्यायाधीश के आचरण के संदर्भ के बिना दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, तत्काल मामले में शामिल मुद्दा, क्या पुराने सदन के विघटन के कारण प्रस्ताव समाप्त हो गया है और जांच समिति निष्क्रिय है। जो वर्जित है वह न्यायाधीश को हटाने से संबंधित हर मामला नहीं है; वर्जना अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश के आचरण के संबंध में चर्चा तक सीमित है। [95 ई-एच, 96 ए]

5.3 1968 के अधिनियम के ऐसे हिस्से की व्याख्या करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव को सदन में लंबित रहने का निर्देश दिया गया था या घोषित किया

गया था, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमित कानूनी कल्पना पैदा की गई थी कि आरती क्लै 121 के तहत प्रतिबंध को समय से पहले नहीं हटाया गया था।

[96 बी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. 2 एस सी आर।

22

ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड और फिन्सबरी बरो काउंसिल: 1952

ए. सी. 109, संदर्भित।

5.4 पूरे अधिनियम को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि

उसमें सदन को जब्त करने के लिए जानबूझकर चुना गया था

मामला, और इसके परिणामस्वरूप इसे शामिल करना आवश्यक हो गया प्रस्ताव को इस उद्देश्य के लिए लंबित रहने का निर्देश देने वाला प्रावधान

समय से पहले चर्चा को रोकना। इस प्रकार यह अधिनियम बहुत सफल रहा है।

अनुच्छेद 124 और 121 दोनों का उनकी वास्तविक भावना में पूरी तरह से सम्मान किया गया,

उन्हें साफ-सुथरे ढंग से सुसंगत बनाना। [97 बी]

5.5 संसद शुरू से ही इस मामले के नियंत्रण में है।

आरंभ करने के लिए किसी भी सदन के बड़ी संख्या में सदस्यों की आवश्यकता मामला, सदन के माध्यम से कार्यवाही के नियंत्रण में लाया जाता है

खंड (4) के तहत सदन में मतदान करने की बात, और यह एक शर्त नहीं है कार्यवाही शुरू करने और आगे के कदम उठाने के लिए पूर्ववर्ती

इस संबंध में। [97 जी-एच, 98 ए]

5.6 यह एक बड़े निकाय को सौंपने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है।

स्पष्ट व्यावहारिक कारणों से एक छोटे निकाय की जांच, और

इस तरह के अभ्यास को त्याग में लिप्त होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।प्राधिकार से। यह एक संसदीय समिति से पूछ सकता था कि

आरोपों की जांच करें या इसके लिए किसी अन्य तंत्र का उपयोग करें

उद्देश्य। [98 डी]

5.7 जब तक कानून सदन को अपना रखरखाव करने में सक्षम बनाता है

प्रत्यक्ष रूप से या अध्यक्ष के माध्यम से नियंत्रण, जांच को सौंपना शक्ति के त्याग के बराबर नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें संसद ने न्यायाधीश के पक्ष में समिति के आदेश का सम्मान करने का निर्णय लिया है, जो खंड के अनुरूप है।

(4) और कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। [99 बी]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। बटुक देव पति त्रिपाठी और अन्र। , [1978] 2 एस. सी. सी. 102, संदर्भित।

5.8 सदन, जो कार्यवाही के नियंत्रण में है, हकदार है।

मामले में सभी आवश्यक और प्रासंगिक कदम उठाने के लिए, न्यायाधीश के आचरण को तब तक रोकने के अलावा जब तक कि चरण तक नहीं पहुंच जाता है और अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटा दिया जाता है। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि समिति एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है जो हाउस सब के नियंत्रण के अधीन नहीं है-न्यायिक उत्तरदायित्व पर समिति v.

यू. ओ. आई. 23

प्रत्यक्ष रूप से या अध्यक्ष के माध्यम से, तब अधिनियम को व्यवहार्य नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह 5 या 4 न्यायाधीशों से युक्त एक तंत्र प्रदान करके भारत के मुख्य न्यायाधीश की गरिमा को कम करेगा।

आरआर

उसके खिलाफ अपील करने के लिए बैठें। यदि समिति को सदन में लंबित कार्यवाही के उद्देश्य के लिए सहायता करने की दृष्टि से संसद की देखरेख और नियंत्रण में कार्य करते हुए माना जाता है, तो यह संसद होगी जो कार्यवाही के नियंत्रण में होगी, न कि

समिति। [99 ई-एफ, एच]6.1 जब न्यायाधीश के खिलाफ निर्णय के बाद भी समिति, संसद या उस मामले के लिए दोनों में से किसी एक द्वारा वापस किया जाता है।

सदन किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने से इनकार कर सकते हैं, और न्यायालय के पास सी मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि जांच के मध्यवर्ती चरण में न्यायालय को हस्तक्षेप करने की शक्ति मिली है। यह हो रहा है

कारण, यदि सदन का नियंत्रण कार्यवाही पर जारी रहता है, जिसका प्रयोग अध्यक्ष के माध्यम से किया जा सकता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि न्यायालय के पास एक समानांतर अधिकार क्षेत्र है, जिसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा, न्यायालय को सहायता में कदम की प्रकृति में आदेश पारित करने के लिए अनुबंधित नहीं किया जा सकता है, जहां अंतिम परिणाम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश या निर्देश पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप केवल व्यर्थता हो सकती है, और देश के सर्वोच्च न्यायिक और विधायी अधिकारियों दोनों के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो सकती है। संविधान को इस तरह के इरादे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। [101 ए-सी]

6.2 इन परिस्थितियों में इस न्यायालय सहित न्यायालयों के पास उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही के संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। [101 सी] 7. इस विवाद पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है कि पहले के सदन को भंग करने पर एफ प्रस्ताव समाप्त हो गया या नहीं, क्योंकि इस मुद्दे का फैसला लोकसभा को करना है। [102 ई]

8. यह न्यायालय इस प्रार्थना पर कोई स्थायी या अस्थायी आदेश पारित नहीं कर सकता है कि प्रतिवादी संख्या 3, संबंधित न्यायाधीश को अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। [102 एफ]

कार्यपालिका और न्यायपालिका, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सख्ती से पालन नहीं किया गया है और कुछ ओवरलैपिंग है धूसर क्षेत्रों में शक्तियाँ।

[80 एफ-जी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. 2 एस सी आर।

24

श्रीमती. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, [1976] 2 एस. सी. आर. 347 पी. 415 , संदर्भित किया गया।

9.2 आम तौर पर, विवादों के निर्णय से जुड़े प्रश्न हैं -

न्यायालयों की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी, लेकिन अपवाद हैं, न केवल वे जो व्यक्त शब्दों में संविधान के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा कवर किए गए हैं, बल्कि अन्य जो संवैधानिक योजना में शामिल स्थापित न्यायशास्त्र के सिद्धांतों से उत्पन्न आवश्यक प्रेरणा द्वारा प्रतिरक्षा का आनंद ले रहे हैं। [81 सी]

10. उसके पूरे मामले को ध्यान में रखने की अनुमति है।

व्याख्या में सहायता के रूप में संविधान और अधिनियम के प्रावधानों की वास्तविक पृष्ठभूमि। [84 सी]

बंगाल इम्युनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 603 632 और 633; बी. प्रभाकर राव बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य,

[1985] पूरक 2 एस. सी. आर. 573, संदर्भित।

हेडन का मामला: 76 ई. आर. 637; ईस्टमैन फोटोग्राफिक सामग्री

कंपनी वी। पेटेंट के नियंत्रक, एल. आर. [1898] ए. सी. 571, का उल्लेख किया गया है।

मौलिक न्यायनिर्णय: 1991 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 491। (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

1991 का हस्तांतरण याचिका (नागरिक) सं. 278।(भारत के संविधान के अनुच्छेद 139-ए (आई) के तहत)

के साथ

लिखित याचिका (नागरिक) सं। 541 , 542 & 560/91

जी. रामास्वामी, महान्यायवादी, अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त महान्यायवादी। महान्यायवादी, शांति भूषण, राम जेठमलानी, पी. पी. राव, कपिल सिब्बल,

P.R.Krishnan, सुश्री इंदिरा जयसिंह, अशोक देसाई, हरदेव सिंह, पी. एस. पोती, डेनियल लतीफी, राजिंदर सच्चर, एम. के. राममूर्ति, आर. के. गर्ग, एस. के. ढोलकिया, संतोष हेगड़े, वी. एन. गणपुले, तपस रे, एन. बी. शेटी, जयंत भूषण, मोहन राव, प्रशांत भूषण, सुश्री कामिनी जैसवाल, ए. के. श्रीवास्तव, मनोज वाड, सुश्री रश्मि कठपालिया, सुश्री नीना दीक्षित, ई. एम. एस. अनम, राजीव के. गर्ग, एन. डी. गर्ग, जी. डी. शर्मा, सुधीर वालिया, ए. एम.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. सी. रे, जे. ये रिट याचिकाएं कुछ संवैधानिक हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 121 और 124 के निर्माण और न्यायाधीशों की उप-समिति-जे. यू. डी. एल. के निर्माण पर काफी कुछ महत्व के मुकदमे।

उत्तरदायित्व "। यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 25

(जाँच) अधिनियम, 1968 "यद्यपि जिस संदर्भ में उन्हें लाया गया है, वे कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

9वीं लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, जिसका कार्यकाल इसके भंग होने पर समाप्त हो गया था।

इस न्यायालय के श्री न्यायमूर्ति को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करना। 12 मार्च, 1991 को प्रस्ताव को लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिन्होंने इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत, बोम बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति पी. डी. देसाई और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित न्यायविद श्री न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी की एक समिति का गठन किया।

इन कार्यवाहियों में इस तरह के विवाद के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष के निर्णय की सहायता के लिए कार्य करने से इनकार करना और यह अधिसूचित करने से इनकार करना अवसर है कि समिति में दो वर्तमान न्यायाधीशों की सेवाओं को संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी के पैरा 11 (बी) (i) के अर्थ के भीतर "वास्तविक सेवा" के रूप में माना जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की अधिसूचना के बिना दो मौजूदा न्यायाधीश समय नहीं ले सकते हैं। उनके दरबार से-काम। केंद्र सरकार अपनी इस समझ पर अपने रुख को सही ठहराना चाहती है कि संबंधित न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा दिया गया प्रस्ताव और साथ ही 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक समिति का गठन करने का निर्णय, दोनों ही प्रस्ताव 9वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गए हैं।

इसलिए, कुछ महत्व के संवैधानिक मुद्दे संवैधानिक और कानूनी स्थिति और प्रस्ताव की स्थिति के रूप में उत्पन्न होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के अनुसरण में बनाए गए कानून के तहत किसी न्यायाधीश का प्रस्ताव और क्या लोकसभा के विघटन पर ऐसे प्रस्ताव पर चूक का सिद्धांत लागू होगा और क्या इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उच्च संवैधानिक पदों के धारकों को हटाने, महाभियोग आदि के लिए ऐसे प्रस्ताव राजनीतिक रूप से अपने स्वभाव में हैं।

संसद के दोनों सदनों में किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित मामले कानून की अदालतों के समक्ष न्यायसंगत हैं। यह भी आग्रह किया जाता है कि भले ही इन मुद्दों में कुछ हद तक न्यायिक स्वभाव हो और इसमें कुछ न्यायोचित क्षेत्र शामिल हों, न्यायालय को अपने निर्णय के रूप में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर देना चाहिए और इसकी रिट इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निष्फल हो सकती है कि अंतिम विश्लेषण में, अंतिम मध्यस्थ को कोई भी पता प्रस्तुत किया जाना है या नहीं, यह विशेष रूप से संसद के सदनों के पास है और जो पूरी तरह से न्यायालयों के दायरे से बाहर हैं।

2. पूर्वगामी मोटे तौर पर उन संवैधानिक मुद्दों की जटिलताओं को इंगित करता है जिन पर न्यायालय को निर्णय देने के लिए आमंत्रित किया जाता है और सभी संवैधानिक मुकदमों की तरह, विचार अनिवार्य रूप से संवैधानिक निर्णयों में नीतिगत विकल्पों की एक श्रृंखला को दर्शाते हैं और कुछ हद तक, निर्णयों को महत्व देते हैं।

3. 1991 की रिट याचिका संख्या 491 "न्यायिक जवाबदेही पर उप समिति" नामक एक निकाय द्वारा है जिसका प्रतिनिधित्व इसके संयोजक, श्री हरदेव सिंह, इस न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता निकाय एक उप-समिति होने का दावा करता है जिसका गठन "न्यायिक जवाबदेही पर अखिल भारतीय सम्मेलन" द्वारा "सम्मेलनों के संकल्पों को लागू करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए" किया गया है। 1991 की रिट याचिका संख्या 541 सु प्रीमे कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा है जिसका प्रतिनिधित्व इसके मानद सचिव द्वारा किया जाता है। बार एसोसिएशन इस याचिका पर "व्यापक सार्वजनिक हित में और विशेष रूप से वादी जनता के हित में" मुकदमा चलाना चाहता है। दोनों याचिकाओं के लिए समान दो प्रार्थनाएँ हैं, पहला, कि भारत संघ को "न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968" के तहत जांच समिति को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाए और दूसरा, कि समिति के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विद्वान न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों को करने और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने से रोका जाना चाहिए।

4. रिट याचिका संख्या 542 हरीश उप्पल नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है। यह लिखावट

याचिका डब्ल्यू. पी. सं. 541/1991 और डब्ल्यू. पी. सं. 491/1991 में दूसरी प्रार्थना के काउंटर की प्रकृति में अधिक है। याचिकाकर्ता, श्री हरीश उप्पल का कहना है कि जब तक जांच समिति वास्तव में विद्वान न्यायाधीश को आरोपों के लिए दोषी नहीं पाती है, तब तक उनके न्यायिक कार्यों में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और यदि ऐसा निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो उसके बाद जब तक संसद के सदनों द्वारा निपटाये गए न्यायाधीश को हटाने के लिए अभिभाषण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं की जानी चाहिए, राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों से अलग होने के लिए कह सकते हैं।अधिवक्ता श्याम रतन खंडेलवाल द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 560/1991 में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 100,105,118,121 और 124 (5) से परे है। इसमें यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 9वीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया है। यह इस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार करने के अध्यक्ष के निर्णय को रद्द करने का भी अनुरोध करता है कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने और एक समिति का गठन करने के लिए आगे बढ़ने से पहले न्यायाधीश को सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया था। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की वैधता के सवाल पर, सब-जे. यू. डी. एल. पर समिति।

1968 , याचिकाकर्ता का तर्क है कि ठीक से अर्थ लगाया गया कानून सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में अध्यक्ष में एक प्रस्ताव को स्वीकार करने और धारा 3 के तहत एक समिति के गठन की शक्तियों को निहित करता है और संसद के सदनों के कानून, प्रक्रिया और सम्मेलनों के प्रसिद्ध और अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अधीन है और क़ानून इन सिद्धांतों से अलग नहीं है। इसके विपरीत, कानून एक ऐसे निर्माण को स्वीकार करता है जो सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों के अनुरूप है और प्रवेश के उस स्तर पर भी प्रस्ताव पर सदन द्वारा बहस की आवश्यकता होगी। यह आग्रह किया जाता है कि यदि वह निर्माण है, जिसे क़ानून की भाषा स्वीकार करती है, तो इसका कोई दोष नहीं होना चाहिए। इसमें असंवैधानिकता। लेकिन यदि कानून का यह अर्थ लगाया जाता है कि वह विशेष रूप से अध्यक्ष को ऐसी शक्ति प्रदान करता है, तो ऐसे संविधान पर कानून, संविधान के अनुच्छेद 100 (1), 105,118 और 121 का उल्लंघन करने के रूप में असंवैधानिक होगा।

4. स्थानांतरण याचिका सं. 268/1991 इस न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय से खुद को वापस लेने के लिए है, दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं. 1061/1991 जहां श्री खंडेलवाल द्वारा WP (सिविल) सं. 560/1991 में अनुरोध किए गए राहतों के समान राहत मांगी गई है। स्थानांतरण के लिए अनुरोध अभी तक मंजूर नहीं किया गया है; केवल उच्च न्यायालय में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इन सभी मामलों में पूरी तरह से बहस सुनी गई है। यह उचित है कि इस रिट याचिका को भी औपचारिक रूप से वापस लिया जाए और अंत में मामलों के वर्तमान समूह के साथ निपटाया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय से डब्ल्यू. पी. (सिविल) संख्या 1061/1991 को वापस लेने का एक औपचारिक आदेश देना आवश्यक है, जो हम एतद्द्वारा करते हैं।

5. न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और अनियमितताओं के कुछ आरोप तब लगाए गए थे जब वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ग. खरीद और अन्य व्यय की कुछ वस्तुओं के संबंध में कुछ लेखापरीक्षा रिपोर्टें थीं। थर। भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी ने इस ओर से दी गई रिपोर्टों और इस ओर से उन्हें प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया और न्यायमूर्ति रामास्वामी को सलाह दी कि जब तक उन आरोपों को दूर नहीं किया जाता, तब तक वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने से दूर रहें। इसके बाद, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले को देखने और उन्हें सलाह देने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया था कि क्या तथ्यों पर न्यायमूर्ति रामास्वामी इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने में शर्मिंदा हो सकते हैं। समिति ने मुख्य न्यायाधीश को अपनी सलाह दी। इसने नोट किया कि न्यायमूर्ति रामास्वामी ने अपने आचरण पर निर्णय में बैठने के लिए किसी भी समिति के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तदनुसार, समिति ने आरोपों की जांच से परहेज किया, लेकिन उसके समक्ष मामले के मूल्यांकन पर, यह विचार व्यक्त किया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. पी. के आरोप हैं।

2 एस सी आर।

विभिन्न जांचों में नैतिक अधमता से जुड़े अनुचित आचरण को स्थापित नहीं किया गया था, तब उन्हें न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के संवैधानिक वारंट के संचालन तक रोक नहीं लगाया जा सका था।

इसके बाद, फरवरी 1991 में, लोकसभा के 108 सदस्यों ने 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा।

राष्ट्रपति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत विद्वान न्यायाधीश को हटाने के लिए कहा। आई. डी. 1 पर लोकसभा अध्यक्ष ने उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का कथित प्रयोग करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन आधारों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिनके आधार पर हटाने का अनुरोध किया गया था।

प्रस्ताव को स्वीकार करने और आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने के अध्यक्ष के निर्णय के तुरंत बाद, नौवीं लोकसभा का कार्यकाल इसके भंग होने पर समय से पहले समाप्त हो गया। याचिकाकर्ता अध्यक्ष के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हैं और दावा करते हैं कि सभी मामलों में, प्रस्ताव सदन के भंग होने के साथ समाप्त हो गया था। इस तर्क का भारत संघ द्वारा समर्थन किया जाता है। उनका कहना है कि नौवीं लोकसभा के विघटन का प्रभाव "पार्लिया मेंटरी स्लेट के पार एक स्पंज पारित करना" है और सभी लंबित प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं। हटाने का प्रस्ताव, यह आग्रह किया जाता है, कोई अपवाद नहीं है।

6. हमने श्री शांति भूषण, श्री राम जेठमलानी, श्री पी. पी. राव, श्री आर. के. गर्ग और सुश्री इंदिरा जयसिंह-विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को रिट याचिका संख्या में प्रार्थनाओं के समर्थन में सुना है। 491 और 1991 का 541 क्रमशः न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति और सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया; श्री जी. रामास्वामी, भारत संघ के विद्वान महान्यायवादी; श्री कपिल सिब्बल रिट याचिका संख्या 560/91 और स्थानांतरण याचिका संख्या 278/91 में याचिकाकर्ताओं की ओर से। श्री हरीश उप्पल, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से रिट याचिका संख्या 542/91 में अपनी लिखित दलीलें दायर की हैं।

मामले के तर्कों में भारत में उच्च न्यायपालिका के सदस्यों को हटाने और उनसे उत्पन्न होने वाले विवादों की न्यायसंगतता की समस्याओं से संबंधित एक व्यापक संवैधानिक योजना शामिल थी। जब हम इन तर्कों के गुण-दोष का आकलन करेंगे तो हम तर्कों का उल्लेख करेंगे।7. उन याचिकाओं के समर्थन में सुनवाई में आग्रह की गई दलीलें जो अध्यक्ष के फैसले को लागू करने की मांग करती हैं और साथ ही जिन याचिकाओं में आग्रह किया गया है

उन याचिकाओं के समर्थन का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है जिनमें कहा गया है कि प्रस्ताव समाप्त हो गया है:

एम. एम. आई. टी. ई. जे. यू. डी. एल. पर। लेखा योग्यता v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 29

एन ए:

घर को। यह प्रश्न कि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव समाप्त हो गया है या नहीं, उस सदन के कामकाज के संचालन से संबंधित मामला है जिसमें सदन एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश है। अदालत के समक्ष मामले का कोई भी पहलू न्यायोचित नहीं है।

एन बी:

न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया, अपने मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं में, संसद के सदनों के अनन्य क्षेत्र के भीतर एक राजनीतिक प्रक्रिया है। सदन की प्रक्रिया और कार्य को विनियमित करने में अध्यक्ष की भूमिका किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगी। लोकसभा अध्यक्ष न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में कार्य करता है। न्यायाधीश (पूछताछ में) अधिनियम, 1968 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चूक के इस सिद्धांत से अलग हो। इसके विपरीत, 'अधिनियम' के प्रावधान इसके अनुरूप हैं -यह संवैधानिक स्थिति।

एन सी:

अनुच्छेद 124 (5) जिसके अनुसार न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 केवल एक सक्षम करने वाला प्रावधान है। न्यायाधीश के आचरण की चर्चा के खिलाफ अनुच्छेद 121 के तहत बार के समक्ष गलत नलिका का पूर्व प्रमाण एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं है।

एन डी:

सदन को संदर्भित किए बिना प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार करने और [1991] एस. यू. पी. पी. के निर्णय के समर्थन के बिना जांच के लिए एक समिति का गठन करने में अध्यक्ष की कार्रवाई।

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30

सदन अधिकार से बाहर है अनुच्छेद 100 (1), 105,121 और नियम संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाया गया।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधानों को पढ़ा जा सकता है।

पूर्ववर्ती के अधीन संवैधानिक योजना के अनुरूप

लेखों ने कहा। लेकिन अगर अधिनियम के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाता है

अध्यक्ष को उन शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए

और संदर्भ के बिना और स्वतंत्र रूप से कार्य

सदन, तब अधिनियम के प्रावधान असंवैधानिक होंगे

राष्ट्रीय।

विषय-वस्तु ई:

प्रस्ताव को स्वीकार करने और जांच के लिए एक समिति बनाने का अध्यक्ष का निर्णय अनुपालन में विफलता के लिए अमान्य है।

आई।

स्वाभाविक न्याय के नियमों के साथ, यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायाधीश को निर्णय से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था ले जाया गया।

सामग्री एफ:

राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए प्रस्ताव के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया एक राजनीतिक उपाय है। लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का मौलिक अधिकार अपने दायरे में उत्कृष्ट और बेदाग प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा के न्यायाधीशों से युक्त अदालत में जाने का अधिकार लेता है जो लागू करने योग्य है। यह न्यायिक उपचार संवैधानिक उपचार के विचाराधीन है और न्यायालय के पास अपने उचित संविधान के बारे में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। इस अधिकारिता के संदर्भ में इसे कथित दुर्व्यवहार के आधारों की जांच करनी चाहिए और न्यायाधीश को न्यायिक कार्य से रोकना चाहिए।

ट्युनिंग।

सामग्री जी:

अध्यक्ष के निर्णय को दुर्भावनापूर्ण और अप्रत्यक्ष और संपार्श्विक उद्देश्यों से दूषित किया जाता है।

सामग्री एच;

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति-क्रमशः 1991 की रिट याचिका संख्या 491 और 1991 की रिट याचिका संख्या 541 में याचिकाकर्ताओं के पास मुकदमा करने के लिए आवश्यक स्थिति नहीं है और तदनुसार, रिट याचिकाएं उनके कहने पर बनाए रखने योग्य नहीं हैं।

सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 31

आशय I:

सभी स्थितियों में, भले ही अध्यक्ष को क़ानून के तहत कार्य करने वाला एक सांविधिक प्राधिकरण माना जाता है और वह लोकसभा के पक्ष या कार्य के हिस्से के रूप में नहीं है और न्यायालय की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी है, इस न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय और रिट पर मुकदमा चलाया जाता है, इस निर्विवाद संवैधानिक स्थिति को देखते हुए निष्फल होने की संभावना है कि, अल्टीमेट विश्लेषण में, प्रस्ताव को अपनाने या अस्वीकार करने का निर्णय विशेष रूप से सदन की शक्ति के भीतर है और न्यायालय को उस क्षेत्र पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

अत: न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर देगा। निष्फलता के आधार।

8. तर्कों के गुण-दोष पर चर्चा करने से पहले यह आवश्यक है कि -

न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अवलोकन करें।और उसकी स्वतंत्रता। इसमें संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए

न्यायालय को एक ऐसे निर्माण को अपनाना चाहिए जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं और मूल संरचना को मजबूत करता हो। कानून का शासन संविधान की एक बुनियादी विशेषता है जो पूरे संविधान में व्याप्त है।

राष्ट्रीय संरचना और यह संवैधानिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। इंडीन्यायपालिका का विचाराधीन होना कानून के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है। अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में,

मुख्य न्यायाधीशों के साथ सुलह। ये प्रावधान भी स्थिरता सुनिश्चित करते हैं -

न्यायाधीश के पद का कार्यकाल। संविधान वेतन की रक्षा करता हैन्यायाधीश। अनुच्छेद 121 में प्रावधान है कि पार्लिया में कोई चर्चा नहीं होगी।

अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में, इसके लिए एक प्रस्ताव को छोड़कर

राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उन्हें हटाने की प्रार्थना की

न्यायाधीश जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 124 (4) और 124 (5) कार्यकाल के समय से पहले निर्धारण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 124 (4) में कहा गया है कि "उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जाएगा सिवाय इसके कि"

आदि। हटाने के लिए आधार फिर से साबित दुर्व्यवहार तक सीमित हैं।

और अक्षमता। यह एक उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर है और इन प्रावधानों का स्पष्टीकरण कि इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे हैं

हल करने के लिए।

9. संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ लगाने में कानून और प्रक्रिया

अन्य देशों में न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार एक पृष्ठभूमि और एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। समाधान, निश्चित रूप से, हमारी अपनी संवैधानिक योजना के भीतर पाया जाना चाहिए। लेकिन एक तुलनात्मक विचार एक उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

संवैधानिक योजना की समझ और व्याख्या के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. 2 एस सी आर।

32

10. इंग्लैंड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को केवल हटाया जा सकता है।

1

संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संबोधन प्रस्तुत करने पर

मुकुट। किसी भी सदन में याचिका दायर करके कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

क्राउन को संबोधित करने के लिए संसद या क्राउन को संबोधित करने के लिए एक प्रस्ताव द्वारा नामित व्यक्ति के आचरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए, हालांकि अधिमानतः उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में शुरू किया जाना चाहिए। कभी-कभी [जैसा कि बैरिंगटन मामले (1830) में], जांच का एक आयोग नियुक्त किया जाता है और मामले पर उक्त आयोग की रिपोर्ट के आलोक में विचार किया जाता है। हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है

पूरे घर में। यदि कोई जांच की जानी है तो आरोप, इसे या तो सदन की प्रवर समिति को भेजा जाता है या

पूरे सदन की समिति। न्यायाधीश को अवसर दिया जाता है

जिनका आचरण सार्वजनिक जाँच पर बचाव करने के लिए आक्षेपित है।

समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को सदन के समक्ष रखा जाता है जहां इस मामले पर बहस होती है। (देखिए: हैल्सबरी के नियम

इंग्लैंड, चौथा संस्करण। खण्ड. पी। 1108) .

11. इस प्रक्रिया की निम्नलिखित आलोचना की गई है -

(i) विधायी निष्कासन राजनीतिक पक्षपात द्वारा रंगीन होता है क्योंकि प्रक्रिया की शुरुआत के साथ-साथ अंतिम परिणाम राजनीतिक विचारों और तथ्य की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है-खोज और विचार-विमर्श भी पार्टी की भावना से पीड़ित होते हैं।

((ii) सरकार का न केवल कार्यवाही के अंतिम परिणाम पर बल्कि संसदीय समय पर भी काफी नियंत्रण है।

उन्हें एक पते के लिए प्रस्तावों को अपनाने से रोकने में सक्षम बनाता है

अगर यह उन्हें सूट करता है।

((iii) न्यायिक तथ्य के लिए विधायी प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है।

ढूँढना; और

((iv) चूँकि संसद अपनी स्वयं की प्रक्रिया की स्वामी है, इसलिए न्यायिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएं और साक्षय के नियम जो न्यायिक निष्कासन के मामले में आवश्यक प्रतीत होते हैं, उन्हें संसद में अनुमति दिए जाने की संभावना नहीं है। (देखिए: शेट्रीट-न्यायाधीश

ऑन ट्रायल (1976) पी। 405-407)

12. न्यायपालिका पर न्याय उप-समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या सदनों को संबोधित करके हटाने की मौजूदा प्रक्रिया है।

इसे बदलती जरूरतों और स्थितियों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक नए तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित या पूरक किया जाना चाहिए। उप-समिति, अपने 1972 में। रिपोर्ट में उक्त प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया गया और न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक नई प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया गया है। उप-समिति ने एक तदर्थ न्यायिक आयोग की स्थापना को लागू करने की सिफारिश की है।

लॉर्ड चांसलर द्वारा इंगित किया गया है, यदि वह निर्णय लेता है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रश्न की जांच की जानी है। आयोग में उच्च न्यायिक पद धारण करने वाले या रखने वाले व्यक्तियों की एक प्रमुख समिति और किसी भी स्थिति में कम से कम तीन को शामिल किया जाना चाहिए। संसद के सदस्य या ऐसे व्यक्ति जो कोई राजनीतिक नियुक्ति रखते हैं या रखते हैं, उन्हें बाहर रखा जाएगा। अपनी जांच पूरी करने के बाद तदर्थ आयोग तथ्यों की रिपोर्ट करेगा और सिफारिश करेगा कि क्या किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रश्न प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को भेजा जाना चाहिए। यदि आयोग ऐसी सिफारिश करता है सुधार होने पर, प्रिवी काउंसिल इस मामले पर विचार करेगी और यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता

है कि न्यायाधीश को हटा दिया जाना चाहिए, तो वह महामहिम को सलाह देगी। [देखू: शेट्रीट 'जज ऑन ट्रायल', (1976); पीपी। 404-405] .

डॉ. शेट्रीट ने एक माध्यम-मीडिया का सुझाव दिया है और संस्था का समर्थन किया है

उप-समिति द्वारा सुझाए गए तर्ज पर हटाने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति (लेकिन हटाने से कम अनुशासन के लिए नहीं), लेकिन यह विचार व्यक्त किया है कि संबोधित करने की मौजूदा प्रक्रिया भी होनी चाहिए

संरक्षित किया गया। [देखिए: शेट्रीट 'जज ऑन ट्रायल', (1976); पी। 409] . मार्गरेट ब्रेज़ियर ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है। (देखिए: रॉडनी ब्रेज़ियर 'संविधान राष्ट्रीय पाठ (1990) पीपी। 606-607

13. कनाडा में, 1867 के संविधान अधिनियम की धारा 99 (1) के तहत,

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अच्छे व्यवहार के दौरान पद धारण करते हैं, और सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स के संबोधन पर गवर्नर-जनरल द्वारा हटाए जा सकते हैं। 1868 और 1874 में हटाए जाने की याचिका पर मामला सदन की प्रवर समिति को भेजा गया था। 1874 में एक तीसरे मामले में प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई किए जाने से पहले ही न्यायाधीश की मृत्यु हो गई। हाल ही में 1966-67 में, ओंटारियो के सर्वोच्च न्यायालय के श्री न्यायमूर्ति लियो लैंड्रेविल को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था और उस संबंध में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति इवान सी. रैंड से मिलकर एक शाही आयोग को जांच अधिनियम आर. एस. सी. 1952 सी. 154 के तहत नियुक्त किया गया था। पूछताछ की। उक्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सदनों की एक संयुक्त समिति ने हटाने की सिफारिश की लेकिन न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया जब संसद संयुक्त संबोधन द्वारा उन्हें हटाने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद, न्यायाधीश अधिनियम 1971 में अधिनियमित किया गया था जिसके तहत कनाडाई न्यायिक परिषद

बनाया गया है। एस में उल्लिखित परिषद के कार्य। 39 (2) पूछताछ करना और शिकायतों या शिकायतों की जांच करना शामिल है।

एस में वर्णित गैशन। 40. धारा 40 में प्रावधान है कि परिषद यह निर्धारित करने के लिए एक जांच कर सकती है कि क्या कोई वरिष्ठ, जिला या जिला का न्यायाधीश है।

काउंटी अदालत को पद से हटा दिया जाना चाहिए और यह कनाडा के न्याय मंत्री को सिफारिश कर सकता है कि एक न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाना चाहिए। जिन आधारों पर ऐसी सिफारिश की जा सकती है, वे निम्नलिखित हैं -

एस। 41 (2) अधिनियम और वे हैं: (क) आयु या दुर्बलता, (ख) [1991] एस. यू. पी. पी. होने पर।

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34

दुराचार का दोषी, (ग) अपने पद के उचित निष्पादन में विफल रहा हो, या (घ) अपने आचरण से या अन्यथा, अपने पद के उचित निष्पादन के साथ असंगत स्थिति में रखा गया हो। (गॉल 'द कैनेडियन कानूनी प्रणाली '(1983); पीपी। 184-186) .

1982 में श्री न्यायमूर्ति थॉमस बर्जर का मामला, एक न्यायाधीश

ब्रिटिश कोलंबिया के सर्वोच्च न्यायालय की जांच कनाडाई न्यायिक परिषद द्वारा की गई थी, जो न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से प्रेरित थी। परिषद ने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति में

न्यायमूर्ति बर्जर द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति एक "अविवेक" थी, लेकिन यह कि वे इस सिफारिश का आधार नहीं थे कि उन्हें पद से हटा दिया जाए और उक्त सिफारिश के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, हालांकि न्यायमूर्ति बर्जर ने न्यायाधीश के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया।कुछ महीने बाद। (देखिए: गाल: कनाडाई कानूनी प्रणाली, (1983) पी। 189) .

14. राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया संविधान की धारा 72 (ii) के तहत

शिक्षा अधिनियम, 1900, उच्च न्यायालय और संसद द्वारा बनाए गए अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों को गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल द्वारा एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों से एक संबोधन पर इस तरह के निष्कासन के लिए प्रार्थना करने के अलावा नहीं हटाया जा सकता है।

दुर्व्यवहार या अक्षमता। राज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में राज्यों के संविधानों में भी इसी तरह के प्रावधान हैं।

श्री न्यायमूर्ति मर्फी को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई

1984 में ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय ऑस्ट्रेलिया संविधान अधिनियम की सामान्य संपत्ति की धारा 72 (ii) के तहत। उन कार्यवाही के संबंध में सबसे पहले सीनेट की एक चयन समिति को मामले की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें तीन राजनीतिक दलों के छह सीनेटर शामिल थे। समिति ने बहुमत के निर्णय (3:2, एक पक्षीय) द्वारा धारा 72 (ii) के तहत दुर्व्यवहार के बराबर कोई आचरण नहीं पाया। विभाजित मत को देखते हुए उन्हीं तीन राजनीतिक दलों के चार सीनेटरों की एक दूसरी समिति की स्थापना की गई और इसे दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा सहायता प्रदान की गई-एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय से और दूसरा ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय से और उक्त समिति ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया लेकिन न्यायाधीश किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। न्यायाधीश पर न्यू साउथ वेल्स के केंद्रीय आपराधिक न्यायालय के समक्ष भी मुकदमा चलाया गया था और उन्हें न्याय के पाठ्यक्रम को विकृत करने के प्रयास का दोषी पाया गया था, लेकिन

उक्त फैसले को आपराधिक अपील न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। नए सिरे से मुकदमा चलाया गया जिसके तहत न्यायाधीश को दोषी नहीं पाया गया। इसके बाद, एक तदर्थ कानून, अर्थात् संसदीय जांच मिशन अधिनियम, 1986 को राष्ट्रमंडल संसद और एक आयोग द्वारा अधिनियमित किया गया था जिसमें क्रमशः विक्टोरिया के सर्वोच्च न्यायालय, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल थे।

सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.]

और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले कि उक्त आयोग अपनी रिपोर्ट दे पाता, न्यायाधीश गंभीर रूप से बीमार हो गए और अधिनियम को निरस्त कर दिया गया [ऑस्ट्रेलियाई संविधान पर लेन की टिप्पणी, (1986) पी। 373] .

15. एक अन्य मामले में, उनके खिलाफ हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी

क्वींसलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के श्री न्यायमूर्ति वस्ता और उस उद्देश्य के लिए क्वीन्सलैंड विधानमंडल ने संसदीय (न्यायाधीश) जांच मिशन अधिनियम, 1988 को अधिनियमित किया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय, विक्टोरिया के सर्वोच्च न्यायालय और न्यू साउथ वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय के क्रमशः तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से मिलकर एक आयोग का गठन किया गया।

16. ऑस्ट्रेलिया में, मौजूदा प्रक्रिया की आलोचना हुई है

न्यायाधीशों को न्यायाधीशों और वकीलों दोनों द्वारा हटाने के संबंध में। श्री न्यायमूर्ति एल. जे. किंग, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है:

" दोनों सदनों के पते से हटाने की अवधारणा संसद अपने आप में काफी आलोचना का विषय है।

दिलचस्प बात यह है कि आम आलोचनाएँ जो की जाती हैं, वे विरोधाभासी होती हैं

टोरी। एक आलोचना यह है कि इसमें शामिल होने की आवश्यकता

विधायिका यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाएगा और

कि इसलिए न्यायाधीशों को एक व्यावहारिक प्रतिरक्षा है

मूवल। इस माध्यम से हटाना निश्चित रूप से बेहद दुर्लभ है।

हालाँकि, यह हो सकता है क्योंकि जिन देशों में यह

प्रक्रिया प्रचलित है, शर्तें ऐसी हैं कि एक न्यायाधीश जो आता हैन्यायिक कदाचार का एक गंभीर कार्य निश्चित रूप से होगा

साइन करें। उस विचार के साथ, इस तथ्य के साथ कि मानकउन देशों में न्यायिक आचरण आम तौर पर बहुत अधिक है,

विधायिका द्वारा हटाने को एक दुर्लभता बनाता है। इसके विपरीत आलोचना

हालांकि, यह है कि इसके लिए कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है

•

एक न्यायाधीश का मुकदमा, जिसे विधायिका द्वारा हटाने की मांग की जाती है। यह है।

जांच जिस पर न्यायाधीश अपना बचाव करने में सक्षम होगाआरोपों के खिलाफ, लेकिन यह एक मामला होगा

प्रत्येक मामले में विधायिका। कुछ लोग हैं जो डरते हैं कि एक संसद मानसिक बहुमत, के बारे में उत्तेजित सार्वजनिक भावना से प्रोत्साहित

एक अलोकप्रिय न्यायिक निर्णय, किसी दिन हटाने के लिए कार्य कर सकता है

उचित प्रक्रिया के बिना एक न्यायाधीश।

यह कम से कम संदिग्ध है कि क्या संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा हटाने की प्रणाली एक न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. के अनुरूप है।

2 एस सी आर।

प्रतिभूति की डिग्री जो न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए आवश्यक है।

[' न्यायिक स्वतंत्रता के न्यूनतम मानक '1984 (58) एएलजे

340 , पी पर। 345]

इसी तरह, न्यू एच वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय के श्री न्यायमूर्ति एम. एच. मैकलेलैंड ने यह विचार व्यक्त किया है:

" पहले से चर्चा किए गए उपायों के बदले में, कुछ प्रति व्यक्ति, और अधिमानतः ऑस्ट्रेलिया-व्यापी, दुर्व्यवहार या अक्षमता के अस्तित्व के न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया स्थापित करने के उद्देश्य से कानून द्वारा तंत्र प्रदान किया जाना चाहिए जो एक न्यायाधीश को पद से हटाने की गारंटी दे सकता है। उस तंत्र की रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे न्यायिक स्वतंत्रता,

न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास और अदालतों के अधिकार को कम से कम नुकसान हो, जो इसके प्रभावी संचालन के अनुरूप हो। यह ऐसा भी होना चाहिए कि एक न्यायाधीश को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सार्वजनिक वसीयत या शर्मिंदगी से सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके।

(ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीशों को अनुशासित करना, (1890) 64 ए. एल. जे. 688 पी. 401)

न्यायमूर्ति श्री मैकलेलैंड ने यह भी सुझाव दिया है कि न्यायाधिकरण को पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की जानी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है:

" इसके अलावा, न्यायिक संरक्षण। कार्यकाल और स्वतंत्रता, जिसे निपटान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का इरादा था, ने बीच की अवधि में अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। 1701 में, क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स तीन शक्तिशाली लेकिन अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से लंबित संस्थाएं थीं। एक न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक था कि वह संसदीय संबोधन प्रक्रिया के तहत हटाए जाने के जोखिम में होने के लिए एक साथ तीनों की नाराजगी का सामना करे। पार्टी प्रणाली और कैबिनेट सरकार के बाद के विकास (विशेष रूप से सख्त पार्टी अनुशासन के आधुनिक विचारों के साथ) ने स्थिति को व्यापक रूप से बदल दिया है। आधुनिक समय में, कार्यकारी सरकार और निचला सदन (और अक्सर ऊपरी सदन, जहां एक होता है) प्रभावी रूप से एक व्यक्ति या एकजुट समूह के नियंत्रण में होते हैं, ताकि अब एक न्यायाधीश को संसदीय संबोधन प्रक्रिया के तहत हटाने का खतरा हो सकता है यदि जे. यू. डी. एल. पर एस. यू. बी.-समिति है।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 37

उसे केवल उस व्यक्ति या समूह की नाराजगी का सामना करना पड़ता था।

(ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीशों को अनुशासित करना, (1990) 64 ए. एल. जे. 388 पी. 402-3)

सर मौरिस बायर्स, राष्ट्रमंडल के पूर्व सॉलिसिटर जनरल

उन्होंने भी इसी तरह से बात की है:

" एक संघीय प्रणाली में उच्च न्यायालय और संसद और कार्यपालिका के बीच तनाव शामिल होता है। हाल के वर्षों में यह वृद्धि देखी गई है क्योंकि संविधान की व्याख्याएँ पार्टी का सिद्धांत बन गई हैं। न्यायालय के संवैधानिक निर्णयों को कई अनजान और कुछ गठित लोगों द्वारा दल के राजनीतिक प्रश्नों पर असर डालने के रूप में देखा जाता है। जब श्री न्यायमूर्ति मर्फी और बहुत कम हद तक सर गारफील्ड बारविक के मामले में, एक पूर्व राजनीतिक व्यक्ति, एक निर्णय देता है, तो वह संसद में कुछ लोगों के प्रति शत्रुता और अक्सर दुर्व्यवहार को आकर्षित करता है। संविधान की धारा 72 उन्हें अपने विरोधियों के हमले और अक्सर अपने पूर्व दोस्तों के संदिग्ध समर्थन से अवगत कराती है। क्या संसद स्वयं पद के लिए उनकी योग्यता के न्यायिक प्रश्न का निर्णय ले सकती है या "हमारी गलत धारणा या अक्षमता साबित"

कम से कम संदिग्ध है। लेकिन न्यायालय को इस खतरे का सामना नहीं करना चाहिए। न्यायाधीशों का एक आयोग, जिसकी सदस्यता बारी-बारी से आती है, बुलाया जाता है। (बार टेबल के दूसरी तरफ से: न्यायपालिका के बारे में अधिवक्ताओं का दृष्टिकोण, (1987) 10 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स लॉ जर्नल पी। 185) .

राष्ट्रमंडल संविधान में सुधारों का सुझाव देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था। उक्त आयोग नेसिफारिश की गई कि आयोग में संशोधन करके प्रावधान किया जाना चाहिए

राष्ट्रमंडल संविधान (ए) ऑस्ट्रेलिया में सभी न्यायाधीशों को धारा 72 द्वारा प्रदान किए गए कार्यकाल की सुरक्षा का विस्तार करना, और (बी) यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना करना कि क्या उस न्यायाधिकरण द्वारा पाए गए तथ्य दुर्व्यवहार या अक्षमता के बराबर हैं जो हटाने की गारंटी देते हैं।

कार्यालय से एक न्यायाधीश।

(मैकलेलैंड 'ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीशों को अनुशासित करना', (1990) 64 ए. एल. जे. 388,

पी। 403)

17. संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या संघीय न्यायाधीश को हटाना अमेरिकी संविधान के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

संविधान जिसमें अनुच्छेद II (4) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी सिविल अधिकारियों को देशद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य उच्च अपराधों के लिए महाभियोग और दोषी ठहराए जाने पर पद से हटाने का प्रावधान करता है।

2 एस सी आर।

38

और दुराचार। महाभियोग के लिए साधारण बहुमत से मतदान किया जा सकता है

प्रतिनिधि सभा के सदस्य, जिस पर एक गणपूर्ति होती है

इसके बाद सदन और मुकदमा सीनेट में आयोजित किया जाता है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों के वोट से दोषी ठहरा सकता है, जिसमें एक गणपूर्ति होती है। राज्य न्यायपालिका के संबंध में, हटाने की प्रक्रिया राज्य संविधान द्वारा शासित है। अधिकांश राज्य संघीय स्वरूप का पालन करते हैं और महाभियोग को हटाने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में प्रदान करते हैं।

नियुक्त न्यायाधीश। कुछ राज्यों में हटाने का प्रावधान किया गया है

राज्यपाल का विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करना या एक संयुक्त संकल्प द्वारा

विधायिका की। कुछ राज्यों में, हटाने की शक्ति राज्य के सर्वोच्च न्यायालयों में निहित है, जबकि कुछ राज्यों में, हटाने के आरोपों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें प्रदान की जाती हैं। न्यूयॉर्क राज्य में, न्यायालय को न्यायपालिका पर न्यायालय के रूप में जाना जाता है। (हेनरी जे. अब्राहम को देखिए: न्यायिक प्रक्रिया, तीसरी

एड। पी. 45)।

राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक प्रशासन के लिए न्यायिक व्यवस्था है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्मेलन जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्यारह क्रमांकित परिपथों में से प्रत्येक के मुख्य न्यायाधीशऔर कोलंबिया जिले और संघीय सर्किट के, लेकिन 1957 से, प्रत्येक सर्किट से एक जिला न्यायाधीश प्रतिनिधि के अपवाद के साथ

संघीय परिपथ, जिसमें एक परीक्षण-न्यायालय स्तर का अभाव है। 1932 में पारित कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा (यू. एस. कोड के शीर्षक 28 में शामिल) न्यायिक सम्मेलन को एक व्यापक सर्वेक्षण करने का कर्तव्य सौंपा गया है

न्यायालयों में कार्य की स्थिति; सर्किट या जिलों में या वहां से न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए योजना तैयार करना जहां आवश्यक हो; और विभिन्न न्यायालयों को सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करना ताकि एक संघ को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रबंधन प्रक्रियाओं की औपचारिकता और न्यायालय का त्वरित संचालन व्यवसाय। न्यायिक सम्मेलन का कार्य विशेष रूप से किया जाता है।

समितियाँ जिनमें न्यायिक नैतिकता पर विशेष समिति शामिल है। अ.

1939 में पारित कांग्रेस के अन्य अधिनियम में न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है।

सर्किट के सर्किट न्यायाधीशों से बनी प्रत्येक सर्किट के लिए परिषद जो प्रभावी और शीघ्रता के लिए सभी आवश्यक आदेश देने के लिए सशक्त है।

अपने परिपथ के भीतर न्यायालयों के व्यवसाय का प्रशासन। न्यायिक परिषदों का अधिदेश न्यायपालिका के कार्य को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करता है।

संस्थागत भावना (न्याय का प्रशासन), जैसे कि किसी न्यायाधीश या अदालतों से जुड़े अन्य व्यक्ति के कार्यों से अदालत प्रणाली के संबंध में सार्वजनिक सम्मान और विश्वास के नुकसान से बचना। न्यायिक परिषदों ने अदालत के कर्मियों, अधिकारियों और न्यायाधीशों की ओर से कदाचार के आरोपों की समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग किया है। न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, कांग्रेस ने न्यायिक परिषद सुधार और न्यायिक आचरण

और विकलांगता अधिनियम 1980 लागू किया है, जिसके तहत न्यायिक परिषद को स्पष्ट रूप से न्यायिक विषय-समिति के बारे में शिकायतें प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 39

अस्पष्ट रूप से वर्णित आचरण "न्यायालयों के कार्य के प्रभावी और शीघ्र प्रशासन के लिए प्रतिकूल, या यह आरोप लगाते हुए कि ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है।" यह प्रशासनिक प्रणालियों के भीतर ऐसी शिकायतों को संसाधित करने के लिए एक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित करता है।

परिषदों और न्यायिक सम्मेलन का सत्र। यदि कोई परिषद यह मानती है कि आचरण महाभियोग के लिए आधार है तो मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक सम्मेलन को प्रमाणित किया जा सकता है जो उचित कार्रवाई कर सकता है और यदि महाभियोग को आवश्यक माना जाता है, तो सम्मेलन को रिकॉर्ड और इसके निर्धारण को प्रतिनिधि सभा को प्रेषित करने का अधिकार है।

जहाँ तक राज्यों का संबंध है, सभी पचास राज्यों में अपने न्यायाधीशों को अनुशासित करने के लिए केंद्रीय संस्थान हैं और प्रत्येक में अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं।

निर्णय आयोग या तो एक स्तर में या कई स्तरों में आयोजित किया जाता है जो तथ्य-खोज को निर्णय की सिफारिश के कार्यों से अलग करने की कथित वांछनीयता पर निर्भर करता है। आयोग की सिफारिशें राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को इसकी आधिकारिक अनिवार्यता के लिए हस्तांतरित की जाती हैं, सिवाय उन राज्यों के जहां वे उन विधानसभाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं जो न्यायिक पुनः चल शक्ति बनाए रखते हैं। (रॉबर्ट J.Janosik एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द अमेरिकन जूडी सियाल सिस्टम, Vol.II पीपी देखें। 575 578)।

18. उपर्युक्त में प्रचलित प्रथा का यह अध्ययन

देशों से पता चलता है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में विधायिका में हटाने की औपचारिक प्रक्रिया की स्थापना से पहले एक न्यायिक एजेंसी द्वारा एक न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार या अक्षमता के आरोपों की जांच और जांच शामिल है। इंग्लैंड एकमात्र अपवाद है जहाँ पूरी प्रक्रिया संसद में है लेकिन यह भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं कि संसद के सदनों द्वारा मामले को उठाने से पहले इसे न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा जांच की न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा और विधि संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों में की गई सिफारिशों का भी यही रुझान है

यर्स।

19. अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन अपने 19 वें द्विवार्षिक सम्मेलन में

अक्टूबर 1982 में नई दिल्ली में आयोजित न्यायिक स्वतंत्रता के न्यूनतम मानकों को अपनाया गया। 'न्यायिक निष्कासन और डिस्की प्लाइन' से संबंधित पैरा 27 से 32 निम्नानुसार हैं:

" 27. अनुशासन और न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही से न्यायाधीश के लिए निष्पक्षता और सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित होना चाहिए।

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40

28. अनुशासन की प्रक्रिया कैमरे में रखी जानी चाहिए।

जनता, इस अनुरोध के अंतिम और तर्कपूर्ण स्वभाव के अधीनअनुशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा। अनुशासनात्मक मामलों में निर्णय

भोजन चाहे कैमरे में हो या सार्वजनिक रूप से, पब हो सकता है

प्रस्फुटित।

29. (क) न्यायाधीशों को हटाने के लिए आधार निर्धारित किए जाने चाहिए -

कानून और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।

(ख) सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई मानकों पर आधारित होगी -

कानून द्वारा या स्थापित नियमों में घोषित न्यायिक आचरण

30. एक न्यायाधीश को हटाने के अधीन नहीं किया जाएगा जब तक कि, कारण से नहीं।आपराधिक कार्य या घोर या बार-बार उपेक्षा या शारीरिक रूप से

कैल या मानसिक अक्षमता, उसने खुद को स्पष्ट रूप से एक दिखाया है

न्यायाधीश का पद धारण करने के लिए उपयुक्त।31. ऐसी प्रणालियों में जहां न्यायाधीशों को अनुशासित करने और हटाने की शक्ति है

विधानमंडल के अलावा किसी अन्य संस्थान में निहित है, न्यायाधिकरण

अनुशासन और न्यायाधीशों को हटाने के लिए कानून अस्थायी होगा।

और मुख्य रूप से न्यायपालिका के सदस्यों से बना होगा।32. न्यायालय के प्रमुख के पास वैध रूप से पर्यवेक्षी हो सकता है।

प्रशासनिक मामलों पर न्यायाधीशों को नियंत्रित करने की शक्तियाँ।

20. न्याय की स्वतंत्रता पर पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया

10 जून, 1983 को मॉन्ट्रियल में एक सार्वभौमिक को अपनाया गया। न्याय की स्वतंत्रता पर घोषणा। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायाधीशों से भी संबंधित है। निम्नलिखित अनुच्छेद राष्ट्रीय न्यायाधीशों के संबंध में 'अनुशासन और पुनः चलन' से संबंधित हैं:

"2.32 न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

• एक उचित अभ्यास के तहत जानबूझकर और निष्पक्ष रूप से, और न्यायाधीश

शिकायत पर टिप्पणी करने का अवसर मिलेगा

प्रारंभिक चरण। शिकायत की प्रारंभिक जांच

चरण को गोपनीय रखा जाएगा, जब तक कि अन्यथा अनुरोध नहीं किया जाता है न्यायाधीश।

2,33 (क) न्यायिक निष्कासन या अनुशासन के लिए कार्यवाही,

जब ऐसी पहल की जाती है, तो अदालत या बोर्ड के समक्ष आयोजित की जाएगी।

मुख्य रूप से न्यायपालिका के सदस्यों से बना और से

न्यायपालिका द्वारा ली गई।

(ख) हालांकि, हटाने की शक्ति पैर में निहित हो सकती है।

महाभियोग या संयुक्त संबोधन द्वारा, अधिमानतः एक 23 (क) में निर्दिष्ट न्यायालय या बोर्ड की सिफारिश। .

जेयूडीएल पर छूट। उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 41

[स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी: उन देशों में जहां कानूनी पेशा कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपरिहार्य भूमिका निभाता है, यह अनुशंसा की जाती है कि कानूनी पेशे के सदस्य अदालत या बोर्ड के सदस्यों के चयन में भाग लें, और उन्हें इसके सदस्यों के रूप में शामिल किया जाए।]

2.34 सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई न्यायिक आचरण के स्थापित मानकों पर आधारित होगी। 2.35 न्यायाधीशों के अनुशासन के लिए कार्यवाही न्यायाधीश के लिए निष्पक्षता और पूर्ण सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करेगी।

2.36 विधानमंडल के समक्ष कार्यवाही के अपवाद के साथ, अनुशासन और हटाने की कार्यवाही कैमरे में रखी जाएगी। तथापि, न्यायाधीश अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण द्वारा इस अनुरोध के अंतिम और तर्कपूर्ण निपटारे के अधीन, सार्वजनिक रूप से सुनवाई आयोजित करने का अनुरोध कर सकता है। डिस्क में निर्णय पूर्ण कार्यवाही, चाहे कैमरे में हो या सार्वजनिक रूप से, हो सकती है

प्रकाशित किया जाए।

2.37 विधानमंडल के समक्ष या उनके संबंध में कार्यवाही के अपवाद के साथ, एक अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण का निर्णय अदालत में अपील के अधीन होगा। 2.38 एक न्यायाधीश को हटाने के अधीन नहीं किया जाएगा, सिवाय असमर्थता या दुर्व्यवहार के साबित आधारों के, जिससे वह पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है।

2.39 यदि किसी न्यायालय को समाप्त कर दिया जाता है तो इस न्यायालय में सेवारत न्यायाधीश प्रभावित नहीं होंगे, सिवाय उसी स्थिति के किसी अन्य न्यायालय में उनके स्थानांतरण के। ”

26 अगस्त से सितंबर 985 तक मिलान में आयोजित अपराध की रोकथाम पर सातवीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने अपराध की स्वतंत्रता पर बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया। अनुच्छेद 17 से 20 'अनुशासन, निलंबन और

ये निम्नानुसार हैं:

" 17.एक न्यायाधीश के खिलाफ उसकी न्यायिक और व्यावसायिक क्षमता में लगाए गए आरोप या शिकायत पर एक उचित प्रक्रिया के तहत तेजी से और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। प्रारंभिक चरण में मामले की जांच को गोपनीय रखा जाएगा, जब तक कि

अन्यथा न्यायाधीश द्वारा अनुरोध किया गया।

18. न्यायाधीश केवल असमर्थता या व्यवहार के कारणों से निलंबन या निष्कासन के अधीन होंगे जो उन्हें [1991] एस. यू. पी. पी. के लिए अयोग्य बनाता है।

2 एस सी आर।

42

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

19. सभी अनुशासनात्मक, निलंबन या हटाने की कार्यवाही

जू के स्थापित मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाए न्यायिक आचरण।

20. अनुशासनात्मक, निलंबन या हटाने के निर्णय आगे बढ़ते हैं।एक स्वतंत्र समीक्षा के अधीन होना चाहिए। यह राजकुमार

याचिका उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर लागू नहीं हो सकती है और

महाभियोग या इसी तरह की कार्यवाही में विधायिका के

िंग्स "।

कांग्रेस दस्तावेज़ों का समर्थन संयुक्त राष्ट्र जनरल ने किया था

9 नवंबर, 1985 को अपने संकल्प 40/32 और संकल्प 40 /

146 13 दिसंबर, 1985 को। संकल्प 40/146 दिनांक 13 दिसंबर, 1985

महासभा ने विशेष रूप से बुनियादी सिद्धांतों का स्वागत किया

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार को सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया

उन्हें और उनके राष्ट्रीय विधान और व्यवहार के ढांचे के भीतर उन्हें ध्यान में रखना "(पैरा 2)।

22. इंग्लैंड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विपरीत, न्यायाधीश

उपनिवेशों में निपटान अधिनियम, 1700 के तहत गारंटी के अनुसार कार्यकाल की सुरक्षा का आनंद नहीं लिया गया था और वे क्राउन की खुशी पर पद धारण करते थे।

(देखिए: टेरेल वी। उपनिवेशों के लिए राज्य सचिव और एक अन्य, 1953 (2), 482)। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधिनियमन तक भारत में स्थिति अलग नहीं थी। उक्त अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा 2 के परंतुक के खंड (बी) में, जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है, यह निर्धारित किया गया था कि "एक न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या शरीर या मन की दुर्बलता के आधार पर गवर्नर-जनरल के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है, यदि प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति, संदर्भित करती है।

उन्हें सूचित किया जा रहा है कि न्यायाधीश को ऐसे किसी भी आधार पर हटाया जाना चाहिए। धारा 220 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए थे। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले, संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अपने मन और शरीर की दुर्बलता के कथित आधारों के बारे में एक न्यायिक निकाय द्वारा निर्धारण करना आवश्यक था। क्या संविधान इस स्थिति को इस तरह से बदलने का प्रयास करता है, ताकि किसी न्यायिक निकाय द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण को बाहर किया जा सके और केवल संसद में ही दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण सहित हटाने की शक्ति को समाप्त किया जा सके।

23. मूल रूप से, एक न्यायाधीश को हटाने या महाभियोग की प्रक्रिया है

एक राजनीतिक प्रक्रिया। "द इम्पीचमेंट ऑफ द फेडरल एम. एम. आई. टी. ई. ऑन जे. यू. डी. एल". में एक विद्वान लेखक।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.]

43

* [व्रीस्ले ब्राउन हार्वर्ड लॉ रिव्यू 1912-1913 684 पृष्ठ पर

" ..... इस प्रकार इस देश में महाभियोग, हालांकि बाहरी रूप और समारोह में न्यायिक है, भावना में राजनीतिक है। यह एक राजनीतिक अपराध के खिलाफ निर्देशित है। यह एक राजनीतिक निर्णय में समाप्त होता है। यह एक राजनीतिक ज़ब्ती लागू करता है। प्रशासन के बारे में कहें तो हर मायने में, यह पूरी तरह से राजनीतिक परिणामों के साथ एक राजनीतिक बुराई के दमन के लिए एक राजनीतिक उपाय है।

इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक और न्यायिक शक्तियों में कोई भ्रम नहीं होता है। सीमांकन की रेखा औपचारिक गैर-आवश्यक वस्तुओं की भूलभुलैया के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, जिसके तहत विभिन्न मामलों में कुशल वकीलों ने इसे दफनाने की कोशिश की है। महाभियोग के दोषी ठहराए जाने पर संसद के उच्च न्यायालय का निर्णय अपने आप राजनीतिक संपत्ति को जब्त करने का काम करता है।

क्षमता; लेकिन यह केवल निर्णय का एक प्रभाव है, जो है

निर्णय से ही अलग होना। "

रो कैपेलेटी 'तुलनात्मक पर्सपेक एंडन प्रेस-ऑक्सफोर्ड 1989 में पृष्ठ 731 पर न्यायिक प्रक्रिया में कहते हैं:

" इस उत्तरदायित्व प्रकार की दो मुख्य विशेषताओं की पहचान की जा सकती है; पहला, यह तथ्य कि 'राजनीतिक' निकायों को, अंततः विधायी और/या कार्यकारी शाखाओं को अनिवार्य रूप से 'राजनीतिक', गैर-न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लेखा दिया जाना चाहिए; दूसरा, और शायद इससे भी अधिक विशिष्ट रूप से, यह तथ्य कि लेखा 'कानूनी' उल्लंघनों के लिए नहीं, बल्कि व्यवहार के लिए दिया जाना चाहिए (और इसमें निजी, कार्यालय से बाहर के व्यवहार शामिल हो सकते हैं) जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है -

' राजनीतिक 'मानदंड।

शायद राजनीतिक जवाबदेही का सबसे अच्छा उदाहरण सामान्य कानून परंपरा की प्रणालियों में पाया जा सकता है। इंग्लैंड में, न्यायाधीशों (किसी भी अन्य अधिकारी की तरह) पर 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष, हाउस ऑफ कॉमन्स के मुकदमे में' महाभियोग चलाया जा सकता है, हालांकि यह प्रथा अस्वीकृत हो गई

है; इसके अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्राउन द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा महामहिम को प्रस्तुत किए गए पते पर पद से हटाया जा सकता है। इस 'पता' प्रक्रिया के पीछे का विचार यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति 'अच्छे व्यवहार के दौरान' की जाती है, इसलिए शर्त का उल्लंघन करने पर उन्हें हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार में ऐसी परिस्थितियाँ शामिल हैं जैसे 'ऐसी प्रकृति के किसी भी कुख्यात अपराध के लिए अभियोग पर दोषसिद्धि का मामला जो 44 को प्रस्तुत करता है।

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्ति कार्यालय का प्रयोग करने के लिए अयोग्य ', लेकिन' अनुचित व्यायाम 'भीकार्यालय से संबंधित कार्यों का, या गैर-उपस्थिति,

या कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने की उपेक्षा या इनकार '। में से

बेशक सदनों और क्राउन का निर्णय केवल हो सकता है

भले ही हमें सूचित किया जाता है कि हटाने की प्रक्रिया है कुछ हद तक 'प्राकृतिक न्याय के नियमों' के अधीन।

24. लेकिन भारत में संवैधानिक योजना एक न्यायिक लक्षय प्राप्त करना चाहती है।

हटाने के लिए राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का विवेकपूर्ण मिश्रण

न्यायाधीश। यद्यपि यह पहली नजर में प्रतीत होता है कि कार्यवाही,

संविधान सभा के खंड (4) और (5) को अपनाने से संबंधित अनुच्छेद 124 इसके विपरीत इंगित करता है और एक इरादे को दर्शाता है

अभियोग की शुद्धता के न्यायिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारण को बाहर करें अधिक सावधानीपूर्वक जाँच करने पर दुर्व्यवहार या अक्षमता के लक्षण

यह सही निष्कर्ष नहीं है। विद्वान _ सलाहकार की प्रस्तुतियों में

जो एक जूडी लाने के इरादे की अभिव्यक्ति के खिलाफ संघर्ष करते हैं

मुख्य तत्व, संविधान की कार्यवाही पर निर्भरता रखी गई है

उच्चतम न्यायालय से संबंधित संघ संविधान समिति की रिपोर्ट के खंड 18 को अपनाने से संबंधित 29 जुलाई, 1947 की विधानसभा। श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने उक्त खंड में संशोधनों और शर्तों के

अधीन उक्त खंड को आगे बढ़ाया था जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें हटाने से संबंधित था। यह प्रावधान किया गया था कि "भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा उसी सत्र में संघ की संसद के दोनों सदनों से एक संबोधन के अलावा इस तरह के दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए नहीं हटाया जाएगा। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए संघीय कानून द्वारा आगे का प्रावधान किया जा सकता है। श्री K.Santhanam

न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित उक्त खंड में एक संशोधन पेश किया था और वह चाहते थे कि आगे के प्रावधान के बारे में अंतिम वाक्य

उस ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए संघीय कानून को हटा दिया जाना चाहिए। श्री M.Ananthasayanam अय्यंगार ने दो संशोधनों का सुझाव दिया

न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में खंड के स्थान पर वैकल्पिक खंड। एक खंड में यह सुझाव दिया गया था कि "एक न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या मन या शरीर की दुर्बलता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।

कानून के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति को इस संबंध में प्रस्तुत एक संबोधन में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा चुने गए कम से कम 7 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की एक समिति, जांच करती है और रिपोर्ट करती है कि ऐसे किसी भी आधार पर न्यायाधीश को हटा दिया जाए। श्री M.Ananthasayanam अय्यंगार द्वारा सुझाए गए अन्य वैकल्पिक खंड में कहा गया था कि "उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या मन या शरीर की दुर्बलता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति द्वारा इसे (सर्वोच्च न्यायालय) संदर्भित किया जा रहा है, तो एक विशेष उपबंध

:

सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. उत्तरदायित्व v. यू. ओ.)। [बी. सी. रे, जे.]

45

न्यायाधीशों या पूर्व न्यायाधीशों के बीच से इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण

उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रिपोर्ट करते हैं कि न्यायाधीश

ऐसे किसी भी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। संविधान सभा

कृष्णस्वामी अय्यर ने श्री एम. द्वारा सुझाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। अनंतसायनम अय्यंगार। श्री संथानम ने अपने संशोधन पर जोर नहीं दिया

और इसे वापस ले लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संशोधनों मेंश्री M.Ananthasayanam अय्यंगार द्वारा सुझाव दिया गया था, यह प्रदान किया गया था

कि दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच होनी चाहिए या

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से बनी समिति द्वारा दुर्बलता

या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या पूर्व न्यायाधीशों से युक्त विशेष न्यायाधिकरण

या उच्चतम न्यायालय, लेकिन द्वारा प्रस्तावित उक्त संशोधनों की अस्वीकृति

जूडी द्वारा ऐसे आरोपों की शुद्धता के बारे में निर्धारण का पक्षकारण श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, खंड को आगे बढ़ाते हुए

18 'दुर्व्यवहार साबित हुआ' शब्द पर जोर दिया था और कहा था:

खंड में प्रावधान है कि आरोपों को साबित किया जाना चाहिए। वास्तव में कैसे? आरोप साबित करने के लिए संघीय कानून में प्रावधान किया जाएगा।

हमें अधिक सावधानीपूर्वक या अधिक विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है।

जिन लोगों ने अन्य क्षेत्राधिकारों में इसी तरह के मामले की सुनवाई की है। आई.

मेरे दोस्त को यह कहने के लिए चुनौती दें कि क्या कोई विस्तृत प्रावधान है

किसी भी अन्य मामले में न्यायाधीशों को हटाने से अधिक

दुनिया में संविधान। सामान्य सिद्धांत निर्धारित किया गया है

संविधान में और बाद में संघीय कानून प्रदान करेगा

पर्याप्त मशीनरी के लिए और वह है आयात

खंड "। "सिद्ध" संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा है।

दुर्व्यवहार "और हम विस्तृत और पर्याप्त प्रो बना सकते हैं

जिस तरह से अपराध को घर लाया जा सकता है, उसके लिए दृष्टिकिसी भी संघीय कानून में एक विशेष न्यायाधीश जिसे पारित किया जा सकता है लेकिन

यह एक अलग बात है "।" लेकिन मुझे नहीं लगता कि

संविधान के बारे में विस्तृत तंत्र प्रदान करना आवश्यक है

अल।

महाभियोग, एक विशेष के खिलाफ बनाए जाने वाले आरोप

न्यायाधीश। इन सब के लिए एक विस्तृत मशीनरी बनाना एक हो सकता है

किसी भी संविधान में अपनाई जाने वाली नई प्रक्रिया "।

(संविधान सभा की बहस, खंड। आई से VI पीपी पर। 899-900)

25. संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 103 पर 24 मई, 1949 को संविधान सभा की बहस का भी संदर्भ दिया गया था। श्री तजामुल हुसैन ने अनुच्छेद 103 के खंड (4) में एक संशोधन पेश किया जो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित था और सुझाव दिया कि

उक्त खंड में संशोधन ताकि यह कहा जा सके कि "सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] का एक न्यायाधीश।

2 एस सी आर।

46

राष्ट्रपति और आदि "। उक्त संशोधन को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया था। (संविधान सभा की बहस, वॉल्यूम। पीपी पर VIII। 243 और 262)। उक्त संशोधन श्री एम. अनंतसायनम, अय्यंगार द्वारा केंद्रीय संविधान समिति की रिपोर्ट के खंड 18 को अपनाने के चरण में पेश किए गए संशोधनों के समान था। श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा उक्त संशोधनों का विरोध करने के लिए दिए गए कारण इस संशोधन पर भी लागू होंगे। 26. इसलिए, संविधान सभा की कार्यवाही इस बात का संकेत नहीं देती है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) को अपनाने में, संरक्षक सभा का इरादा न्यायिक निकाय द्वारा हटाए जाने की मांग करने वाले न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और सबूत को बाहर करना था। श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो मसौदा समिति के सदस्य थे, द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए

M.Ananthasayanam अयंगार, यह अनुमान लगाना संभव है कि संविधान सभा का इरादा यह था कि इस तरह की जांच और सबूत के लिए तंत्र के संबंध में प्रावधान एक ऐसा मामला था जिसे संविधान में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी और यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए संसद द्वारा कानून द्वारा प्रावधान किया जा सकता था।

27. यह इस विषय पर कुछ ऐतिहासिक सामग्री और पृष्ठभूमि है। अब हम विवादों के गुणों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

आरई: सामग्री ए:

28. इस विवाद के दो पहलू हैं: क्या किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के सदन के भंग होने पर समाप्त हो जाता है और

दूसरा, यह सवाल कि क्या यह समाप्त हो जाता है या नहीं, उस सदन के अनन्य अधिकार क्षेत्र और निर्णय के भीतर एक मामला है। पहले पहलू पर, विद्वान महान्यायवादी और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल का तर्क समान है। दूसरे पहलू पर, विद्वान महान्यायवादी कहेंगे कि यह प्रश्न कि कोई प्रस्ताव समाप्त हो गया है या नहीं, मामले का मार्गदर्शन करने वाले कानून के प्रावधानों के आधार पर तय किया जाना है और सदन स्वयं इसका अंतिम मध्यस्थ नहीं है। विद्वान महान्यायवादी कहेंगे कि अकेले न्यायालय के पास मामले के कानून की जांच करने और उस पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र है।

29. चूक निर्भरता के सवाल पर एर्स्किन मे के "द लॉ, प्रिविलेज, प्रोसीडिंग्स एंड यूसेज सब-कमेटी ऑन जेयूडीएल" के उत्कृष्ट ग्रंथ पर रखा गया था।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 47

संसद का "[बीस-पहला संस्करण, लंदन बटरवर्थ्स 1989]। ए मो

यह एक "चित्रण के उद्देश्य से किया गया प्रस्ताव" के रूप में वर्णित है

सदन का निर्णय "। एर्स्किन मे के अनुसार, कुछ मामले हो सकते हैं

केवल एक मूल प्रस्ताव द्वारा उठाया गया। वह कहता है:

" कुछ मामलों पर बहस नहीं की जा सकती है, सिवाय एक ठोस प्रस्ताव के जो सदन के एक विशिष्ट निर्णय की अनुमति देता है। इनमें संप्रभु, सिंहासन के उत्तराधिकारी या शाही परिवार के अन्य सदस्यों, एक स्वतंत्र क्षेत्र के गवर्नर-जनरल, लॉर्ड चांसलर, अध्यक्ष, तरीकों और साधनों के अध्यक्ष, संसद के किसी भी सदन के सदस्य और यूनाइटेड किंगडम के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिसमें न्यायाधीश का पद धारण करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, का आचरण शामिल है।

जैसे कि दिवालियापन की अदालत और काउंटी अदालत में एक न्यायाधीश, या।

एक रिकॉर्डर "।

30. श्री सिब्बल ने निम्नलिखित कथनों पर दृढ़ता से भरोसा व्यक्त किया

"संसद के अभ्यास और प्रक्रिया" में M.N.Kaul और S.L.Shakdher के रूप में

सदन के विघटन के प्रभाव:

" विघटन, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एक सदन के जीवन के अंत को चिह्नित करता है और उसके बाद एक नए सदन का गठन होता है। एक बार जब सदन भंग हो जाता है, तो विघटन अपरिवर्तनीय होता

है। राष्ट्रपति के पास अपने विघटन के आदेश को रद्द करने और पिछले सदन को पुनर्जीवित करने की कोई शक्ति नहीं है। विघटन के निष्कर्ष निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय होते हैं। लोकसभा में, जो अकेले संविधान के तहत विघटन के अधीन है, विघटन "संसदीय स्लेट पर एक स्पंज पारित करता है"। इसके या इसकी किसी भी समिति के समक्ष लंबित सभी कार्य भंग होने पर समाप्त हो जाते हैं। भंग सदन के अभिलेखों के किसी भी हिस्से को नए सदन के अभिलेखों या रजिस्टरों में नहीं ले जाया जा सकता है और प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती है। संक्षेप में, विघटन आकर्षित करता है

मौजूदा सदन पर अंतिम पर्दा "।

अन्य व्यवसायों पर विघटन के प्रभाव की ओर रुख करना, जैसे -

विद्वान लेखकों का कहना है कि प्रस्ताव, संकल्प आदि:

" लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य, उदाहरण के लिए, प्रस्ताव, संशोधन, अनुदान के लिए पूरक मांगें आदि, किसी भी स्तर पर, भंग होने पर समाप्त हो जाते हैं, साथ ही सदन में प्रस्तुत याचिकाएं जो समिति को भेजी जाती हैं।

याचिकाओं पर "।

विद्वान महान्यायवादी ने आग्रह किया कि लेखों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए

107 , 108 और 109 अप्रतिरोध्य रूप से आगे बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष कि विघटन पर [1991] एस. यू. पी. पी.

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48 *

सदन में, सभी विधेयक केवल अनुच्छेद 108 में निर्धारित अपवाद के अधीन रहते हुए समाप्त हो जाएंगे। यह भी आग्रह किया जाता है कि पहले सिद्धांत पर भी यह आवश्यक है कि

यह स्वीकार किया गया कि सदन के विघटन पर कोई भी प्रस्ताव तब तक कायम नहीं रहना चाहिए जब तक कि प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत अन्यथा निर्धारित न किया गया हो। यह आग्रह किया जाता है कि चूक का सिद्धांत इस विचार का एक आवश्यक सहवर्ती है कि प्रत्येक नवगठित सदन एक अलग इकाई है जिसका अपना जीवन है जब तक कि पिछले सदन का कार्य क़ानून के बल या प्रक्रिया के नियमों द्वारा नहीं किया जाता है। विद्वान अटॉर्नी जनरल इराल और श्री कपिल सिब्बल दोनों ने हमें संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के बारे

में बताया ताकि यह दिखाया जा सके कि सदन का कार्यकाल समाप्त होने या इसके पहले भंग होने पर सभी लंबित कार्य हमेशा समाप्त हो जाते हैं।

श्री राम जेठमलानी ने याचिकाकर्ता-उप-समिति की ओर से

ब्रिटिश संसद के सम्मेलनों और आग्रह किया कि कार्य लंबित है। सत्रावसान में चूक और एक सामान्य प्रथा के रूप में सदन को आमतौर पर भंग करने से पहले रद्द कर दिया जाता है। विद्वान वकील ने कहा कि महाभियोग

गतियाँ अपने स्वभाव में उदार होती हैं और वे समाप्त नहीं होती हैं। वह है। हालाँकि, लिखित संविधान के तहत भारतीय संसदीय अनुभव को ब्रिटिश सम्मेलनों से अलग करना आवश्यक है। वास्तव में, पुरुषोत्तमन नम्बूदिरी बनाम में इस न्यायालय के व्यपगत होने के सिद्धांत का संदर्भ लें। केरल राज्य [1962] पूरक। 1 एस. सी. आर. 753 गजेंद्रगडकर जे. ने कहा:

..... इस तर्क के समर्थन में यह आग्रह किया जाता है कि जहाँ भी

सरकार का अंग्रेजी संसदीय रूप इन शब्दों पर हावी है।" सत्रावसान "और" विघटन "ने स्थिति प्राप्त कर ली है

कला के संदर्भ और उनके महत्व और परिणाम अच्छी तरह से हैं।

तय हो गया। तर्क यह है कि यदि इसका कोई प्रावधान नहीं है।

हमारे संविधान में इसके विपरीत अंग्रेजी कन्वेंशन

विघटन के परिणाम के लिए उद्यान को नीचे रखा जाना चाहिए

भारत में भी कम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी में, अड्डी में

उन सभी व्यवसाय को समाप्त कर देता है जो विचाराधीन हैं इस तरह के सत्रावसान के समय किसी भी सदन के समक्ष; परिणामस्वरूप

सदन में या किसी समिति में कोई कार्यवाही

सत्र के साथ सदन की समाप्ति संसद का विघटन है

अनिवार्य रूप से सत्रावसान से पहले, और इसके बारे में क्या सच है सत्रावसान का परिणाम है, यह कहा जाता है, एक फोर्टियोरी के बारे में सच है

विघटन का परिणाम। कभी-कभी संसद का विघटन होता है

"संसद की नागरिक मृत्यु" के रूप में वर्णित। इल्बर्ट, अपने काम में

'संसद' में कहा गया है कि "सत्रावसान का अर्थ है अंत।

एक सत्र का (संसद का नहीं) "; और जोड़ता है कि" विघटन की तरह "

यह उन सभी बिलों को समाप्त कर देता है जो अभी तक पारित नहीं हुए हैं। वह भी। विघटन को "संसद का अंत (न कि केवल सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल.)" के रूप में वर्णित किया गया है।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 49

एक सत्र) शाही घोषणा द्वारा ", और यह देखता है कि" यह मिटा देता है

सभी अधूरे नोटों या अन्य से स्लेट साफ करें

कार्यवाही "। p.759 और 760]।

इंग्लैंड में स्थिति का उल्लेख करने के बाद कि का विघटन

विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि संसद का सदन समाप्त हो गया और इस मायने में विघटन के समय सदन की सभी व्यस्तताओं को समाप्त कर दिया गया।

..... इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि सी. एल. का प्रभाव। (5) होना है।

उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करें जहां विघटन पर चूक का सिद्धांत

यह लागू होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो एक विधेयक की सहमति लंबित है

राज्यपाल या राष्ट्रपति सी. एल. से बाहर हैं। (5) और कहा नहीं जा सकता विधानसभा के विघटन पर चूक "।

[पी। 768]

" ..... सीएल की अनुपस्थिति में। (5) इसके बाद यह सब हुआ होगा

लंबित व्यवसाय, अंग्रेजी सम्मेलन के सादृश्य पर,

विधान सभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। यह.

यह सच है कि वर्तमान याचिका द्वारा हमारे सामने उठाया गया प्रश्न

कला के तहत। 196 कठिनाई से मुक्त नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर, हम

वे यह दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक हैं कि सी. एल. का प्रभाव। (5) बस इतना ही?

इसके दायरे में नहीं आने वाले मामले इस सिद्धांत के अधीन नहीं हैं

विधान के विघटन पर लंबित कार्य की समाप्ति

अपनी सभा। इस अर्थ में हम सी. एल. पढ़ते हैं। (5) एक्साउस से निपटने के रूप में बिलों के साथ सक्रिय रूप से जो के विघटन पर समाप्त हो जाएगा

सभा। यदि यह सही स्थिति है तो तर्क है कि

वह विधेयक जो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित था, समाप्त हो गया

विधान सभा के विघटन को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

[पी. 769]

31. यह सच है कि पुरुषोत्तमन नम्बूदिरी का मामला एक कानून के साथ निपटता है

लेटिव उपाय और गति की प्रकृति में एक लंबित व्यवसाय नहीं। लेकिन, हम इस विचार से सहमत हैं कि न तो यह सिद्धांत कि किसी सदन का विघटन "संसदीय स्लेट पर एक स्पंज पारित करता है" और न ही संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए किसी भी नियम या नियमों में निहित विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विघटन के प्रभाव को निर्धारित करते हैं. कारण यह है कि अनुच्छेद 124 (5) और उसके तहत बनाया गया कानून इस क्षेत्र में अनुच्छेद 118 के संचालन को बाहर करता है।

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है:

* 3 (1) यदि पता प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है

राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करते हुए -

(क) लोक सभा में दिए गए नोटिस के मामले में,

उस सदन के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा; [1991] एसयूपीपी।

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50

(ख) राज्य परिषद में दी गई सूचना के मामले में,

उस परिषद के कम से कम पचास सदस्य;

तब, अध्यक्ष या, यथास्थिति, अध्यक्ष, -

ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद, यदि कोई हो, जो वह उचित समझता है

ऐसी सामग्री, यदि कोई हो, जो उसके लिए उपलब्ध हो, पर विचार करते हुए,

(2) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तोअध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष रखेंगे -

प्रस्ताव लंबित है और इसके लिए, जितनी जल्दी हो सके, गठन किया जाता है

उन आधारों की जाँच करने का उद्देश्य जिन पर एक न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना की जाती है, एक समिति जिसमें

तीन सदस्यों में से

(क) मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों में से एक का चयन किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से एक का चयन किया जाएगा।

अदालतें; और

(ग) एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो, अध्यक्ष की राय में या, के रूप में

मामला, अध्यक्ष, एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो सकता है;

प्रोविसो &)

हटा दिया गया।

उप-अनुभाग)

के रूप में

(3) से (9))

यहाँ अनावश्यक है।

?

धारा 6 (2) में प्रावधान है:

" (2) यदि समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष मिलता है कि न्यायाधीश किसी दुर्व्यवहार का दोषी है या किसी शांति भंग से पीड़ित है, तो धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव, समिति की रिपोर्ट के साथ, सदन या संसद के उन सदनों द्वारा विचार के लिए लिया जाएगा जिनमें यह लंबित है।

इन प्रावधानों का प्रभाव यह है कि प्रस्ताव को तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक कि समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती और यदि समिति को पता चलता है कि

दोषी ठहराएँ, प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। केवल एक प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है जो लंबित रहेगा। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि प्रस्ताव को सदन के विघटन के सामान्य प्रभाव के अधीन लंबित रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि संसद द्वारा बनाया गया और सदन को बाध्य करने वाला कानून चूक के सिद्धांत के खिलाफ प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 124 (5) में परिकल्पित कानून संसदीय कानून है जो अनुच्छेद 118 के तहत सदन द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में उच्च गुणवत्ता और प्रभावकारिता का है। ऐसा कानून, और वर्तमान क़ानून के तहत, जे. यू. डी. एल. पर उप-समिति कर सकता है।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. 1. [बी. सी. रे, जे.]

51

चूक के सिद्धांत के खिलाफ प्रदान करें। इसके अलावा, कला। 118 स्पष्ट रूप से कहता है कि

संसद का प्रत्येक सदन विनियमन के लिए नियम बना सकता है।

इस संविधान के प्रावधान "।

पंजाब राज्य में v. सत पाल डांग और ओआरएस। [1969] 1 एस. सी. आर. 478 यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 209 के प्रयोजनों के लिए कानून (अनुच्छेद के अनुरूप)

119) यहाँ तक कि सरकार द्वारा घोषित अध्यादेश का रूप भी ले सकता है

न ही अनुच्छेद 214 के तहत किसी राज्य का और न ही जहां कहीं प्रतिकूलता है अनुच्छेद 208 (अनुच्छेद 118) के तहत बनाए गए प्रक्रिया नियमों के बीच

संसद के मामले में), अनुच्छेद 209 के तहत बनाया गया कानून प्रबल होगा। में।

न्यायाधीश को हटाने का संवैधानिक क्षेत्र, अनुच्छेद के तहत बनाया गया कानून

124 (5) थोड़ा और आगे जाने और संचालन को बाहर करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए

अनुच्छेद 118 के तहत नियम। वास्तव में, तिरस्कार का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था

यह उस हद तक उत्पन्न होता है जब क्षेत्र अनुच्छेद 124 (5) के तहत कानून द्वारा कवर किया जाता है।

इस तरह का दृष्टिकोण वास्तव में कुछ विसंगतियों को दूर करेगा जो हो सकती हैं

अन्यथा उत्पन्न होता है। राज्यसभा भंग नहीं की गई है और वर्तमान के लिए एक प्रस्ताव है

न्यायाधीश को हटाने के लिए पता वहाँ कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अनुभाग

3 यह संसद के दोनों सदनों पर लागू होता है। शब्द "रखेंगे

लंबित प्रस्ताव के दो अलग-अलग अर्थ नहीं हो सकते हैं।

उस घटना का प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। हमारा मानना है कितर्क है कि ऐसा प्रस्ताव सदन के विघटन के साथ समाप्त हो जाता है

संसद टिकने योग्य नहीं है।

32. विवाद ए का दूसरा अंग यह है कि सवाल यह है कि क्या

यह दावा किया जाता है कि संसद के सदनों को अनन्य होने का विशेषाधिकार प्राप्त हैउनकी कार्यवाहियों की वैधता के मध्यस्थ। मजबूत निर्भरता रही है

ब्रैडलॉफ बनाम में अक्सर उद्धृत निर्णय पर रखा गया। गोसेट,

[1884] 12 प्र. बी. डी. 271. वहाँ संसदीय न्यायशास्त्र की विशिष्टता है

उस क्षेत्र से संबंधित मामले पर जहां संसद, न कि न्यायालय, इसके पास अनन्य अधिकार क्षेत्र था, भले ही मामले एक क़ानून द्वारा कवर किए गए हों।

लेकिन जहाँ, इस देश में और इंग्लैंड के विपरीत, एक है

लिखित संविधान जो मौलिक और उस अर्थ में एक "उच्च कानून" का गठन करता है और विधानमंडल और अन्य पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है।

संविधान के तहत अनुदान प्राप्तकर्ताओं के रूप में राज्य के अंग, संसदीय संप्रभुता की सामान्य घटनाएं प्राप्त नहीं होती हैं और अवधारणा 'सीमित सरकार' में से एक है। न्यायिक समीक्षा, वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की एक घटना है और प्रवाहित होती है।

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

· 52

मौलिक की इस अवधारणा से। और उच्च विधि राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमाओं का स्पर्श पत्थर है जो संविधान के तहत शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं और यह कि न्यायिक शाखा संविधान की व्याख्या करने वाली है और इसलिए, राज्य के विभिन्न अंगों की लेखक की सीमाओं की व्याख्या करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्राउन के साथ ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और इसकी शक्तियां

असीमित हैं और अदालतों के पास कानून की न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। सोननगस्टल स्टेड नवस्टेड टेड: बस [19 बेटा।

इस प्रकार 6 10 100

79

नी 8! यह सिद्धांत एक अर्थ में स्थायी कानून में अति अधिकार का सिद्धांत है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक बन जाती है! वास्तव में, मद्रास राज्य, [1950], एस. सी. आर. 88 अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13 को स्वयं बहुतायत से युक्त माना गया था और यह कि इसकी अनुपस्थिति में भी यदि किसी भी विधायी अधिनियम द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था, तो अदालत को हमेशा यह घोषित करने की शक्ति थी: अधिनियम अमान्य है। एक कानूनी साधन के रूप में संविधान की व्याख्या और इसका दायित्व न्यायालयों का कार्य है। यह दृढ़ता से प्रांत है

और न्यायिक विभाग का कर्तव्य है कि वह बताए कि कानून क्या है। इन रे: विशेष संदर्भ मामला, [1965] 1 एससीआर 413 गजेंद्रगडकर, सीजे ने कहा: ** ' ओ बॉन

1 1992 265 3 ओ कोरोनी आर

टी.

.....यद्यपि हमारे विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं, वे कार्य करते हैं

सामग्री और प्रासंगिक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर

142 साले।

ई संविधान के प्रावधान। मैं।

यह है!

डब्ल्यूए

अल।

} } , {

को

लिखित संविधान द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में, यह

संविधान सर्वोच्च और संप्रभु है।

लेकिन यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधान की व्याख्या करे

जिसका अर्थ है कि यह न्यायालय अंतिम मध्यस्थ है।

एफ.

एफ.

100

7 33 ! श्री कपिल सिब्बल ने हमें निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया

ब्रैडलॉफ बनाम में स्टीफन जे। गोसेट, ऊपर:

4

स्विक्लैज़

सब सब नी एड या दे सान

एल. ई.

नहीं डी और

स्टार ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है कानून की व्याख्या करने की अनन्य शक्ति, जहाँ तक विनियमन

अपनी खुद की कार्यवाही को 'अपनी खुद की' दीवारों के भीतर करना अनुचित है।

13: प्रमाणित; और यह कि भले ही वह व्याख्या 'गलत होनी चाहिए:

सास, इस अदालत के पास इसमें सीधे हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है या

अप्रत्यक्ष रूप से "।

एन आर। शक "हालगढ़ ए स्टिलू: बार पेतुवो ईद ऐ 26 915dw तुद ए थुद्ज़ लार्ट नी कुस लेम्सरुलनैट आर सायंटानोस डोंड नोम [पी: 280 & 281] 1 तारिटो ब्रस "कुल! हाउस ऑफ कॉमन्स न्याय का न्यायालय नहीं है; लेकिन

अपनी आंतरिक चिंताओं को विनियमित करने के अपने विशेषाधिकार का प्रभाव

इसे व्यावहारिक रूप से न्यायिक चरित्र के साथ निवेश करने के लिए जब इसे संसद के अधिनियमों के प्रावधानों को विशेष मामलों में लागू करना होता है।

> सब-कमेटी ऑन जुडल एकाउंटेबिलिटी एफ. यू. क्यू. जे. 2 [बी. सी. रे, जे.] 532

हमें यह मान लेना चाहिए कि यह इस कार्य को ठीक से और उन कानूनों को ध्यान में रखते हुए करता है, जिनके निर्माण में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि इसका निर्धारण कानून के अनुसार नहीं है, तो यह एक न्यायाधीश द्वारा त्रुटि के मामले से मिलता-जुलता है जिसका निर्णय अपील के अधीन नहीं है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है।

: को। वीडी 22

-मूओ

उन बा

हू 90

4

इस तथ्य की मान्यता कि ऐसी त्रुटि संभव है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आपराधिक मामले में एक जूरी एक विकृत निर्णय देती है, तो कानून ने कोई उपाय प्रदान नहीं किया है। यह कहावत कि उपचार के बिना कोई गलत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, जैसा कि कभी-कभी माना जाता है, कि हर नैतिक या राजनीतिक गलत के लिए कानूनी उपाय है।

डब्ल्यू. एस. आई. ओ.

वाई.

लेज़।

पर सेट करें

70 होली

1 21 एस.

सोल।

:

[पी। 285]

!) 5,4 °

एआर

जे.

ब्रैडलॉफ बनाम में 'नियम'। गोसेट, ऊपर, को लागू नहीं माना गया था

लिखित संविधानों द्वारा शासित औपनिवेशिक विधायिका की कार्यवाहियां

बार्टन v.Taylor, [1886] 11 एसी 197 और रिडिफ्यूजन (हांगकांग) लिमिटेड बनाम। हांगकांग के महान्यायवादी, [1970] एसी 1136।

¿ हाँ, + टी 4.51

* विज्ञापन

ब्रैडलॉफ में सिद्धांत यह है कि एक वैधानिक अधिकार भी यदि यह संबंधित है

उस क्षेत्र में जहां संसद के पास अनन्य न्यायपालिका थी, न कि न्यायालयों के पास, यह संसद की अपनी चिंता का विषय होगा। लेकिन उस सिद्धांत का विस्तार नहीं किया जा सकता है जहां मामला केवल प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि संसदीय प्रक्रिया से परे के मामलों से संबंधित मूल कानून का है। प्रक्रिया के मामलों में भी संवैधानिक प्रावधान बाध्यकारी हैं क्योंकि कानून लागू करने योग्य हैं। संविधान की व्याख्या और कानून क्या है, इस बारे में अदालतों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे कहें कि कानून क्या है। यह प्रश्न कि क्या प्रस्ताव समाप्त हो गया है, संविधान के प्रावधानों और प्रासंगिक कानूनों के आधार पर सुनाया जाना है। वास्तव में, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि यह प्रश्न कि क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं और कानूनों की व्याख्या के रूप में, इस तरह का प्रस्ताव समाप्त हो जाता है या नहीं, विशेष रूप से अदालतों को तय करना है।

कानूनों की व्याख्या अदालतों का अधिकार क्षेत्र है और

संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की ऐसी व्याख्या के लिए यह अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता है कि कानून के तहत ऐसा प्रस्ताव व्यपगत नहीं होता है और न्यायालयों के पास ऐसा घोषित करने की अधिकारिता बनी रहती है। सामग्री ए का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

आरई: सामग्री (बी), (सी) और (डी):

34. इन विवादों में आम और अति-लैपिंग क्षेत्र हैं और

एक साथ निपटाए जाने और निपटाए जाने को स्वीकार करें। अनुच्छेद 121,124 (4) और 124 (5) के सही अर्थ और दायरे के लिए उपयुक्त व्याख्यात्मक मानदंडों पर, वास्तव में, तीन निर्माणात्मक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं:

1 [1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54

एक को हटाने के लिए सभी कदम उठाने की पूरी शक्ति

. सबसे पहले:

न्यायाधीश, द्वारा एक संबोधन की प्रस्तुति में समापन

राष्ट्रपति के लिए संसद के विभिन्न सदन

अकेले संसद के दोनों सदनों के लिए सीमित और नहीं

आई. एन. आई. के बिना किसी भी जांच की शुरुआत संभव है।

स्वयं सदनों द्वारा लिया जा रहा है। कोई कानून नहीं संसद द्वारा अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाया गया कानून हटा सकता है।

इस शक्ति को। अनुच्छेद 121 का प्रतिबंध उसी क्षण हटा दिया जाता है।

संसद का कोई भी सदस्य प्रस्ताव की सूचना देता है

एक न्यायाधीश को हटाना और उसके द्वारा लगाए गए सभी आरोपवह सदन में ही चर्चा के लिए खुला रहेगा। यह.

सदन के सदस्यों के बहुमत के लिए होगा

तय करें कि क्या और कैसे वे आरोप लगाना चाहेंगेजांच की गई। इस शक्ति को कम करना बुरा है।

दूसरा:

राष्ट्रपति को संबोधन प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव के बाद से

अनुच्छेद 121 और 124 (4) में निर्दिष्ट होना चाहिए

प्रस्ताव तब तक किया जा सकता है जब तक कि गलतियों से संबंधित आरोप न लगेव्यवहार या अक्षमता सबसे पहले साबित हुई है।

संसद के दोनों सदनों के बाहर किसी मंच पर। कानून

अनुच्छेद 124 (5) के तहत और संसद तक अनिवार्य है।

कानून बनाता है और जाँच के लिए प्रावधान करता है

कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता और विनियमन

इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहींन्यायाधीश को अनुच्छेद 124 (4) के तहत अनुमति होगी और

संसद के सदन को तस्वीर में नहीं लाया जाएगा

पार्लिया के दोनों सदनों के बाहर कुछ अधिकार होने तक

दुर्व्यवहार या असमर्थता का पता चला है इट्टी। 'सिद्ध' अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है।

कि अनुच्छेद 124 (5) केवल एक सक्षम प्रावधान है और

तीसरा:

कि यह प्रावधान किसी भी सदन में प्रवेश करने के लिए खुला होगा न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

हालाँकि, यह अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद के लिए खुला है।

शुरू होने वाली पूरी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने के लिए न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के साथ -

विज्ञापन की प्रस्तुति के साथ संबंधित और समाप्त

संसद के दोनों सदनों द्वारा पहना हुआ। यह खुला रहेगा।

संसद को अपनी पसंद के किसी भी प्राधिकरण को नामित करने के लिए

आरोपों की जांच करने और जे. यू. डी. एल. पर उप-समिति को विनियमित करने के लिए।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 55

दोनों में से किसी मामले पर विचार करने की प्रक्रिया

घर।जैसे ही कोई कानून अधिनियमित हो जाता है, उसके सभी प्रावधान संसद के दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी होंगे और संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को भी ओवरराइड कर देंगे। किसी भी सदन को ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। यह सवाल कि अनुच्छेद 121 के तहत किसी न्यायाधीश की नियुक्ति पर चर्चा के खिलाफ प्रतिबंध हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में कब और किन परिस्थितियों में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाएगी, संसद के ऐसे अधिनियम के अनुसार होगा।

पहले और दूसरे वैकल्पिक प्रस्तावों के संबंध में, संयुक्त चयन समिति के विचार-विमर्श साक्षय देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच एक तीव्र विभाजन का संकेत देंगे। श्री के. के. शाह और श्री एम. सी.

शाह के विचारों के बीच का अंतर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सीतलवाड़। पहला दृष्टिकोण इस मामले को पूरी तरह से सदन पर छोड़ देता है, जो मामले-दर-मामले अलग-अलग प्रक्रिया भी अपना सकता है। यह मामला पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से परे होगा। फिर राजनीतिक प्रभाव और असुविधाजनक न्यायिक घोषणाओं से उत्पन्न होने वाली समकालीन राजनीतिक उत्तेजनाओं का अपरिहार्य तत्व है जो इस प्रकार न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।

इस विषय पर एक कानून बनाना। अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून न्यायिक मूल्यों को टालने वाला एक बहुत ही सभ्य कानून हो सकता है।स्वतंत्रता। लेकिन तब संसद उस कानून को निरस्त करने और पहले विचार में परिलक्षित स्थिति पर लौटने के लिए स्वतंत्र होगी। तीसरा दृष्टिकोण हमेशा संसद के चुनाव में पहले स्थान के पूर्ण आयामों को प्राप्त कर सकता है।

35. दूसरे दृश्य की अपनी सराहनीय विशेषताएं हैं। यह विभिन्न प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से और न्यायिक स्वतंत्रता के पोषित मूल्यों के साथ सुसंगत रूप से पढ़ने में सक्षम बनाता है। यह अनुच्छेद 124 (4) में "सिद्ध" शब्द को उचित मान्यता भी देता है। यह दृष्टिकोण संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया की एकरूपता भी सुनिश्चित करेगा और न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही में मनमानेपन को समाप्त करने का काम करेगा। इससे दोनों सदनों में जांच और जांच के दोहराव से बचा जा सकेगा। आइए हम इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 124 के भौतिक भागों को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

" 121. संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। - कोई डिस्कस नहीं

आचरण के संबंध में संसद में आयोजन किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश काप्रस्तुत करने के प्रस्ताव को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन

न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित करना जैसा कि इसके बाद दिया गया है।

124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।

(1) ..... (2) उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी जिन्हें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पद धारण करेगा:

बशर्ते कि इसके अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा:

आगे कहा गया है कि -

(क) एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ के नीचे लिख कर, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;(ख) न्यायाधीश को उसके पद से इस तरीके से हटाया जा सकता है -

खंड (4) में उपबंधित। (4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन के अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा अपने पद से नहीं हटाया जाएगा।

उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को उसी सदन में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गलत साबित होने के आधार पर इस तरह के निष्कासन के लिए सत्र

हमारा या अक्षमता।

(5) संसद विधि द्वारा खंड (4) के अधीन किसी न्यायाधीश के अभिभाषण के पूर्वप्रवेश और दुर्व्यवहार या असमर्थता के अन्वेषण और प्रमाण के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। ”

धारा 121 में सुझाव दिया गया है कि किसी भी न्यायाधीश के आचरण के साथ संसद में चर्चा पर लगी रोक को राष्ट्रपति के समक्ष एक न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना करने वाले प्रस्ताव पर हटा दिया जाता है।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 57.

टेर प्रदान किया गया '। 'गति' और 'जैसा कि इसके बाद दिया गया है' शब्द ओबीवी हैं।

+ कैट कोहस

अनुच्छेद 124 के खंड (4) के प्रयोजन के लिए प्रस्ताव के संदर्भ

जो बदले में, "सिद्ध" दुर्व्यवहार या असमर्थता की अवधारणा को आयात करता है।

1202

इट्टी। जो बात अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध को उठाती है, वह है "दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार"।

साल्ट

असमर्थता। फिर सवाल उठता है कि जांच और सबूत कैसे।

BRAVO q

वीडियो

£ .....

2

हटाने के लिए गति के चरण से पहले दुर्व्यवहार या अक्षमताअनुच्छेद 124 (4) के तहत "सिद्ध" दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर

आगे बढ़ना है। अनुच्छेद 124 के खंड (5) में एक अधिनियम बनाने का प्रावधान है -

इस उद्देश्य के लिए कानून, लाठी में। मुझे अच्छा लग रहा है: 411 31.

.....ला वोरा

ओवो के लिए

100 od:

10 798 वी.

37. बुनियादी सवाल यह है कि क्या खंड (5) केवल एक मुद्दा है।

विशेष रूप से 'मे' शब्द के उपयोग को ध्यान में रखते हुए,

एम.

एमएएस

या इसमें डी. आई. जी. डब्ल्यू. ए. को हटाने की शक्ति पर एक शर्त, पूर्ववर्ती शामिल है।

संसद। दूसरे शब्दों में, कर सकते हैं, अनुच्छेद के तहत हटाने का कार्य

जुलाई

124 (4) खंड (5) के अधीन अधिनियमित विधि की सहायता के बिना निष्पादित किया जाएगा? अगर

प्रेपारा वी. 43

#उज़ाल

यह, तब, दुर्व्यवहार या पाप के लिए जांच और प्रमाण की शक्ति हो सकती है।

254 इन्टा, दा

न्यायाधीश की असमर्थता खंड (4) में ही पाई जानी चाहिए और

उडोवी फिये

12

खंड (5), केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए किसी विधि के अधिनियमन तक सीमित है यदि -

संसद ऐसा चाहती है और अन्यथा नहीं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि खंड

(5) हटाने की शक्ति पर एक संवैधानिक सीमा निहित है खंड (4) में ताकि इसका प्रयोग केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता पर किया जा सके।

यह खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार "सिद्ध" होता है। ऐसे में इस स्थिति में, संसद की शक्ति केवल इसके लिए उपलब्ध होगी

खंड (5) के तहत कानून बनाना, और यदि दुर्व्यवहार या अक्षमता है

" इस तरह के कानून के अनुसार साबित हुआ। वह गति जो बार को उठाती है

{

अनुच्छेद 121 में निहित वास्तव में खंड के तहत इस तरह के निष्कासन के लिए एक प्रस्ताव है

कथित दुर्व्यवहार के बाद अनुच्छेद 124 की धारा (4) सदन में चली गई, या 2

द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार अक्षमता साबित हुई है

अनुच्छेद 124 के खंड (5) के तहत संसद। इस संबंध में, संसद

केडेकट

मेंटोरी प्रक्रिया दुर्व्यवहार या इन्कैड मेटाला के प्रमाण के बाद ही शुरू होती है।

खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार शांति, तंत्र, 1

दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और सबूत खोजने के लिए आर के तहत अधिनियमित कानून के प्रावधानों द्वारा पूरी तरह से शासित वैधानिक होने के नाते

हाथ

खंड (5)। यह अनुच्छेद 121 को भी सुसंगत बनाता है। स्थिति यह होगी कि

द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार जांच की गई और साबित पाया गयासंसद को शामिल किए बिना अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद।

उस स्तर तक; किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या असमर्थता पाए जाने पर

उस कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से साबित हुआ, एक प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव

उस आधार पर न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करना होगा

अनुच्छेद 124 (4) के तहत प्रत्येक सदन में प्रस्ताव पेश किया गया; इस तरह से प्रस्ताव पेश किए जाने पर

दुर्व्यवहार या असमर्थता के प्रमाण के बाद और यह प्रस्तुत करने के लिए है

न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को एक संबोधन, [1991] एस. यू. पी. पी. पर प्रतिबंध।

2 - एस. सी. आर

58

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक में प्रस्ताव के परिणाम के आधार पर परिणाम होगा संसद का सदन। यदि, तथापि, खोज यंत्र द्वारा पहुँचा गया है

अधिनियमित कानून में यह प्रावधान है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, मामला

समाप्त हो जाता है और इसके अनुसार प्रस्ताव पेश करने का कोई अवसर नहीं होता है अनुच्छेद 124 (4)।

38. यदि यह स्वीकार किया जाता है कि अनुच्छेद 124 के खंड (4) में शामिल हैं:

खंड के तहत किसी कानून को हटाने और अधिनियमित करने की पूरी शक्ति

(5) केवल सक्षम कर रहा है और अभ्यास पर संवैधानिक सीमा नहीं है

खंड (4) के तहत हटाने की शक्ति के बारे में, तब कुछ अन्य प्रश्न उठते हैं।

विचार के लिए। यदि खंड (5) केवल एक सक्षमकारी प्रावधान है, तो यह (4) में शक्ति के दायरे को कम नहीं कर सकता है और इसलिए,

खंड (4) के तहत संसद के किसी सदन की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है -

खंड (5) के अधीन अधिनियमित मात्र सक्षमकारी विधि जो केवल इसके लिए बनाई जा सकती है -

खंड के तहत कार्य के अभ्यास में सहायता या सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य

(4) . उस स्थिति में, खंड (5) के तहत सक्षम कानून का अधिनियमन।

कानून द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को पार्लिया के दायरे से बाहर नहीं ले जाएगा

खंड (4) के अधीन मन की शक्ति। यह तर्क कि अधिनियमन के बिना

खंड (5) के तहत कानून, दीक्षा के समय से लेकर पूरी प्रक्रिया

राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्तुत करना, जिसमें जांच और

लेकिन खंड (5) के तहत एक कानून के अधिनियमन पर उस क्षेत्र से उत्कीर्ण किया जाता है संसद का क्षेत्र और वैधानिक चरित्र कमजोर प्रतीत होता है।

यदि तर्क सही था, तो खंड (5), केवल एक पर विचार करेगा

आत्म-त्याग।

39. दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अनुच्छेद 124 का खंड (4) शक्ति प्रदान करता है -

यदि मामला इस स्तर पर उसके समक्ष लाया जाता है तो संसद न्यायाधीश को निर्धारित तरीके से साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए कार्य करेगी और उस स्तर तक पहुंचने के लिए संसद से उस उद्देश्य के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने वाले खंड (5) के तहत एक कानून बनाने की अपेक्षा की जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी न्यायाधीश पर आरोप लगाना, पक्ष लेने की पहल, जांच और दुर्व्यवहार या असमर्थता का प्रमाण पूरी तरह से संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा नियंत्रित होता है।

खंड (5) और जब वह चरण पूरा हो जाता है, तो संसद चर्चा में आती है और साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को निर्धारित तरीके से संबोधित करने के लिए पेश किया जाता है। यह मामला इस चरण से पहले संसद के समक्ष नहीं होने का भी अनुच्छेद 121 द्वारा संकेत दिया गया है जो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध को केवल एक प्रस्ताव पेश करने पर हटा देता है। राष्ट्रपति को संबोधित करना जैसा कि बाद में अनुच्छेद 124 (4) में दिया गया है।

सब-कमेटी ऑन जेयूडीएल में बार। उत्तरदायित्व "। यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.]

59

अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर लागू होता है लेकिन कदाचार या अक्षमता की जांच और प्रमाण ऐसी चर्चा को बाहर नहीं कर सकते हैं। यह इंडी बताता है कि जाँच और सबूत के लिए तंत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए

संसद के बाहर और उसके भीतर नहीं। दूसरे शब्दों में, सबूत जिसमें शामिल है। न्यायाधीश के आचरण की चर्चा एक ऐसे निकाय द्वारा की जानी चाहिए जो अनुच्छेद 121 की सीमा से बाहर हो। 'सिद्ध' शब्द हमारी कानूनी प्रणाली में समझे जाने वाले तरीके से सबूत को भी दर्शाता है, यानी न्यायिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप। नीति यह प्रतीत होती है कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के प्रमाण तक का पूरा चरण, जो आरोप लगाए जाने पर जांच शुरू करने से शुरू होता है, अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा शासित होता है और अनुच्छेद 121 में प्रदान किए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, उस तंत्र को संसद के बाहर होना चाहिए न कि उसके भीतर। यदि ऐसा है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि जब तक कदाचार या असमर्थता साबित नहीं हो जाती, तब तक संसद की न तो कोई भूमिका है और न ही अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून में प्रदान किए गए तंत्र पर उसका कोई नियंत्रण है। पार्लियामेंट तस्वीर में तभी आता है जब उस मशीन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई है। अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 स्वयं इंगित करता है कि संसद ने अनुच्छेद 121,124 (4) और 124 (5) की एकीकृत योजना को इस तरह समझा। अधिनियम की सामान्य योजना इस दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अधिनियम में उपयोग की गई कुछ अभिव्यक्तियों, विशेष रूप से धारा 3 और 6 में यह सुझाव दिया गया है कि प्रस्ताव सदन में शुरू किया गया है या जांच के दौरान सदन में लंबित रखा गया है, यदि इस संवैधानिक योजना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मिलान किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है क्योंकि शिकायत पर विचार करने का अधिकार 'अध्यक्ष/अध्यक्ष' है, शिकायत को 'प्रस्ताव' के रूप में लिखा गया है और शिकायत केवल संसद के निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा की जा सकती है। सारतः इसका केवल यह अर्थ है कि केवल निर्दिष्ट संख्या में एम. पी. ही ऐसी शिकायत कर सकते हैं। द कॉम

'अध्यक्ष/सभापति' के समक्ष शिकायत की जानी चाहिए; ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर यदि अध्यक्ष/सभापति यह राय बनाते हैं कि जांच के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला है, तो वह न्यायिक समिति का गठन करेंगे जैसा कि पहले लिखा गया है और यदि निष्कर्ष 'दोषी' है तो अध्यक्ष/चैमन न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार संसदीय कार्यवाही शुरू करते हैं और अनुच्छेद 121 में लगी रोक हटा ली जाती है।

40. यदि यह सही स्थिति है, तो कानून की वैधता अधिनियमित की गई

अनुच्छेद 124 के खंड (5) के तहत संसद द्वारा और उस कानून के अनुसार जांच के समापन तक का चरण पूरी तरह से क़ानून द्वारा शासित होने के कारण न्यायिक समीक्षा के लिए खुला होगा क्योंकि अनुच्छेद 124 (4) के तहत संसदीय प्रक्रिया केवल एक निष्कर्ष दर्ज होने के बाद शुरू होती है कि खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार की गई जांच में कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होती है। इस कारण से यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. पी. पर संसद के अधिकार क्षेत्र की विशिष्टता पर आधारित है।

2 एस सी आर।

60 ,

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच की प्रक्रिया और प्रगतिऔर परिणामस्वरूप मामले में इस न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन

एन.

यह चरण उत्पन्न नहीं होता है। इसी कारण से, "अधिनियम" के तहत जांच समिति के गठन को जन्म देने वाले अध्यक्ष को दिए गए प्रस्ताव पर चूक के सिद्धांत को लागू करने का सवाल भी नहीं उठता है और सदन के लिए किसी भी समय ऐसा कहने का कोई अवसर नहीं हो सकता है। इसलिए, यदि सदन को इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसद की सलाहकार प्रक्रिया अपराध साबित होने के बाद ही शुरू हो सकती है,एक निरर्थक रिट का आगे का सवाल भी नहीं उठता है। यह तर्क कि सदन दोषी पाए जाने के बाद भी निर्णय ले सकता है कि वह नहीं करेगा

} .

19 जेएफएच

एक्र

न्यायाधीश को हटाने के लिए मतदान करने के लिए आगे बढ़ना इस मुद्दे के लिए वैध नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद 124 (4) + 3 के तहत संवैधानिक योजना में ही अनुमत है, इस तथ्य के बावजूद कि क्या अनुच्छेद 124 (5) केवल एक सक्षम प्रावधान है।

या अनुच्छेद के तहत शक्ति के प्रयोग पर एक संवैधानिक सीमा

यूएमपीयूएनजी

40 .0 पारा

124 (4)

' टी विज़ुइडॉर्म

8 पीसी जे

किम बी

-41. यह अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून नहीं है जो कम करता है या

संसदीय प्रक्रिया या विशेष रूप से इसके अधिकार क्षेत्र में कटौती करता है लेकिन कलबंट

स्वयं संवैधानिक योजना जिसने खंड (4) और (5) को अधिनियमित करके समान रूप से संकेत दिया कि खंड (4) के चरण तक पहुँच गया है और प्रक्रिया,

एम.

इसके तहत केवल तभी शुरू होता है जब कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता, खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार साबित होती है।

एती अगर

154

VAGE A

ऊँचा।

ए.

42. तभी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है।

संसद का गठन होता है और इसलिए, अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटा दिया जाता है। में।

संक्षेप में, जब मामला संवैधानिक योजना में संसद प्रोसिना के समक्ष सबसे पहले आता है, तो अनुच्छेद 121 में प्रावधान है कि प्रतिबंध हटा दिया गया है।

टीएएल

दूसरा दृष्टिकोण संसद में चर्चा को सीमित करके कठिनाइयाँ पैदा करता है।

विलाय

एक प्रस्ताव पर जो उसके सामने होगा। कॉन हैविंग विकसित करने का सुझाव

जेक्यू

, डी

उस स्तर पर चर्चा से बचने या प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अध्यक्ष द्वारा अपनाए गए किसी अन्य 1.53 डी. ए. एन. ए. उपकरण द्वारा इसे रोकने का उल्लेख दिखाई नहीं देता है।

एक संतोषजनक समाधान या स्पष्टीकरण हो। कि यह स्पष्ट स्थिति

जिसे बिना प्रदान किए छोड़ दिया जा सकता था और मैदान को एक सम्मेलन के लिए छोड़ दिया जा सकता था। इन प्रावधानों को अत्यधिक सावधानी के साथ लागू करते हुए बाद में विकसित किया गया और

लिखित संविधान में सावधानी बरतने की संभावना बहुत कम है। यह इंगित करता है कि इस क्षेत्र को खुला नहीं छोड़ा गया है, जो इस बात का भी संकेत है कि जिस स्तर पर अनुच्छेद 121 में बाधा को हटाया गया है, वह संसदीय प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। जब दुर्व्यवहार या असमर्थता साबित हो जाती है; आरोप लगाकर प्रक्रिया शुरू करने का चरण, उसका तरीका, जांच और सबूत खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा कवर किए जाते हैं; यदि आरोप साबित नहीं होता है, तो खंड (4) के तहत संसद की अधिकारिता का आह्वान करने की पूर्व शर्त मौजूद नहीं है, जो 1968 अधिनियम की धारा 6 के ऐसा कहने का कारण है; और यदि यह साबित हो जाता है, तो एस. यू. बी.-जे. यू. डी. एल. पर समिति।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.]

61

खंड (4) के तहत प्रक्रिया शुरू होती है, जो प्रदान किए गए परिणाम में समाप्त होती है

बाइट्ज़ीमिट ओल्स।

95 एन. जी. के. एच. 110: एडिलेम "

1 .

एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए। •

• पोलर्वोक, 96 "rudw

वीई

(1) मी. 43. में। संविधान से संबंधित संविधान का भाग-V 1। संघ अनुच्छेद 1124 अध्याय IV में है। संघ न्यायपालिका? जबकि अनुच्छेद 118 और 1: 19

नियम बनाने या विनियमित करने के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित;

- प्रक्रिया और इसके कार्य का संचालन अध्याय 2 "संसद" में है।

(प्रक्रिया शीर्षक के तहत। आम तौर पर जिसमें-अनुच्छेद 121 में भी दरार पाई जाती है। संदर्भ और सेटिंग जिसमें खंड (5) के साथ दिखाई देता है

अनुच्छेद में खंड (4)। 124 इंगित करें-खंड (4) से जुड़ी इसकी प्रकृति

न्यायाधीश के कार्यकाल को कम करने के लिए, खंड (4) का प्रावधान-व्यक्ति

हटाने का अधिकार और खंड (5) हटाने के लिए पूर्व-आवश्यकता,

अनुच्छेद 118,119 और 121 से, जो सभी प्रक्रिया से संबंधित हैं, और

संसद में कार्य संचालन। इसलिए अनुच्छेद 124 (5) लागू नहीं होता है।

प्रक्रिया और संचालन से संबंधित अनुच्छेद 118 के रूप में एक ही क्षेत्र में भोजन किया

संसद में व्यवसाय।

शोर-शराबा करने के लिए मेरी सहायता लें

(2) (1) एन 'एटनी अताउ सेनक्वेक जुल्ट वी

तदनुसार, योजना यह है कि हटाने की पूरी प्रक्रिया में है

और, दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण एक अधिनियमित कानून द्वारा कवर किया जाता है, संसद की भूमिका केवल विधायी है जैसा कि उसके द्वारा अधिनियमित सभी कानूनों में है।

और दूसरा भाग खंड (4) के तहत सबूत के बाद ही संसद में है, कि

प्रक्रिया, केवल अधिनियमित कानून के अनुसार सबूत पर शुरू होती है

खंड (5) के अधीन। इस प्रकार पहला भाग पूरी तरह से वैधानिक है जबकि दूसराकेवल एक हिस्सा संसदीय प्रक्रिया है।

श्रीत को ताऊज़िम डी

2251 एल 44। संविधान ने पहले भाग के लिए एक स्पष्ट प्रावधान का इरादा किया था।पूरी तरह से अधिनियमित कानून द्वारा कवर किया गया है, जिसकी वैधता और वहां की प्रक्रिया

और सबूत के बाद यह एक संसदीय प्रक्रिया होने का इरादा था। यह बात है। एक न्यायाधीश को हटाने के लिए हमारी संवैधानिक योजना में किया गया संश्लेषण।

वाट ']' से #617 562)

6 0915 : यदि हटाने के लिए एक पता प्रस्तुत करने के प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है

अनुच्छेद 121 और 124 (4) 'साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर'

यह अनुमान लगाता है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता पहले ही साबित हो चुकी है।

यह 'जांच और सबूत' अभिव्यक्ति के कारण अधिक है।

खंड (4) के विशिष्ट संदर्भ के साथ खंड (5) में प्रयुक्त। यह इंगित करता है कि

' दुर्व्यवहार या असमर्थता की जांच और प्रमाण खंड के भीतर नहीं है।

सबूत जो पूरी तरह से अधिनियमित कानून द्वारा शासित होना है न कि संसदीय प्रथा जिसे प्रत्येक लोकसभा द्वारा बदला जा सकता है।

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62

45. अभिव्यक्ति से पहले 'सिद्ध' शब्द का महत्व

' अनुच्छेद 124 के खंड (4) में दुर्व्यवहार या असमर्थता का भी संकेत दिया गया है।

जब प्रावधान की तुलना अनुच्छेद 317 के हटाने के प्रावधान के साथ की जाती है

अनुछेद 317क अनुछेद 317 अनुछेद दुर्व्यवहार 'जबकि अनुच्छेद 124 के खंड (4) में, यह' का आधार है

दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई '। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने की प्रक्रिया भी खंड (1) में निर्धारित की गई है।

जो एक संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच का प्रावधान करता है

इस उद्देश्य के लिए। न्यायाधीश के मामले में, जाँच की प्रक्रियाऔर सबूत संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार होना चाहिए।

अनुच्छेद 124 के खंड (5) के तहत। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 317 (1) के तहत दुर्व्यवहार का आधार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होना है।

न्यायालय, एक न्यायाधीश के मामले में जो एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी है,

आधार के न्यायिक निर्धारण की आवश्यकता को फिर से सूचित किया जाता है अनुच्छेद 124 (4) में 'सिद्ध' शब्द को जोड़ना और

अनुच्छेद 124 (5) के तहत इस उद्देश्य के लिए कानून।

46. खंड (5) में 'मे' शब्द का उपयोग इंगित करता है कि 'प्रो' के लिए

पता प्रस्तुत करने के लिए संकेत 'यह एक सक्षम प्रावधान है और

कानून की अनुपस्थिति सामान्य प्रक्रिया या जिसे सदन द्वारा हल किया जाता है

लागू हो सकता है लेकिन 'जांच और प्रमाण अधिनियमित कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना है। खंड (5) में 'मई' शब्द इस दृष्टिकोण के लिए कोई बाधा नहीं है।

47. दूसरी ओर, यदि 'विल' शब्द का उपयोग इसके स्थान पर किया गया था

' हो सकता है कि खंड (5) में यह इंगित किया गया हो कि यह बाध्यकारी था

संसद दुर्व्यवहार या असमर्थता की जांच करने और उसे सही पाए जाने के बाद अपनी प्रक्रिया के मामले में भी कोई विकल्प नहीं छोड़ते हुए ऐसा कानून बनाकर किसी संबोधन को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी विनियमित करेगी। कभी-कभी, विधायिका उस प्राधिकरण के उच्च दर्जे को टालने के लिए "हो सकता है" शब्द का उपयोग करती है जिस पर शक्ति और

दायित्व प्रदान किए जाने और लगाए जाने के लिए अभिप्रेत हैं। (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देखें। जोगिंदर सिंह, [1964] 2 एस. सी. आर. 197 202 पर। वास्तव में, जब कोई प्रावधान किसी अधिकार को प्रभावी बनाने का इरादा रखता है-यहां यह अनुच्छेद 124 (4) के तहत न्यायाधीशों को संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए है-तो अनुच्छेद 124 (5) के रूप में एक प्रावधान जो अन्यथा केवल एन्ना ब्लिंग लग सकता है, अनिवार्य हो जाता है। शक्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। फ्रेडरिक गिल्डर जूलियस बनाम। द राइट रेव. द लॉर्ड बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड; रेव. थॉमस टेलसन कार्टर, [1879-80] 5 ए. सी. 214 पी. 244 , लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा:

" ..... सक्षम करने वाले शब्दों को जब भी अनिवार्य माना जाता है

शक्ति का उद्देश्य एक कानूनी अधिकार को प्रभावी बनाना है। "सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल.

लेखा योग्यता v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 63

पंजाब में सिख नियमित मोटर सेवा, मौधापुरा बनाम। द रे

राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण, रायपुर और अन्र, [1966] 2 एस. सी. आर. 221, इस न्यायालय ने मध्य प्रांत और बरार मोटर वाहन नियम, 1940 में नियम 63 (ए) में 'मई' शब्द का उल्लेख करते हुए कहा:

" ..... अपीलार्थी की ओर से पूर्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था

नियम 63 में दबाव 'मई'। लेकिन संदर्भ और भाषा में

नियम का शब्द 'हो सकता है' हालांकि रूप में अनुमेय होना चाहिए अनिवार्य माना जाता है। नियम 63 के तहत पुनः अनुदान देने की शक्ति

काउंटर का नया-वर्तमान में परमिट पर हस्ताक्षर

मामला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बिलासपुर को सौंपा गया है।

नवीकरण की ऐसी शक्ति का प्रयोग इस पर निर्भर नहीं करता है कि

ऐसे मामले जिनमें से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है। सक्षम करने वाले शब्द हैं अनिवार्य के रूप में समझा जाता है जब भी शक्ति का उद्देश्य है

कानूनी अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए '। (देखिए: जूलियस वी। ऑक्सफोर्ड के बिशप, 5

ए. सी. 214,244) "।

यदि अनुच्छेद 124 (5) में 'मई' शब्द का कोई अन्य अर्थ दिया गया है कि

उप-अनुच्छेद स्वयं को, संसद द्वारा माना जाने वाला, अत्यधिक अनावश्यक, अनावश्यक और अप्रासंगिक बना देगा। अनुच्छेद 124 (4) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति अन्यथा सदन को भी उपलब्ध हो सकती है। अनुच्छेद 124 (5) के तहत परिकल्पित कानून ऐसा कानून नहीं है, बल्कि ऐसा कानून है जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए संवैधानिक नीति और तंत्र के दर्शन को प्रभावी बनाएगा।

इसलिए, 'मे' शब्द का उपयोग आवश्यक रूप से इंगित नहीं करता है।

कि पूरा खंड (5) एक सक्षम प्रावधान है जो यह तय करने के लिए संसद पर छोड़ देता है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण के लिए भी कोई कानून बनाना है या नहीं।

केवल यह तथ्य कि खंड (5) खंड (4) का भाग नहीं है।

स्वयं, जैसा कि एक स्तर पर माना जाता है जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, वर्ग (5) के महत्व या विषय को कम नहीं करता है। यह संभावना है कि संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से सीमाओं का सीमांकन करने के बारे में सोचा और इसलिए, संकेत दिया कि अक्षमता के दुर्व्यवहार के प्रमाण के स्तर तक यह क्षेत्र संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून द्वारा कवर किया गया है, पहला भाग खंड (5) द्वारा और दूसरा खंड (4) द्वारा केवल इस अंतर के साथ कवर किया गया है कि संसद को दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने के बाद संबोधन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी विनियमित करने का विकल्प दिया गया था ताकि इस उद्देश्य के लिए एक कानून बनाकर इसे अधिक निश्चित और सुसंगत बनाया जा सके।

.

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

64

48. इसी तरह, इनवेस की प्रक्रिया को इंगित करने के लिए 'गति' शब्द का उपयोग

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में अभियोग और सबूत क्योंकि'अध्यक्ष' के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव धारा 6 में उस अभिव्यक्ति के उपयोग के बावजूद इसे 'सदन में प्रस्ताव' नहीं बनाते हैं। अन्यथा,

धारा 6 यह नहीं कहेगी कि एक के मामले में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाना है 'दोषी नहीं' का पता लगाना। इसका मतलब केवल यह है कि जब आरोप नहीं है

साबित हुआ कि अध्यक्ष को खंड (4) के तहत प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता नहीं है जो केवल साबित होने की स्थिति में शुरू की जाती है। इसलिए, अध्यक्ष को इस अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण चुना गया है क्योंकि आगे की प्रक्रिया संसदीय है और ऐसी शिकायत करने का अधिकार उन्हें दिया गया है -

संसद के सदस्य। इसके अलावा, अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमन अनुच्छेद 124 (5) के दायरे को निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं हो सकता है।

यदि अनुच्छेद 118,121 के बीच अंतर-संबंध का यह निर्माण,

124 (4) और 124 (5) उन पर रखे जाने के लिए उचित है, जैसा कि वास्तव में हम

तो, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के प्रावधानों के साथ गड़बड़ नहीं करते हैं

संवैधानिक योजना।

49. अनुच्छेद 124 (5) के तहत कानून के दायरे में, विनियमन का विचार

(i) पता प्रस्तुत करने की प्रक्रिया; (ii) व्याख्या के दो संभावित विकल्पों को स्वीकार करने के लिए दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण। "अभिभाषण प्रस्तुत करने" का विचार संसद के दोनों सदनों द्वारा संबोधन की वास्तविक प्रस्तुति तक सीमित हो सकता है; या प्रस्ताव द्वारा आरंभ होने से लेकर पूरी प्रक्रिया को शामिल करने के लिए आयोजित किया जा सकता है।

पता देने के अंतिम कार्य तक घर। यदि पहला दृष्टिकोण सही है तो अनुच्छेद 124 (5) के तहत कानून जांच के चरण में लागू होगा।

दुर्व्यवहार या असमर्थता का प्रमाण और प्रस्ताव के बाद संबोधन प्रस्तुत करने के अंतिम चरण में दोनों सदनों द्वारा अपनाया जाता है। प्रस्ताव और सदन द्वारा इसका विचार और अनुमोदन इस तरह के कानून के दायरे से बाहर होगा और इसे अनुच्छेद 118 के तहत बनाई गई प्रक्रिया के नियम द्वारा विनियमित किया

जाएगा। यह दृश्य बहुत संकीर्ण है। अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए सदन की प्रक्रिया के नियमों को लाकर यह अनिश्चितता के एक तत्व का परिचय देता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

50. दूसरा दृष्टिकोण पसंद किया जाना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया को सक्षम बनाता है

हटाने को संसद के एक कानून द्वारा विनियमित किया जा रहा है-एकरूपता सुनिश्चित करता है और मनमानेपन की संभावना को कम करता है। अनुच्छेद 118 एक सामान्य प्रावधान है जो संसद के प्रत्येक सदन को अपने स्वयं के नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रक्रिया। ये नियम सदन के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और इन्हें बदला जा सकता है: किसी भी समय घर। इस तरह के नियमों का उल्लंघन एक अनियमितता है और अनुच्छेद 122 को देखते हुए न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।

51. अनुच्छेद 124 (5) एक विशेष प्रावधान की प्रकृति है जिसका उद्देश्य है -

अनुच्छेद 124 (4) के तहत एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करता है जो जे. यू. डी. एल. पर उप-समिति है।

उत्तरदायित्व "। यू. ओ. 1. [बी. सी. रे, जे. जे. 65

यह सदन के सामान्य कार्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि विशेष कार्य की प्रकृति का है। इसमें न्यायाधीश को हटाने से संबंधित पूरा क्षेत्र शामिल है। अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियम इस क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं।

इसलिए, विशेष रूप से यह निर्धारित करना आवश्यक था कि अनुच्छेद 119 के तहत बनाया गया कानून अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए प्रक्रिया के नियमों पर प्रबल होगा। चूँकि अनुच्छेद 118 और 124 (5) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इसलिए अनुच्छेद 119 में निहित इस तरह का प्रावधान आवश्यक नहीं था और यहां तक कि इस तरह के प्रावधान के अभाव में, अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाया गया कानून अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा और संसद के दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी होगा। इस तरह के कानून का उल्लंघन अवैध होगा और अनुच्छेद 122 (1) के तहत न्यायिक जांच से मुक्त नहीं हो सकता है।

53. वास्तव में, यह अधिनियम हटाने की प्रक्रिया के न्यायिक और राजनीतिक दोनों तत्वों के संवैधानिक दर्शन को दर्शाता है। अंतिम।प्राधिकरण इस अर्थ में संसद के पास रहता है कि भले ही जांच के लिए समिति एक निष्कर्ष दर्ज करती है कि न्यायाधीश आरोपों के लिए दोषी है, फिर भी संसद को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत नहीं करने का निर्णय लेने के लिए खुला है। लेकिन अगर समिति यह निष्कर्ष दर्ज करती है कि न्यायाधीश दोषी नहीं है, तो फिर से कार्रवाई की प्रक्रिया में राजनीतिक तत्व के पास कोई और विकल्प नहीं है। यह कानून वास्तव में न्यायाधीशों की जवाबदेही की अवधारणा और न्यायिक स्वतंत्रता के मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला एक सभ्य कानून है।

54. वास्तव में, न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में डॉ. एल. एम. सिंघवी का असहमतिपूर्ण नोट तीखा है।

बहुमत की रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्मरणीय है कि 1964 के विधेयक ने हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति निहित की थी

कार्यकारी। यह न्यायिक स्वतंत्रता के विचार के साथ आपत्तिजनक और असंगत पाया गया। हालांकि, प्राधिकरण की प्रकृति के बारे में, जो जांच करने की शक्ति का भंडार था, असहमत राय, आवश्यक निहितार्थ से, बहुमत के दृष्टिकोण पर जोर देती है जो अंततः कानून बन जाता है। डॉ. सिंघवी अपनी असहमति में कहते हैं:

" 10. वर्तमान विधेयक केवल एक समिति के नामकरण में पहने हुए न्यायाधिकरण के तौर-तरीके प्रदान करने का प्रयास करता है। विधेयक में विचार की गई समिति को संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अर्थ के भीतर एक त्रिकोणीय या "प्राधिकरण" माना जा सकता है, जो अपने काम को न्यायिक समीक्षा और पर्यवेक्षण के अधीन करता है। इसके अलावा, संसद की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] के मामले और प्रक्रिया में संसद के पास कोई विकल्प नहीं बचा है।

2 एस सी आर।

66

टेरी समिति को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ मैं नहीं हूँ

सहमति में।

11. इन दोनों मामलों में जिनके संबंध में मैंने संयुक्त चयन समिति में अपने सम्मानित सहयोगियों से असहमति जताई है, अब निष्क्रिय बर्मी संविधान के विधेयक के प्रावधानों पर एक छाप दिखाई देती है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि इस तरह के प्रस्ताव की सूचना पर किसी भी सदन की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और आगे यह कि आरोप की जांच एक विशेष न्यायाधिकरण (बर्मी संविधान की धारा 143) द्वारा की जाएगी। बर्मी मामले में, विशेष न्यायाधिकरण में प्रेसी डेंट या उनके नामित व्यक्ति और चैंबर ऑफ नेशनलिटीज और चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष शामिल होने थे। मुझे लगता है कि बुर मेस एनालॉग न तो प्रेरणादायक है और न ही शिक्षाप्रद है, और अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की अधिक विकसित प्रक्रियाएं जो सदियों से आजमाई और परखी गई हैं, वे आगे बढ़ेंगी।

हमारी बेहतर सेवा की है।

55. इसलिए, विवाद बी, सी और डी पर हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं

इसके अंतर्गत:प्रस्ताव को स्वीकार करने तक न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया, समिति का गठन और समिति द्वारा निष्कर्षों को दर्ज करना, सख्ती से, संसद के सदनों में कार्यवाही नहीं है। अध्यक्ष अधिनियम के तहत एक सांविधिक प्राधिकारी है। इस बिंदु तक मामले को न्यायालय के न्यायशास्त्र के बाहर नहीं कहा जा सकता है। विषय-वस्तु बी का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाए गए कानून के अनुसार कदाचार का पूर्व प्रमाण संसद में एक न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने के खिलाफ अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटाने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

अनुच्छेद 124 (4) वास्तव में केवल इसके तहत बनाए गए कानून के साथ ही सार्थक हो जाता है।

अनुच्छेद 124 (5)। इस तरह के कानून के बिना एक न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक योजना और प्रक्रिया अनिश्चित रहती है। सामग्री सी का उत्तर एसी दिया गया है

- कॉर्डलिंगली।

अध्यक्ष एक प्रस्ताव स्वीकार करते हुए और एक समिति का गठन करते हुए

दुर्व्यवहार या अक्षमता के कथित आधारों की जांच करना सदन के हिस्से के रूप में कार्य करें। सदन इस स्तर पर तस्वीर में नहीं आता है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधान असंवैधानिक नहीं हैं।

सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों को कम करने के रूप में। न्यायाधीशों(जाँच) अधिनियम, 1968 संवैधानिक है और अधिकार के भीतर है। सामग्री डी है

तदनुसार निपटाया जाता है।

सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.] 67

आरई: सामग्री (ई)

56. श्री सिब्बल ने आग्रह किया है कि गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए

अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्ताव के प्रवेश से प्रवाहित होने वाले उद्धरण और

जाँच के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय, यह बाध्यकारी है

अध्यक्ष न्यायाधीश को पहले सुनवाई का अवसर देने के लिए

ऐसा निर्णय लिया जाता है। यह आग्रह किया जाता है कि इस तरह का निर्णय महत्वपूर्ण हैन्यायाधीश और समग्र रूप से न्यायिक प्रणाली दोनों से संबंधित है और

कि एक न्यायाधीश को घेरने के लिए कोई भी राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम केवल नहीं होगा

स्वयं न्यायाधीश को प्रभावित करता है लेकिन प्रशासन की पूरी प्रणाली को भी प्रभावित करता है

न्याय। यदि कोई प्रस्ताव संपार्श्विक और तिरछे उद्देश्यों के साथ लाया जाता है, तो यह

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को बहुत आगे बढ़ाएगा,

1968 यदि संबंधित न्यायाधीश को स्वयं को स्वीकार करने के निर्णय से पहले सुना जाता है

प्रस्ताव जिसका परिणाम जहां तक न्यायाधीश का अधिकार है, टूट जाता है

लिया जाता है। प्राकृतिक न्याय की न्यूनतम आवश्यकताएँ, उपयुक्त

विद्वान वकील का कहना है कि इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के पास एक

सुनने का अवसर।

57. इसके विपरीत श्री जेठमलानी ने तर्क दिया कि यह होगा

अत्यधिक अनुचित है कि अध्यक्ष को एक न्यायाधीश को नोटिस जारी करना चाहिए और

उन्हें अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहें। इसके अलावा, श्री जेठमलानी कार्यवाही के उस चरण में कहा गया जहां अध्यक्ष केवल निर्णय लेता है

यह कहा जा सकता है कि मामले की जांच हो सकती है कि अधिकारों, हितों या वैध अपेक्षाओं को प्रभावित करने वाले कोई भी निर्णय नहीं लिए गए हैं। श्री.

जेठमलानी ने यह इंगित करने की कोशिश की कि इन कार्यवाही की बराबरी नहीं की जा सकती हैअनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही के साथ। अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं लेते हैं।

उस स्तर पर न्यायाधीश के खिलाफ बात।

ऐसी प्रारंभिक कार्यवाहियों की प्रकृति और उद्देश्य का उल्लेख करते हुए

कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम (वॉल्यूम। 48 ए) कहता है:

" एक सामान्य नियम के रूप में, अनुशासनात्मक या हटाने की कार्यवाही संबंधित होती है

न्यायाधीशों के लिए सुइ जेनरिस हैं और सिविल या आपराधिक नहीं हैं।

प्रकृति; और उनका उद्देश्य न्यायिक आचरण की जांच करना है और

जिससे न्यायिक योग्यता के मानकों को बनाए रखा जा सके।

[p.614]

जिस स्तर पर नोटिस और अवसर की आवश्यकता है

कानून के कथन की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश हैं:

" सामान्य नियम यह है कि न्यायाधीश के समक्ष अनुशासित किया जा सकता है, जैसे -हटाने से, वह नोटिस और एक अवसर का हकदार है

बचाव भले ही ऐसा कोई क़ानून नहीं है जिसकी आवश्यकता हो। आम तौर पर,

1 [1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

68

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बचाव के अधिकार का प्रयोग मुकदमे या सुनवाई में किया जाता है, जैसा कि माना जाता हैइन्फ्रा 51। विशेष रूप से न्यायाधीश नोटिस देने का हकदार है।

उसके खिलाफ विशेष आरोप। इसके अलावा, नोटिस शुल्क समय से पहले पर्याप्त रूप से दिया जाना चाहिए

एक प्रदर्शन की उचित तैयारी की अनुमति देने के लिए एक बचाव प्रस्तुत करना

विपक्ष में "।

(पीपी। 613-614)

लेकिन इस स्थिति को नकारते हुए कि न्यायाधीश का कोई अधिकार नहीं होगा

प्रारंभिक चरण में भी यह कहा गया है:

औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रारंभिक के रूप में व्यक्तिगत आचरणिंग्स।

न्यायपालिका आयोग मामलों की जांच कर सकता है।

औपचारिक अनुशासन के प्रारंभिक रूप में न्यायिक आचरण से संबंधित

गैर कार्यवाही, और एक अदालत, अपनी सामान्य शक्तियों के तहत कर सकते हैं निचली अदालतों में, अध्यक्षता करने के लिए एक विशेष आयुक्त नियुक्त करें

प्रारंभिक जाँच। एक अदालत का नियम प्रदान करता है कि एदुराचार के आरोप में न्यायाधीश को उचित सजा दी जानी चाहिए।

प्रारंभिक जाँच के दौरान प्रस्तुत करने का अवसर

ऐसे मामले जो वह चुन सकता है, उसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है

जो संवैधानिक प्रावधानों द्वारा आवश्यक है "।

[पी। 615]

58. स्थिति यह है कि प्रावधानों के स्तर पर जब

अध्यक्ष न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, एक न्यायाधीश, अधिकार के मामले के रूप में, इस तरह के नोटिस का हकदार नहीं है। कानून की योजना और आवश्यक निहितार्थ द्वारा उसके तहत बनाए गए नियम, ऐसे अधिकार को बाहर करते हैं। लेकिन यह अध्यक्ष को रोक नहीं सकता है, अगर उनके सामने रखे गए तथ्य और साक्षय इंगित करते हैं कि न्यायाधीश की सुनवाई स्वयं अनुचित नहीं हो सकती है, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार करने और बिना सहमति के जांच के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय ऐसा अवसर अपने आप में और केवल इसी कारण से निर्णय को दूषित नहीं करता है। सामग्री ई को तदनुसार निपटाया जाता है।

आरई: सामग्री (एफ)

59. विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इस विवाद का सार

याचिकाकर्ता के वकील, "उप-समिति" ने श्री आर. के. गर्ग द्वारा विशेष जोर देते हुए तर्क दिया कि एक न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक तंत्र केवल न्यायिक दुर्व्यवहार के लिए एक राजनीतिक उपाय है।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.]

69

और न्यायिक अखंडता सुनिश्चित करने और लागू करने के लिए वादियों के लिए उपलब्ध न्यायिक उपचार को बाहर नहीं करता है। यह आग्रह किया जाता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और यह अपने दायरे में, जैसा कि इसमें विरासत में मिला है, त्रुटिहीन अंतरंगता और चरित्र वाले व्यक्तियों के साथ एक निष्पक्ष न्यायपालिका का अधिकार है। इसके बिना अदालत में जाने का मौलिक अधिकार ही बंजर और खोखला हो जाता है। यह आग्रह किया जाता है कि न्यायालय के पास स्वयं अधिकार क्षेत्र है

नहीं ए

-

इसे बनाने वाले सदस्यों की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना और किसी भी ऐसे सदस्य को रोकना जिसका उन आवश्यक संबंधों और उपलब्धियों में अभाव पाया जाता है जिन पर जनता का विश्वास बनाया जाता है।

यह सच है कि समाज को उच्चतम और सबसे अधिक अपेक्षा करने का अधिकार है।

न्यायिक आचरण में औचित्य के सटीक मानक। कोई भी आचरण जो दक्षता अखंडता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कम करता है

न्यायालय का कार्य वास्तव में वर्जित है। इन कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम (वॉल्यूम। 48 ए) न्यायाधीशों के आचरण, अक्षमताओं और विशेषाधिकारों के मानकों का उल्लेख करते हुए, यह देखा जाता है:

" जो राज्य न्यायिक कार्यालय का निर्माण करता है, वह उपयुक्त पद निर्धारित कर सकता है।

उस पद को धारण करने वाले न्यायाधीश के लिए आचरण के मानक, और

कई क्षेत्राधिकार, व्यक्त या निहित के भीतर कार्य करने वाले न्यायालय शक्तियों ने कुछ नियमों या संहिताओं को अपनाया है या उनका पालन किया है

न्यायिक आचरण। मामलों में किसी विशेष न्यायालय की शक्ति

नैतिक पर्यवेक्षण और मानकों का रखरखाव

न्यायपालिका अनन्य हो सकती है।

न्यायिक आचरण के लिए दिशानिर्देश दोनों संहिताओं में पाए जाते हैं

न्यायिक आचरण और सामान्य रूप से नैतिक और नैतिक मानक

समुदाय द्वारा न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है। तोपें या कोड सामान्य सिद्धांतों की सेटिंग के एक बयान के रूप में अभिप्रेत हैं।

न्यायाधीशों के लिए आचरण का एक संपूर्ण मानक जो

ऐसा आचरण निर्धारित करें जो मैलम के विपरीत मैलम हो। निषेध वे उन सामान्य राजकुमारों को फिर से स्थापित करने के लिए काम करते हैं

जिन्होंने हमेशा न्यायिक आचरण को नियंत्रित किया है।

हालाँकि इन नियमों को न्यायाधीशों के लिए बाध्यकारी माना गया है।

और कानून का बल हो सकता है जहां द्वारा घोषित किया गया हैविधायी रूप से अधिनियमित या न्यायिक रूप से अपनाए गए न्यायालयों को छोड़कर

उनके पास स्वयं कानून की शक्ति और प्रभाव नहीं है।

[पीपी। 593-594]

निर्धारित आचरण की प्रकृति पर यह कहा गया है:

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. 2 एस सी आर।

70

उनके न्यायिक कार्यालय के लिए सार्वजनिक सम्मान।सामान्य दिशानिर्देशों और नियमों के तहत यह एक बुनियादी आवश्यकता है।

न्यायिक आचरण का, कि एक न्यायाधीश का आधिकारिक आचरण स्वतंत्र हो

अनुचितता और अनुचितता की उपस्थिति से और वहउसका आधिकारिक और व्यक्तिगत व्यवहार दोनों के अनुसार होना चाहिए

उच्चतम मानक वाला समाज उम्मीद कर सकता है। कोन का मानक

नली आम लोगों की अपेक्षा से अधिक होती है और उससे भी अधिक होती है।जो वकीलों से अपेक्षित है। अंतिम मानक होना चाहिए

आयोजित किया जाता है जो लगातार उच्च स्तर के लिए फिटनेस की पुष्टि करता है

न्यायिक कार्यालय और न्यायाधीशों की प्रायोजकताओं को इतना आरामदायक होना चाहिए

स्वयं न्याय के प्रशासन को सम्मानित करने के लिए और

जनता के विश्वास और सम्मान की सेवा करें। यह महत्वहीन है।

कि आपत्तिजनक माना जाने वाला आचरण संभवत: विधिसम्मत है

यह गैर-न्यायिक माना जाता है या इसे लो-ह्यूमर हॉर्सप्ले के रूप में माना जाता है।

विशेष रूप से, एक न्यायाधीश को एसी में भाग लेने से बचना चाहिए।

ऐसे समुदाय जो उनके न्यायपालिका के प्रति सार्वजनिक सम्मान को कम कर सकते हैंपद संभालें और ऐसे आचरण से बचें जो उचित हो सकता है

जीवन भर एक न्यायाधीश को ईमानदारी और औचित्य के मानकों का पालन करना चाहिए। दूसरों के लिए स्वीकार्य माने जाने वाले लोगों की तुलना में अधिक। जबकि एक न्यायाधीश

नियंत्रण पर अपने व्यक्तिगत विचारों का मनोरंजन करने का अधिकार है

वैकल्पिक मुद्दे और अपने अधिकारों को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है या

एक नागरिक के रूप में राय-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र संगठन का उनका अधिकार

यह समय-समय पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों द्वारा सीमित होता है और वह

सार्वजनिक रूप से शामिल होने से बचने के लिए सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए

विवाद "।

[पीपी। 594-596]

संपत कुमार और ओआरएस में। वी. भारत संघ और अन्य। [1985] 4 एस. सी.

458 , प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों की योग्यताओं, उपलब्धियों और उपलब्धियों से संबंधित, जिनका उद्देश्य उच्च न्यायालयों के अधीन करना था, इस न्यायालय ने न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक गुणों पर जोर दिया।

60. लेकिन हम इस प्रस्ताव से डरते हैं कि संविधान के अलावा

एक न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रीय तंत्र, न्यायपालिका के पास स्वयं न्यायशास्त्र है और उचित मामलों में अपने सदस्यों में से एक की अखंडता की जांच करने और न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने से रोकने का कर्तव्य गंभीर जोखिमों से घिरा हुआ है। अदालत तब वास्तव में एक न्यायाधीश को हटाने के लिए एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करेगी। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले विद्वान वकील 1

सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.) 71

उन्होंने कहा कि किसी न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने से रोकने का प्रभाव हटाने के बराबर नहीं है क्योंकि न्यायाधीश की सेवा की शर्तों जैसे वेतन आदि को बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि सामान्य प्रस्ताव कि अदालत के पास स्वयं ऐसा अधिकार क्षेत्र है, अस्वीकार्य है। यह अधिक समस्याओं के लिए उत्पादक है तो यह हल करने की उम्मीद कर सकता है।

61. न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों के निर्वहन से रोकने के निर्देश से राहत नहीं दी जा सकती है। यह एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों सहित पूरी संवैधानिक योजना है जिसे इस पहलू पर विचार करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना है। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अनुच्छेद 121 के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में निहित इस उद्देश्य के लिए संवैधानिक योजना के समानांतर चलने वाले किसी भी व्यक्ति में कोई अधिकार हो सकता है। कोई भी प्राधिकारी वह नहीं कर सकता जो संविधान आवश्यक निहितार्थ से मना करता है। समान रूप से, यह ऐसे मामले में अंतरिम राहत

के सवाल पर भी प्रकाश डालता है जो न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत प्रक्रिया की शुरुआत पर न्यायाधीश को न्यायिक रूप से काम करने से रोकने का परिणाम है। संवैधानिक योजना यह प्रतीत होती है कि जब तक अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून के प्रावधानों के अनुसार कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता 'साबित' नहीं होती है और अनुच्छेद 121 में निहित प्रतिबंध के कारण न्यायाधीश को हटाने के लिए एक संबोधन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं किया जाता है, तब तक संसद में भी न्यायाधीश के आचरण के बारे में चर्चा नहीं हो सकती है, जिसके पास अनुच्छेद 124 (4) के तहत हटाने की पर्याप्त शक्ति है। यदि इसलिए संवैधानिक योजना यह है कि न्यायाधीश के आचरण पर संसद में भी चर्चा नहीं की जा सकती है, जिसे हटाने की पर्याप्त शक्ति दी गई है, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित कानून के अनुसार कथित कदाचार या अक्षमता 'साबित' नहीं हो जाती है, तो यह स्वीकार करना मुश्किल है कि न्यायाधीश के आचरण की ऐसी कोई चर्चा या इसकी योग्यता के बारे में कोई मूल्यांकन या निष्कर्ष इस उद्देश्य के लिए क़ानून के तहत गठित जांच समिति के समक्ष अभियोग के दौरान के अलावा कानून के अनुसार कहीं और अनुमत है। इसलिए, संकेत यह है कि कथित दुर्व्यवहार या असमर्थता की जांच के चरण के दौरान इस तरह के अंतरिम निर्देश को हमारी संवैधानिक योजना के लिए अलग नहीं माना जाता है।

62. हालाँकि, औचित्य का सवाल वैधता से अलग है। लोक सेवा आयोग के सदस्य के मामले में अनुच्छेद 317 (2) जैसे कानूनी प्रावधान का अभाव, इस तरह की जांच का सामना कर रहे न्यायाधीश को जांच के परिणाम को लंबित रखते हुए न्यायिक कार्यों का निर्वहन जारी रखने या अनुच्छेद 124 (4) के तहत हटाने की प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी दुर्भावना या अक्षमता साबित होने की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए, आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं देता है कि न्यायाधीश उस अवधि के दौरान कार्य करना जारी रखेंगे। उस क्षेत्र को [1991] एस. यू. पी. पी. द्वारा कवर किया जाना है।

2 एस सी आर।

72

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं विद्वान न्यायाधीश की औचित्य की भावना और न्यायिक परंपरा

भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारों का प्रतीक। यह पूर्व होना चाहिए

ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया जाएगा

स्वयं न्यायपालिका के निर्वहन से दूर रहने के लिए औचित्य के कार्य के रूप में निर्णय लेता है गर्भावस्था के दौरान कार्य करता है। चूँकि विद्वान न्यायाधीश जारी रहेंगे

एक न्यायाधीश का पद धारण करने के लिए जब तक कि वह इस्तीफा नहीं देता है या हटा दिया जाता है, एक व्यवस्था

स्थिति से निपटने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा योजना तैयार की जानी चाहिए। द.

संविधान में जनता के किसी सदस्य के निलंबन का प्रावधान करते हुए

सेवा आयोग ने अनुच्छेद 317 (2) में इसी तरह की स्थिति में विचार-विमर्श किया है।

राष्ट्रीय पदाधिकारी, अर्थात्, वरिष्ठ न्यायाधीश और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महाभियोग का सामना कर रहे भारत के राष्ट्रपति। यह मान लेना उचित है कि

संविधान निर्माताओं ने मान लिया था कि एक वांछनीय सम्मेलन होगा

उस स्थिति में एक न्यायाधीश द्वारा अनुसरण किया जाएगा जिसकी आवश्यकता नहीं होगी

निलंबन की शक्ति का प्रयोग। वांछनीय पाठ्यक्रम के स्वामित्व को इस परिप्रेक्षय में देखा जाना चाहिए। यह मान लेना भी उचित होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऐसी स्थिति में एक वांछनीय समाधान खोजने की उम्मीद की जाती है ताकि विद्वान न्यायाधीश और संस्थान को इस तरह से शर्मिंदगी से बचाया जा सके जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल हो और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह विचार हो कि विद्वान न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 124 (4) के तहत अंतिम परिणाम तक न्यायिक कार्य से दूर रहना वांछनीय है, तो वह तदनुसार विद्वान न्यायाधीश को सलाह देंगे। यह मान लेना और भी उचित है कि संबंधित विद्वान न्यायाधीश आम तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह का पालन करेंगे। हालाँकि, यह सब औचित्य के क्षेत्र में है और किसी भी अदालत को इस उद्देश्य के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोई कानूनी निर्देश जारी करने की अनुमति देने के लिए कानूनी प्राधिकरण का मामला नहीं है। तदनुसार सामग्री एफ को अस्वीकार कर दिया जाता है।

आरई: सामग्री (जी)

63. यह अध्यक्ष के खिलाफ कथित दुर्भावना से संबंधित है। द.

राज बीरबल और शाम रतन खंडेलवाई दोनों की याचिकाओं में इस संबंध में कथन समान हैं। हम प्रासंगिक कथनों को देख सकते हैं:

“ इसलिए, यह ध्यान देने योग्य है कि अध्यक्ष ने कार्रवाई की

संवैधानिक प्रथा के विपरीत। यह माना जाता है कि इस उच्च

संवैधानिक पदाधिकारी को कुएँ के बारे में पता होता

तथ्य के संबंध में स्थापित और स्थापित संवैधानिक अभ्यास वे प्रस्ताव सदन के विघटन के साथ समाप्त हो जाते हैं। एसी।

अध्यक्ष का, इसलिए, प्रस्ताव को स्वीकार करने में

जिस तरह से उन्होंने ऐसा किया, उससे दुर्भावना की गंध आती है और इसलिए, डी एमआईटीटी ऑन जूडी। अकौंटेबिलिटी v.

यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे. जे. 73

गिराए जाने की सेवा करता है।

अध्यक्ष की कार्रवाई एक और मामले में दुर्भावनापूर्ण है। अध्यक्ष ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है

याचिकाकर्ताओं का वास्तव में मानना है कि प्रस्ताव पर पहले हस्ताक्षरकर्ता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह हैं जो जनता दल के नेता भी हैं। याचिकाकर्ताओं का वास्तव में मानना है कि उक्त प्रस्ताव के संकेत ज्यादातर जनता दल के हैं, हालांकि इस तथ्य का विवरण याचिकाकर्ताओं को ठीक से पता नहीं है। अध्यक्ष को, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, संसद को इस मामले को देखने और इस बात पर चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिए थी कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। विभिन्न सदनों से संबंधित संसद सदस्यों के विचारों का पता लगाने के लिए अध्यक्ष को कम से कम सदन में प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था। अध्यक्ष को, कम से कम कहने के लिए, सभी सामग्री न्यायमूर्ति रामास्वामी को प्रेषित करनी चाहिए थी और उनसे जवाब मांगना चाहिए थाप्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रयास करने से पहले। अध्यक्ष को प्रस्ताव पर बहुत पहले विचार करना चाहिए था और न्यायमूर्ति रामास्वामी को उन सभी सामग्रियों के साथ-साथ उन विचारों को प्रेषित करना चाहिए थे जो उनके वाणिज्य दूतावासों के दौरान उन्हें व्यक्त किए गए थे, जिससे वे निर्णय पर पहुँच सके। अध्यक्ष को कम से कम इस संबंध में सदन की इच्छाओं को सुनिश्चित करना चाहिए था। अध्यक्ष को 9वीं लोकसभा की अंतिम शाम को हंगामे और हंगामे के बीच प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला नहीं करना चाहिए था, जब उन्होंने जो कहा वह भी सदन में पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा था। अध्यक्ष एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उन्हें इस उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के पद की उच्चतम परंपराओं में अपने कार्यों का प्रयोग करना चाहिए था। अध्यक्ष को प्रस्ताव पर भी विचार नहीं करना चाहिए था, जिसके प्रमुख प्रस्तावक उनकी ही पार्टी के सदस्य हैं। अध्यक्ष को इस संबंध में उन्हें अयोग्य घोषित कर देना चाहिए था और मामले को सदन की चर्चा के लिए रखना चाहिए था। इस पूरे प्रकरण में अध्यक्ष का आचरण एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के लिए अशोभनीय था। अध्यक्ष की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए

अकेले इस गिनती पर।"

दुर्भावना के बारे में कथन कुछ संवैधानिक मुद्दों के गुणों के साथ मिश्रित और अविभाज्य हैं। वास्तव में, अध्यक्ष के समक्ष इस आधार पर दुर्भावना का आरोप लगाया जाना चाहिए कि उन्होंने [1991] एस. यू. पी. पी. किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74 न्यायाधीश को नहीं सुना, प्रस्ताव पर सदन में चर्चा नहीं की गई आदि।

हम मानते हैं कि ये आवश्यक नहीं थे।

1

64. लेकिन एक बात कही गई कि अध्यक्ष ने ए. पी. में प्रवेश नहीं किया

शपथ पर इन आरोपों से इनकार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए माना जाना चाहिए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका में लगाए गए आरोपों और दुर्भावनापूर्ण दलीलों पर भी, जिन्हें मजबूत आधारों पर स्थापित करने की आवश्यकता है, ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। दुर्भावनापूर्ण मामला केवल अध्यक्ष की राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भी नहीं बनाया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में यह पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। सभी घटनाओं में, मामले से निपटने के लिए एकमात्र वैधानिक प्राधिकरण के रूप में, वैधानिक अपवाद या आवश्यकता के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। सामग्री जी को पहले स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आरई: सामग्री (एच)

65. यह उप-समिति के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

न्यायिक जवाबदेही "और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यवाही को मुख्य बनाने के लिए। यदि यह सच है, तो 1991 की स्थानांतरण याचिका संख्या 278 और अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देने वाली अन्य रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के पास भी मुकदमा करने के लिए आवश्यक स्थिति नहीं होगी। जनहित की कार्रवाइयों में मुकदमा करने के लिए खड़े होने के बारे में कानून में पिछले कुछ वर्षों में भारी बदलाव आया था और लोकस स्टैंडी निर्धारित करने के लिए उदार मानकों को अब मान्यता दी गई है। एस. पी. गुप्ता और अन्य में इस मामले पर काफी सावधानी और विस्तार से चर्चा की गई है। आदि वी। भारत संघ और अन्य। आदि। ; [1982] 2 एससीआर 365। वर्तमान मामला इस तरह का और संवैधानिक हैऐसी प्रकृति और महत्व के मुद्दे कि यह नहीं कहा जा सकता है कि बार के सदस्यों और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। सिद्धांतों और पूर्वजों का एक बार फिर से विस्तृत पुनर्मूल्यांकन अनावश्यक है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि किसी भी दृष्टिकोण से याचिकाकर्ता मुकदमा करने के लिए स्थिति के कानूनी उपकरणों को संतुष्ट करते हैं। इसलिए हम आशय एच को अस्वीकार करते हैं।

66. हम यह कहने के लिए विवश हैं कि कुछ प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ीं

विद्वत न्यायाधीश को समिति की कार्यवाही समाप्त होने तक कार्य करने से रोकने की मांग करने वाली प्रार्थना में उतनी ही औचित्य की कमी थी जितनी मौलिकता और शिष्टाचार में जिसके लिए विद्वत न्यायाधीश हकदार है। तर्क लगभग यह मानते प्रतीत होते हैं कि आरोप स्थापित किए गए थे। न्यायाधीश की खामोशी और सार्वजनिक बहस में शामिल होने से उनके इनकार के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई। यदि हम सम्मान के साथ ऐसा कह सकते हैं, तो विद्वान न्यायाधीश को अपने विरोधियों को अपना

स्पष्टीकरण देने के निमंत्रण को अस्वीकार करने का अधिकार था। 75 के सार और वैधता के बारे में कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं

सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [बी. सी. रे, जे.]

विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपने समर्थन के लिए इन मंचों को मान्यता देने से इनकार करने से आरोप लगाए जा सकते हैं। जबकि बार के सदस्य जनहित में कार्य करने का दावा कर सकते हैं, साथ ही, शिष्टाचार और विशेष देखभाल का कर्तव्य है कि आरोप निराधार पाए जाने की स्थिति में या

किसी भी नैतिक अधमता को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त, न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया में अपूरणीय रूप से नुकसान नहीं होता है। इस दृष्टिकोण की यह आलोचना नहीं होनी चाहिए कि ऐसा करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम मंच द्वारा आरोपों की जांच किए जाने से पहले ही एक सक्षम और विनम्र न्यायाधीश को सार्वजनिक अपमान के लिए बेनकाब करने के लिए इसकी गणना की गई थी। हम चाहते हैं कि अदालत के अंदर और बाहर बहस का स्तर अधिक सभ्य और गरिमापूर्ण हो। स्वामित्व ने फिर से पूछा कि आरोपों को एकमात्र तरीके से साबित करने से पहले, जिसमें इसे साबित करने की अनुमति दी गई है, न्यायाधीश को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक समर्पण उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है; लेकिन है

न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के साधनों में से एक है और इसलिए, यह व्यापक लोक हित में है। यदि व्यवस्था को जीवित रहना है तो संवैधानिक तरीकों का पालन किया जाना चाहिए। कुलसचिव को लिखे अपने पत्र में विद्वान न्यायाधीश-जिसे वे न्यायालय में स्थापित करना चाहते थे

वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के व्यवहार पर गहरी पीड़ा व्यक्त की थी

उन्होंने स्वयं को उस पर निर्णय लेने और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने की अनुमति दी जैसा उन्होंने किया था।

आरई: सामग्री (I)

67. इस तर्क से पता चलता है कि अदालत को इस बात को ध्यान में रखते हुए

उस क्षेत्र की प्रकृति जिसमें न्यायालय का निर्णय और उसका रिट संचालित होना है,

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हुए, यह प्रदान करते हुए कि उसके पास ऐसा अधिकार क्षेत्र है। यह है।

विश्लेषण, व्यर्थ और निष्फल हो जाता है क्योंकि वास्तव में और का संविधानसमिति द्वारा जांच न तो समाप्त होती है और न ही इसका अंत करने का इरादा है।

स्वयं किसी भी स्वतंत्र कानूनी परिणाम में परिणत होते हैं, लेकिन केवल सदन के विचार-विमर्श से पहले और उससे पहले की कार्यवाही

राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव

न्यायाधीश को हटाना। उत्तरार्द्ध, यह आग्रह किया जाता है, निर्विवाद रूप से में है संसद के सदनों का विशेष प्रांत जिस पर अदालतें काम करती हैं

कोई नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र नहीं। का गठन और उससे पहले की कार्यवाही

यह आग्रह किया जाता है कि समिति अनिवार्य रूप से अनुक्रमिक और अभिन्न है

संसद के सदनों में कार्यवाही। चूंकि समिति और उसके

जाँच का न तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही अलग कानूनी सीमित प्रभाव के अलावा, और उद्देश्यों के लिए और के हिस्से के रूप में

संसद के सदनों में संभावित कार्यवाही, न्यायालय

अपने स्वयं के लंबित कानूनी परिणाम और जो अंतिम विश्लेषण में आता है और पूरी तरह से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में रहता है।

यह आग्रह किया जाता है [1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76

कि निष्फलता, औचित्य और निरर्थकता दोनों की दृष्टि से, न्यायालय को हस्तक्षेप करने के निमंत्रण को अस्वीकार कर देना चाहिए, भले ही समिति के गठन से संबंधित कार्यवाही का वह हिस्सा सख्ती से संसद के अनन्य क्षेत्र के भीतर न हो। यह आग्रह किया जाता है कि अदालतें अपनी प्रक्रिया को किसी ऐसे मामले में उम्मीद करने की अनुमति नहीं देंगी जो अंततः किसी ऐसी चीज में विलय हो जाएगा जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

68. यह सुझाव दिया जाता है कि निष्फलता के तत्व दो में उत्पन्न होते हैं।

क्षेत्रों। पहला, जैसा कि माना जाता है, क्या होना चाहिए यदि संसद के सदन यह कहने का विकल्प चुनते हैं कि उनके विचार में प्रस्ताव समाप्त हो गया है? क्या अदालत तब संसद के सदनों की कार्यवाही की वैधता में जाएगी और सदन के फैसले को अमान्य घोषित करेगी?

निष्फलता के सुझाए गए स्रोत का दूसरा क्षेत्र यह है कि

इस स्थिति के परिणाम कि संसद के सदन, समिति की रिपोर्ट के बावजूद, न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधन प्रस्तुत नहीं करने का निर्णय लेने के हकदार होंगे। यह कहा जाता है कि संसद के सदन के लिए सरकार को अनुशासित करना है यदि सदन

यह विचार कि सरकार अध्यक्ष के निर्णय पर अवैध निष्क्रियता के लिए दोषी है क्योंकि अंततः सदन ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है।

69. पहले बिंदु पर कोई कठिनाई नहीं है और होनी चाहिए। द.

इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की व्याख्या कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के तहत एक प्रस्ताव सदन के विघटन पर समाप्त नहीं होता है, एक बाध्यकारी घोषणा है। असम्प के आधार पर कोई तर्क नहीं

यह कि सदन कानून का उल्लंघन करते हुए कार्य करेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि कानून यह है कि प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है, तो यह मान लेना गलत है कि संसद के सदन कानून का उल्लंघन करेंगे। कानून की व्याख्या अदालतों की अनन्य शक्ति के भीतर होती है।

70. जहाँ तक दूसरे पहलू का संबंध है, अब क्या अपेक्षित है

जो याचिकाकर्ता अध्यक्ष के निर्णय को लागू करने और लागू करने की मांग करते हैं, वे समिति को जांच करने का निर्देश नहीं देते हैं। ऐसी प्रार्थना उस स्थिति के लिए कुछ विशिष्ट मुद्दों को उठा सकती है। लेकिन यहाँ, केंद्र सरकार ने स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करने और अध्यक्ष के निर्णय पर अपने कार्यों को विनियमित करने के लिए कानूनी स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास किया है। कानून की वह समझ अब अनुचित पाई गई है।

बस इतना करना आवश्यक है कि सही संवैधानिक घोषणा की जाए।

स्थिति. किसी भी प्राधिकरण को निर्देश के किसी विशिष्ट रिट को जारी करने की आवश्यकता नहीं है। विषय वस्तु की प्रकृति और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंततः जो कुछ भी आवश्यक है उसे पूरा करने का इरादा है कानूनी और संवैधानिक विषय-समिति को जेयूडीएल पर घोषित करना।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.] 77

राष्ट्रीय स्थिति और राज्य के विभिन्न अंगों को विचार करने के लिए छोड़ दें

अपने-अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के दायरे में आने वाले मामले।

विवाद I को तदनुसार निपटाया जाता है।

71. परिणामस्वरूप, पूर्वगामी कारणों से, रिट याचिका सं। 491 और 1991 के 541 का निपटारा कानून की उचित घोषणाओं द्वारा किया जाता है।

जैसा कि निर्णय में निहित है।

याचिका सं. लिखें। 542 और 1991 के 560 को खारिज कर दिया जाता है। 1991 की स्थानांतरण याचिका संख्या 278 की अनुमति है। लेखन याचिका सं. 1061

1991 को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले लिया गया है। स्थानांतरित रिट

याचिका भी खारिज कर दी जाती है।

शर्मा, जे. मैं अपने विवेकपूर्ण निर्णय से गुजरी हूँ।

विद्वान भाइयों, और मुझे खेद है कि मैं अपने विचारों को साझा करने के लिए खुद को राजी नहीं कर पाया। मेरी राय में, ये सभी याचिकाएं छूटने लायक हैं।

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं का रुख। (ग) संख्या। 491 1991 का और 1991 का 541 यह है कि श्री के कथित दुर्व्यवहार के संबंध में जांच।

न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी, डब्ल्यू. पी. में तीसरे प्रतिवादी। (ग) 1991 का सं. 491, जिसे न्यायाधीशों के प्रावधानों के तहत एक समिति को भेजा गया था।

(जाँच) अधिनियम, 1968 को आगे बढ़ना चाहिए और तदनुसार भारत संघ को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

2. उनकी ओर से मुख्य दलीलों को श्री शांति भूषण, श्री राम जेठमलानी और श्री R.K.Garg द्वारा संबोधित किया गया है, जो सभी डब्ल्यू, पी में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं। (ग) 1991 का सं. 491, जिसे मुख्य मामला माना गया है। यद्यपि सार में उनका रुख समान है, वे नहीं हैं

मामले की सुनवाई के दौरान चर्चा किए गए कुछ बिंदुओं पर सुसंगत। उन्हें सुश्री इंदिरा जयसिंह और श्री पी. पी. राव, सर्वोच्च न्यायालय बार एसो एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य रूप से समर्थन दिया गया है। (ग) 1991 का सं. 541 और सुविधा के लिए इन दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा। टी. पी. में याचिकाकर्ता श्रीमती राज बीरबल की ओर से श्री कपिल सिब्बल ने इसके विपरीत दृष्टिकोण रखा है। (ग) 1991 का सं. 278, डब्ल्यू. पी. में मध्यस्थ श्री (ग) 1991 का सं. 491 और डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता श्री श्याम रतन खंडेलवाल। (ग) 1991 की सं. 560; और उनके रुख को ध्यान में रखते हुए, उन्हें इस निर्णय में प्रतिवादी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. तीसरे प्रतिवादी के कथित दुर्व्यवहार की जांच के लिए समिति का गठन प्रोवी [1991] एस. यू. पी. पी. के तहत 12.3.1991 पर किया गया था।

2 एस सी आर।

78 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)

श्री रबी रे, लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष, डब्ल्यू. पी. में एक पार्टी नहीं

((ग) संख्या। 491 1991 का और 1991 का 541, लेकिन श्री श्याम द्वारा प्रेरित

डब्ल्यू. पी. में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में रतन खंडेलवाल (ग) 1991 की सं. 560। द. लोकसभा को अगले ही दिन भंग कर दिया गया, यानी 13.3.1991।

4. भारत संघ की ओर से उपस्थित श्री अटॉर्नी जनरल

ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय को द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की पुष्टि करनी चाहिए

भारत संघ ने अपने शपथ पत्र में कहा कि पिछली लोकसभा के भंग होने पर,

तीसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ प्रस्ताव समाप्त हो गया और मामला समाप्त नहीं हो सकता है आगे बढ़ें।

5. याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार, एक बार समिति

गठित किया गया था, पूरी जांच के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए

अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार का यह रुख कि इस संबंध में सदन के विघटन पर प्रस्ताव समाप्त हो गया है,

अस्वीकार कर दिया। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि - धन आदि प्रदान करने के माध्यम से इस तरह से कार्य करें, ताकि यह हो सके

समिति के लिए अपने कार्य को पूरा करना व्यावहारिक रूप से संभव है। चूंकि अधिनियम के तहत तदनुसार कार्य करने की बाध्यता उत्पन्न होती है, इसलिए इस न्यायालय को वैधानिक कर्तव्य के प्रदर्शन को लागू करने का पूरा अधिकार है; औरवर्तमान मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस शक्ति का प्रयोग करना उचित है।

याचिकाकर्ता आगे प्रार्थना करते हैं कि इस बीच तीसरा जवाब दे

उन्हें न्यायिक मामलों का निपटारा करने का कार्य नहीं करना चाहिए और चूंकि उन्होंने स्वयं ऐसा करने से परहेज नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई न्यायिक कार्य आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य

न्यायाधीश को भी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद नियम निसी जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश को नोटिस जारी करना समीचीन नहीं माना। इस संबंध में अंतरिम निर्देश के लिए एक प्रार्थना भी फिर से की गई। मामलों की सुनवाई के दौरान इसी प्रभाव का एक और आवेदन दायर किया गया था और काफी देर तक सुना गया था और अंततः एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया था।

6. श्री सिब्बल, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के पास चाल है

रिट याचिकाओं की स्थिरता को इस आधार पर चुनौती दी कि मामला न्यायसंगत नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया कि चूंकि अध्यक्ष ने सदन के संदर्भ के बिना लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए अध्यक्ष का आदेश अमान्य था, और समिति का गठन अधिकार से बाहर है। अध्यक्ष के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और दुर्भावना के आधार पर भी चुनौती दी गई है। जहाँ तक जे. यू. डी. एल. पर उप-समिति के विघटन का प्रभाव है।

लेखा योग्यता v. यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.] 79

पिछली लोकसभा चिंतित है कि उत्तरदाताओं ने केंद्र सरकार के इस रुख का समर्थन किया है कि प्रस्ताव समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी गैर-न्यायसंगतता की याचिका के अनुरूप, श्री सिब्बल ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेना सदन का काम है।

लंबी दलीलों को पार के विद्वान वकील द्वारा संबोधित किया गया था

अनुच्छेद 124 (4) और (5) और अधिनियम की सही व्याख्या पर संबंध, और श्री सिब्बल ने तर्क दिया है कि यदि उनके द्वारा सुझाए गए निर्माण अधिनियम के प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया जाता है, अधिनियम को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से निरस्त करना पड़ता है क्योंकि यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

डब्ल्यू. पी. में (ग) नहीं। 1991 का 560 श्री श्याम रतन खंडेलवाल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों को संविधान के अनुच्छेद 121 और 124 (5) के अधिकार से बाहर घोषित करने के लिए अनुरोध किया है; अध्यक्ष के निर्णय को रद्द करने के लिए; और समिति को जांच शुरू करने या आगे नहीं बढ़ने के लिए एक रिट ऑफ मैंडमस जारी करने के लिए। वह यह भी घोषणा चाहते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए तीसरे प्रतिवादी को काम के आवंटन को रोक नहीं सकते हैं, और इस मामले में परिणामी निर्देश चाहते हैं। अपने तर्क के दौरान, श्री सिब्बल ने पीठ के एक प्रश्न के उत्तर में यह स्थिति स्पष्ट की कि यदि उनकी गैर-न्यायसंगतता की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो सभी याचिकाओं को खारिज करना पड़ सकता है।7. यह उचित है कि इस न्यायालय की अधिकारिता और भारत में किसी भी न्यायालय के उस मामले से

संबंधित बिंदु पर पहले विचार किया जाए। यदि इस मुद्दे पर उत्तरदाताओं का रुख सही है, तो पक्षों द्वारा उठाए गए अन्य प्रश्नों से निपटना आवश्यक नहीं हो सकता है। उनके समर्थन में

श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि उन्होंने अनुच्छेद 93 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 122 (2) के प्रावधानों पर भरोसा किया है और आग्रह किया है कि वर्तमान मामला लोकसभा के कामकाज के संचालन से संबंधित है और इसे इसकी प्रक्रिया को विनियमित करने के कार्यों में शामिल किया गया है, और इस तरह अध्यक्ष जो संसद के सदस्य और अधिकारी हैं, उन्हें उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उप-नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या प्रस्ताव जिसके आधार पर

समिति द्वारा वर्तमान जांच का आदेश दिया गया है कि वह समाप्त हो गई है या नहीं और क्या जांच आगे बढ़नी चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करना सदन का काम है और इसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 100 का भी संदर्भ दिया गया था, लेकिन विद्वान वकील ने अपना रुख स्पष्ट किया कि वर्तमान संदर्भ में अनुच्छेद 124 (4) में बताए गए विशेष बहुमत को अनुच्छेद 100 (1) में उल्लिखित साधारण बहुमत के लिए प्रतिस्थापित करना होगा। यह तर्क दिया गया है कि अध्यक्ष मामले को जांच के लिए समिति को भेजने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे और वह भी संबंधित न्यायाधीश को सुने बिना; और किसी भी स्थिति में उनका आदेश किसी भी निर्णय [1991] एस. यू. पी. पी. के अधीन है।

2 एस सी आर।

80

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके विपरीत सदन किसी भी स्तर पर पहुँच गया। राज्य की शक्तियों को इसके तीन अंगों के बीच अलग करने की अवधारणा पर जोर दिया गया और यह दावा किया गया कि सदन के भीतर सभी मामले जिनमें प्रस्तावों को आगे बढ़ाना, स्थगन प्रस्ताव और बहस शामिल हैं, न्यायिक जांच के दायरे से बाहर हैं। वकील ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान मामले में यह केंद्र सरकार है, जिसने विवादित मुद्दे पर अपने लिए निर्णय लिया है और याचिकाकर्ता इसे अदालत का दरवाजा खटखटाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। न्यायालय को इस आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि उसे अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए राजी नहीं किया जा सकता है जो वह सीधे नहीं कर सकता है। सार यह है कि यह मामला संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।

8. हालाँकि अपने अंतिम निष्कर्ष में मैं उत्तरदाताओं से सहमत हूँ।

यह कि वर्तमान मामले में अदालतों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं श्री सिब्बल के तर्क से सहमत नहीं हूं जो सामान्य शब्दों में संसद के बहुत व्यापक और अनन्य अधिकार क्षेत्र की धारणा पर आधारित है, जैसा कि उनके तर्क के दौरान संकेत दिया गया था। उनका यह रुख कि अध्यक्ष अकेले निर्णय नहीं ले सकते

थे, भी उचित नहीं प्रतीत होता है। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि चूंकि एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित मामला शुरू से ही संसद के एक सदन के अनन्य नियंत्रण में है, इसलिए प्रत्येक निर्णय पूरे सदन द्वारा लिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बहस की अनुमति देनी होगी। नतीजतन, न्यायाधीशों के आचरण पर सदन में चर्चा पर प्रतिबंध प्रारंभिक चरण से ही गायब हो जाएगा, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती है। उन्होंने न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964 पर संयुक्त समिति के समक्ष अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5 पर श्री आई. डी. 1 की व्याख्या पर भरोसा किया (जो 1964 का विधेयक संख्या 5 था जिसे अंततः हटा दिया गया था) और उनका विचार था कि संसद में न्यायाधीश के आचरण पर बहस से बचने का वांछित उद्देश्य केवल अध्यक्ष द्वारा इस तरह की बहस की अनुचितता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का सावधानीपूर्वक प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।

9. हालाँकि राज्य की शक्तियों को कॉन्स्टी द्वारा वितरित किया गया है।

तीन अंगों, अर्थात् विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सख्ती से पालन नहीं किया गया है और धूसर क्षेत्रों में शक्तियों का कुछ अतिव्याप्त है। कुछ उदाहरणों से पता चलेगा कि विवादों के निर्णय से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए अदालतों का अधिकार क्षेत्र कई अपवादों के अधीन है। आइए हम एक ऐसे मामले पर विचार करें जिसमें एक व्यक्तिगत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाता है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर और कुछ कृत्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अपूरणीय क्षति और उसके दावे का निर्णय अनुच्छेद 262 या अनुच्छेद 363 द्वारा कवर किए गए विवाद के निर्णय पर निर्भर है। उसके पास अदालतों के समक्ष कोई कानूनी उपाय नहीं है। इसी तरह संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जो आर. एम. ए., जे. जे. जे.]

सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. उत्तरदायित्व "। यू. ओ. आई. [शर्मा

81

अनुच्छेद 122 (2) या 212 (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में न्यायसंगत शिकायत हो सकती है।

अदालतों के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ

देश की सीमा के पास रहने वाले नागरिकों का समूह निकट है

अपनी संपत्ति के अलावा बड़ी संख्या में लोगों की जान गंवाना निश्चित है। यह हो सकता है केवल दुश्मन देश द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार करके टाल दिया गया, जो

समग्र राष्ट्र। हालांकि, राज्य के संबंधित अधिकारियों का मानना है किअलग दृष्टिकोण और एक अपरिहार्य के रूप में तुरंत युद्ध शुरू करने पर विचार करें

रणनीति, यहां तक कि सीमावर्ती क्षेत्र के लिए आसन्न खतरे के सामने भी। एक पर

पीड़ित नागरिकों द्वारा आवेदन, न्यायालय एक पर शुरू नहीं कर सकता

राज्य की प्रस्तावित कार्रवाई के गुण-दोषों की जांचन ही यह निर्देश दे सकता है कि संकटग्रस्त क्षेत्र के निवासियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए

युद्ध शुरू होने से पहले कुछ सुरक्षित स्थान। उदाहरण कई हो सकते हैं।

प्लाई किया। आम तौर पर, विवादों के निर्णय से जुड़े प्रश्न अदालतों के अधिकार क्षेत्र के लिए अनिवार्य होते हैं, लेकिन अपवाद हैं, न केवल वे जो व्यक्त शब्दों में संविधान के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा कवर किए जाते हैं, बल्कि अन्य जो संवैधानिक योजना में शामिल स्थापित न्यायशास्त्र के सिद्धांतों से उत्पन्न आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं। यह इस न्यायालय द्वारा श्रीमती में देखा गया था। इंदिरा गांधी बनाम पेज 415 पर काज नारायण, [1976] 2 एस. सी. आर. 347, के तहत शक्तियों का कठोर पृथक्करण

अमेरिकी संविधान या ऑस्ट्रेलियाई संविधान के तहत लागू नहीं होता है।

हमारे देश और कई शक्तियों को जो सख्ती से न्यायिक हैं, हमारे संविधान के तहत अदालतों के दायरे से बाहर रखा गया है।

10. व्यापक अर्थों में राज्य की न्यायिक शक्ति

अपनी सभी शाखाओं को शामिल करने के रूप में अभिव्यक्ति न्यायिक शक्ति से अलग है जो एक लिखित संविधान द्वारा अदालतों में निहित या निहित होने का इरादा है। वर्तमान मामले में जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या संविधानात्मक योजना के तहत उच्च न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों) के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित कोई मामला अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है या इस अदालत की किसी भी स्थिति में है। संविधान की बारीकी से जांच करने पर मुझे ऐसा लगता है कि राज्य के तीन अंगों-कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के सदस्यों को उच्चतम स्तर पर हटाने के संबंध में एक विशेष पैटर्न अपनाया गया है और इस योजना को संविधान में सचेत रूप से शामिल किया गया है, इसके प्रावधानों को समझने में इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उच्चतम स्तर पर तीन शाखाओं में से किसी एक के सदस्य को हटाने का प्रश्न आता है, अर्थात राष्ट्रपति को; संसद और राज्य के सदस्य विधायिकाएँ; और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उत्पन्न होते हैं, यह निर्णय लेने के लिए एक अन्य अंग पर छोड़ दिया जाता है, इसके अलावा जहां समस्या उत्पन्न हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 55 में बताए गए तरीके से अनुच्छेद 54 द्वारा निर्धारित कॉलेज।

चूँकि उसे सलाह के अनुसार अपने कार्यों का प्रयोग करना होता है।

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत, उनके महाभियोग से संबंधित मामला

अनुच्छेद 61 द्वारा संसद को यह कार्य सौंपा गया है। संविधान मेंसंसद के दोनों सदनों और विधानमंडलों का गठन

राज्य, देश के लोग अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं

चुनाव की प्रक्रिया और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का अंत में निपटारा किया जाता है।

न्यायिक रूप से। जब किसी वर्तमान सदस्य की अयोग्यता की बात आती है, तो

मामला अनुच्छेद 103 या 192 द्वारा निपटाया जाता है और क्या है

वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण यह है कि सौंपने के बजाय

संबंधित सदन के लिए मामला, संविधान ने एक के लिए प्रदान किया है

इस तरह के विवाद पर राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाता है, और वह इस पर कार्रवाई नहीं करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह, लेकिन की राय के अनुसार

चुनाव आयोग जिसे इस न्यायालय ने एक माना है

संविधान के अनुच्छेद 136 के दायरे में आने वाला न्यायाधिकरण

ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस v. एम. ए. संगमा, [1978] 1 एससीआर

393 411 पर। इस प्रकार, किसी विवाद को तय करने की शक्ति का उपयोग इसके द्वारा नहीं किया जाना है

विधानमंडल, लेकिन काफी हद तक न्यायालयों के पास है। इसके अनुरूप

अनुच्छेद 124 के प्रतिमान खंड (4) में जोर देकर कहा गया है कि एक न्यायाधीशउच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को उससे नहीं हटाया जाएगा।

प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत को छोड़कर

संसद। इस प्रकार इस प्रक्रिया में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को बाहर रखा गया है। संविधान और अधिनियम के प्रावधान और प्रासंगिक साथी रियाल, जिन पर बाद में चर्चा की जाएगी, सभी इस संविधानात्मक योजना को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं।

12. योजना, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो मेरे पढ़ने के अनुसार है

संविधान को अपनाया गया है, इसे राज्य के तीन अंगों में विश्वास की कमी के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक लिखित आदेश तैयार करते समय और उसे अपनाते समय अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें लोगों को यह आश्वासन देना शामिल है कि विचाराधीन मुद्दे के रूप में संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय को प्रभावित करने वाले व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की संभावना को स्थिति में यथासंभव समाप्त कर दिया गया है। और जहाँ यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, वहाँ इसकी मदद नहीं की जा सकती है, और आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करके इसका मिलान किया जाना चाहिए, जो यहाँ आकर्षित नहीं है। हैमिल्टन ने "द फेडरलिस्ट" में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि जब सवाल उठते हैं कि क्या न्यायपालिका या विधानमंडल या राष्ट्रपति में बहुत उच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति ने खुद को पद धारण करने के लिए अयोग्य बना दिया है, तो वे एक ऐसी प्रकृति के होते हैं जो मुख्य रूप से समाज को तुरंत की गई चोटों से संबंधित होती है। उन्हें हटाने के लिए कोई भी कार्यवाही, सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. होगी।

उत्तरदायित्व v. यू. ओ. आई. शर्म, जे.] 83

इस कारण से शायद ही कभी पूरे समुदाय की भावनाओं को उत्तेजित करने और इसे संबंधित व्यक्ति के लिए कमोबेश दोस्ताना या शत्रुतापूर्ण दलों में विभाजित करने में विफल रहता है। सार्वजनिक मामलों के प्रशासन में लगे प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अस्तित्व से इतनी गहराई से संबंधित एक विश्वास की नाजुकता और परिमाण खुद के लिए बोलते हैं।

13. श्री सिब्बल ने आगे हैमिल्टन पर भरोसा करते हुए कहा कि "महाभियोग की अदालत को जिस भयानक विवेकाधिकार को अनिवार्य रूप से समाप्त करना होगा।

समुदाय के सबसे गोपनीय और सबसे प्रतिष्ठित पात्रों का सम्मान करना या उन्हें बदनाम करना, कम संख्या में व्यक्तियों के प्रति न्यास की प्रतिबद्धता को मना करता है। वकील ने कहा कि संभवतः यही कारण है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का सवाल विशेष रूप से संसद को सौंपा गया है और आगे इस भावना में अधिनियम के लिए बड़ी संख्या में संसद सदस्यों को प्रस्ताव की सूचना देने की आवश्यकता होती है। 'हार्वर्ड लॉ रिव्यू' (1912-1913 खंड) से उद्धृत करते हुए।, वकील ने तर्क दिया कि न्यायिक कार्यालय अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट को रद्द करने का जनता का अधिकार मौलिक है। एक सच्चे गणराज्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद के अधिकार के साथ पैदा नहीं हो सकता है। सरकार की ऐसी प्रणाली के तहत, पद, चाहे वह चयनात्मक हो या नियुक्तिपूर्ण, एक अर्थ में एक राजनीतिक विशेषाधिकार है। इस विशेषाधिकार का अनुदान लोगों की राजनीतिक शक्ति से आता है,

और इसलिए, अंततः इसे लोगों में निवास करने वाली राजनीतिक शक्ति के प्रयोग द्वारा छीन लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कई न्यायविदों के दृष्टिकोण का उल्लेख करने के बाद श्री सिब्बल फिर से "द फेडरलिस्ट" के पास वापस आए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सु प्रीमे कोर्ट की अयोग्यता पर विचार करते हुए निम्नलिखित शब्दों में महाभियोग की शक्ति सौंपी गई: - " यह बहुत संदेह की बात है कि क्या उस न्यायाधिकरण के सदस्यों को हर समय धैर्य का इतना प्रतिष्ठित हिस्सा दिया जाता है, जैसा कि इतने कठिन कार्य के निष्पादन में कहा जाता है, और यह अभी भी संदेह की बात है कि क्या उनके पास श्रेय और अधिकार का स्तर होगा, जो कुछ अवसरों पर लोगों को उनके निर्णय के साथ मिलाने के लिए अनिवार्य हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि ये वे सटीक विचार हैं जिन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं से इस योजना को अपनाने की अपील की, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के तीन महत्वपूर्ण अंगों में बहुत उच्च अधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय को संविधान द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। मेरा निष्कर्ष आगे नीचे चर्चा की गई सामग्री द्वारा समर्थित है।

14. पक्षों के विद्वान वकील ने संविधान और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के ऐतिहासिक आधार के साथ-साथ कई अन्य देशों के संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया, जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में कानूनी स्थिति की व्याख्या के लिए आदर्श हैं। श्री सिब्बल ने श्री के साक्षय पर बहुत जोर दिया।

न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964। उनका तर्क है कि संयुक्त समिति के समक्ष व्यक्त की गई राय के परिणामस्वरूप विधेयक को हटा दिया गया था, और इसके साथ ही एक और विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था जिसे अंततः संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

1968 के अधिनियम के रूप में संसद। पूर्ववर्ती विधेयक के प्रावधान, उस पर उठाई गई आपत्तियाँ और यह तथ्य कि 1968 का अधिनियम एक उप-विधेयक पर पारित किया गया था, मूल विधेयक को हटाने के निर्णय के तुरंत बाद पुनर्निर्मित किया गया था, सभी कानूनी स्थिति की व्याख्या के लिए अनुमेय सहायक हैं जिन्हें हमारे समक्ष वर्तमान मामलों में सुनिश्चित किया जाना है। यद्यपि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील उनकी स्वीकार्यता को चुनौती देते हैं, श्री सिब्बल द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों के कुछ हिस्सों को याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके रुख का समर्थन करने के रूप में समझने का प्रयास किया गया था। मेरे विचार में, अंतर-ढोंग के लिए सहायता के रूप में पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना अनुचित है। इस पहलू से निपटने वाले कानूनों के निर्माण का नियम 1584 में हेडन के मामले में कहा गया था: 76 ई. आर. 637, और हमारे न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में निर्णयों में इसका पालन किया गया है। हमारे संविधान के

अनुच्छेद 286 की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय द्वारा बंगाल इम्युनिटी कंपनी बनाम में निर्भरता रखी गई थी। बिहार राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 603 632 और 633 पर, हेडन के मामले में लॉर्ड कोक के कथन और टिप्पणियों पर। ईस्टमैन फोटोग्राफिक मैटेरियल कंपनी में अर्ल ऑफ-हैल्सबरी बनाम पेटेंट के नियंत्रक जनरल एल. आर., [1898] ए. सी. 571 पी. 576 निम्नलिखित शब्दों में नियम की पुष्टि करना:

" मेरे स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि क़ानून का अर्थ सवाल, यह न केवल वैध है बल्कि अत्यधिक सुविधाजनक है

पूर्व अधिनियम और सुनिश्चित की गई बुराइयों दोनों को संदर्भित करें

जिसने उपाय प्रदान किया। इन तीनों की तुलना मैं कर रहा हूँनिष्कर्ष पर संदेह नहीं कर सकते।

बी. प्रभाकर राव बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य, [1985] पूरक। 2

एस. सी. आर. 573, पी. पर अवलोकन। 591 , नीचे उद्धृत, रोशन कर रहे हैं:

" जहाँ आंतरिक सहायता नहीं आ रही है, वहाँ हम हमेशा कर सकते हैंविधान के उद्देश्य की खोज के लिए बाहरी सहायता का सहारा लेना

यह। बाहरी सहायता से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह अब एक अच्छी तरह से स्थापित है आधुनिक वैधानिक निर्माण का सिद्धांत। इस प्रकार 'उसे लागू करना

टोरी 'प्रासंगिक है:' एक अधिनियम का अधिनियमित इतिहास सुर है

इसके परिचय के सापेक्ष सार्वजनिक ज्ञान का आवर्ती संग्रह

संसद को एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना और इसके माध्यम से आगे बढ़ना,और अंततः संसद द्वारा पारित किया जाता है। विशेष रूप से यह

विचार के भीतर मानी जाने वाली बाहरी सामग्री संसद ने जब यह अधिनियम पारित किया।

फिर से "आई. एम. सब-कमेटी ऑन जे. यू. डी. एल. की अवधि में। लेखा योग्यता v. यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.] 85

इसके अधिनियमन के बाद, एक अधिनियम को कैसे समझा जाता है, इसका इतिहास समकालीन व्याख्या का हिस्सा है, और इसे विधायी इरादे पर प्रकाश डालने के लिए माना जा सकता है। बाद का इतिहास, इस सिद्धांत के तहत कि एक अधिनियम हमेशा बोल रहा है, इंगित कर सकता है कि समय-समय पर विकास के आलोक में अधिनियम को कैसे माना जाता है। किसी अधिनियम का प्रशासन करने वाले सरकारी विभाग या अधिनियम से संबंधित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक बयानों को इसके

प्रावधानों के अर्थ पर प्रेरक प्राधिकरण के रूप में माना जा सकता है। न्याय अंधा हो सकता है लेकिन बहिरा होना नहीं है। न्यायाधीश हैं

ध्वनिरोधी कक्षों में न बैठें। समिति की रिपोर्ट, संसदीय बहस, नीतिगत बयान और आधिकारिक प्रवक्ताओं के सार्वजनिक बयान वैधानिक व्याख्या में प्रासंगिक हैं। लेकिन राज्य के दो प्रमुख अंगों, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो सौहार्द, शिष्टाचार और पुनर्विचार होना चाहिए, उसके लिए अदालतों को अपने समक्ष रखी गई अतिरिक्त पाठ्य सामग्री का कुशल मूल्यांकन करने और अनिवार्य रूप से अविश्वसनीय को बाहर करने की आवश्यकता होती है। " फिर भी अदालत, अपनी स्वयं की प्रक्रिया के स्वामी के रूप में, उन्हें स्वीकार करने का एक अवशिष्ट अधिकार बरकरार रखती है, जहां दुर्लभ मामलों में, विधायक के इरादे को पूरा करने की आवश्यकता अदालत को दिखाई देती है।

उस अधिनियम की सही व्याख्या करने की दृष्टि से, जो उस मामले का विषय था, सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने, उसके परिणामस्वरूप आंदोलन और आंदोलन के बाद हुए समझौते सहित घटनाओं के इतिहास और उत्तराधिकार, सभी पर विचार किया गया। तदनुसार, मैं संवैधानिक प्रावधानों और अधिनियम दोनों की प्रासंगिक पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताने का प्रस्ताव करता हूं।

15. भारत के संविधान के निर्माण के समय, कई अन्य देशों के संविधान, जो सहायक प्रतीत होते थे, थे - जाँच की गई और शुरू में एक मसौदा तैयार किया गया। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा पेश किए गए संशोधन पर संबंधित प्रावधान को निम्नलिखित शब्दों में अंतिम वाक्य को छोड़कर राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया संविधान अधिनियम (1900) की धारा 72 (ii) के संदर्भ में मसौदे में शामिल किया गया था:

" इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए संघीय कानून द्वारा आगे का प्रावधान किया जा सकता है।

जब इस मामले को अंततः संविधान सभा द्वारा उठाया गया तो बहसों से संकेत मिलता है कि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] की समिति को सौंपने के सुझावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

2 एस सी आर।

86

उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या; और ऐसा करते समय, अन्य राष्ट्रमंडल देशों के कानून को ध्यान में रखा गया। जहां तक मसौदे के अंतिम वाक्य का संबंध था, सर अल्लादी ने यह कहते हुए स्थिति को समझाया कि "इस तरह का प्रावधान अन्य संविधानों में नहीं होता है, लेकिन इस पर प्रावधानों को अधिक विस्तार देने की प्रवृत्ति है।

हमारा पक्ष और यही उस खंड को रखने का एकमात्र औचित्य है।

16. संविधान के निर्माण में बहसों और अन्य कदमों पर आगे विचार करने से पहले, उस बिंदु की प्रासंगिकता और महत्व को समझना उपयोगी हो सकता है जिसका विवादास्पद मुद्दे पर प्रभाव पड़ता है।

हमारे सामने मुद्दा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रश्न अधिनियम के तहत समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही संसद में आता है। संसद या उसके किसी भी सदन का समिति पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो विशुद्ध रूप से एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है, और इसलिए, इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। यदि यह स्थिति सही है, तो 1968 से पहले क्या स्थिति थी, जब कोई अधिनियम नहीं था? सवाल यह है कि क्या संसद के पास कोई कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं थी, भले ही किसी न्यायाधीश के कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता की तत्काल जांच की मांग की गई हो। दूसरे शब्दों में, क्या संसद द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड (4) के तहत शक्ति का प्रयोग खंड (5) के तहत एक कानून के अधिनियमन पर निर्भर था और जब तक यह शर्त पूरी नहीं हो जाती, तब तक खंड (4) के तहत कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। यदि दूसरी ओर संसद की शक्ति किसी कानून के अधिनियमन के अधीन नहीं थी, तो क्या उसे इस अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया था जब उसने कोई अधिनियम पारित किया था? 1968 में किस सिद्धांत पर संसद का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र समाप्त हो सकता था? चूँकि इस पहलू का एक प्रभाव है, इसलिए विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों के दौरान यह कुछ चर्चा का विषय था।

17. श्रीमान सीबा! यह दावा करने में जोरदार था कि खंड (5) प्रकृति में सक्षम था, और खंड (4) को खंड (5) पर निर्भर के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती थी। उन्होंने 1964 के विधेयक संख्या 5 की संयुक्त समिति के समक्ष श्री सीतलवाड़ के साक्षय पर भरोसा किया। 1991 के प्रमुख मामले रिट याचिका (सी) संख्या 491 में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण द्वारा निर्देशित श्री शांति भूषण का रुख यह रहा है कि खंड (5) केवल सक्षम था, लेकिन उस अर्थ में नहीं जैसा कि श्री सीतलवाड़ ने अपने साक्षय में कहा था। उत्तरार्द्ध के विचार में, संसद के लिए यह खुला है कि वह खंड (5) के तहत बनाए गए अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे या किसी भी मामले में इसकी अनदेखी करे और कोई अन्य प्रक्रिया अपनाए। अन्य में

शब्दों में, 1968 के अधिनियम के पारित होने के बाद भी, संसद या तो उक्त अधिनियम के अनुसार आगे बढ़ने या उसे अनदेखा करके स्वतंत्र रूप से कार्य करने का विकल्प चुन सकती है। श्री शांति भूषण ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। एक बार 1968 का अधिनियम लागू हो जाने के बाद, संसद इसका पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन पहले 87

यह अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र था। हालाँकि, वह अपनी दलील में बिल्कुल स्पष्ट थे कि खंड (4) के तहत शक्ति का प्रयोग खंड (5) के तहत एक कानून के अधिनियमन पर सशर्त नहीं कहा जा सकता है, और अन्यथा प्रावधानों की व्याख्या करने से असाधारण परिणाम होगा कि संसद 1968

तक लगभग 18 वर्षों तक असहाय स्थिति में थी, अगर किसी न्यायाधीश को पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। मैं विद्वान वकील से सहमत हूँ।

18. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने किया

इस पहलू का स्पष्ट रूप से प्रचार न करें। श्री गर्ग का मत है कि चाहे तीसरे प्रतिवादी को हटा दिया जाए या नहीं, या समिति के समक्ष जांच आगे बढ़े या नहीं, उन्हें न्यायाधीश के रूप में कार्य करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि खराब होने के कारण, उन्हें साफ किया जाना चाहिए ताकि लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा हो सके। श्री राम जेठमलानी, अन्य विद्वान वकील, जो 1991 की रिट याचिका (सी) संख्या 491 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे, शुरू में खंड (4) और (5) के सह-संबंध पर श्री शांति भूषण के रूप में विचार कर रहे थे, लेकिन कुछ चर्चा के बाद, उन्होंने स्थिति पर पुनर्विचार किया और एक सकारात्मक रुख अपनाया कि खंड (4) के तहत शक्ति का प्रयोग खंड (5) के तहत अधिनियमित किए जा रहे कानून पर निर्भर था, और यह कि संसद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए बाध्य थी।

19. अब चर्चाओं पर वापस आते हुए, श्री संथानम ने एक सुझाव दिया

अधिक विवरण शामिल करने के लिए संशोधन, जिसके लिए सर अल्लादी का उत्तर इस प्रकार था:

" हमें इससे अधिक सावधानी और अधिक विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है।

जिन लोगों ने अन्य क्षेत्राधिकारों में इसी तरह के मामले की सुनवाई की है। आई.

मेरे दोस्त को यह कहने के लिए चुनौती दें कि क्या कोई विस्तृत प्रावधान हैकिसी भी अन्य मामले में न्यायाधीशों को हटाने से अधिक

दुनिया में संविधान "।

उन्होंने सदन से सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करने का अनुरोध किया, अर्थात्

राष्ट्रपति को इस देश के सर्वोच्च विधानमंडल के परामर्श से वह अधिकार होगा, और आश्वासन दिया कि, "इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वोच्च विधानमंडल उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा"। उन्होंने कानून के निर्माण से संबंधित प्रावधान में और जोड़ करने के विचार को यह कहते हुए खारिज कर दिया, "इन सभी के लिए एक विस्तृत प्रावधान करना किसी भी संविधान में अपनाई जाने वाली एक महान प्रक्रिया होगी। आपको यह किसी भी संविधान में नहीं मिलेगा, यहां तक कि जर्मन संविधान में भी नहीं जो विशेष रूप से विस्तृत है, न ही डोमिनियन संविधान में और न ही निपटान अधिनियम और ब्रिटिश संसद के बाद के अधिनियमों में भी जो न्यायाधीशों को हटाने का उल्लेख करते हैं। कुछ सदस्यों ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के कई मौजूदा न्यायाधीशों को [1991] एस. यू. पी. पी. होना चाहिए।

2 एस सी आर।

88

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही में शामिल, जिस पर सर अल्लादी को कड़ी आपत्ति थी। उन्होंने

सदस्यों से आह्वान किया, "पाँच से युक्त तंत्र प्रदान न करें।

या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर निर्णय में बैठने के लिए चार न्यायाधीश

भारत का न्याय? आप हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। " खंड था अंततः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है "सर्वोच्च" में शक्ति निहित करने का मसौदा तैयार किया गया।

संसद "क्योंकि" हटाने की कुछ शक्ति कहीं निहित होनी चाहिए "।

उन्होंने बताया कि इस मामले को विवेक पर नहीं छोड़ा जा रहा है।किसी भी सदन को न्यायाधीश को हटाने के लिए, लेकिन अंतिम संप्रभु शक्ति होगी

संसद के दोनों सदनों में निहित और "यह मेरा महत्व है।

संशोधन "। इस पृष्ठभूमि में, लेख को अंततः शामिल किया गया था

ड्राफ्ट।

हालाँकि जैसा कि सर अल्लादी के बयानों से भी स्पष्ट था

खंड (4) को खंड (5) पर निर्भर नहीं बनाना, फिर भी संभवतः किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए जो शामिल करके उत्पन्न हो सकती थी

एक एकल खंड में पूरे प्रावधानों को विभाजित किया गया और उनमें रखा गया

दो अलग-अलग खंड और ऐसा करते समय, भाषा में थोड़ा बदलाव किया गया थाकानून के सीमित दायरे पर जोर देना। खंड (4) में यह नहीं कहा गया है कि

न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता को केवल में साबित करना होगा

खंड (5) के तहत संसद द्वारा पारित किए जाने वाले कानून के अनुसार।

खंड (4) उद्देश्य की पूर्ति करना जारी रखेगा जैसा कि अब करता है, बिना

यदि खंड (5) को संविधान से हटाया जाना था तो कोई संशोधन

आज। पार्लिया की शक्ति पर किसी सीमा का कोई संकेत नहीं है।यह तय करने के लिए कि यह किस तरह से गलत धारणा पर निष्कर्ष प्राप्त करेगा

उसके द्वारा आगे की कार्रवाई करने के लिए हमारी असमर्थता। खंड (5) मात्र

यदि वह चाहे तो संसद को इस उद्देश्य के लिए एक कानून बनाने में सक्षम बनाता है।'मई' शब्द को कभी-कभी अनिवार्य अर्थों में समझा जाता है।

के रूप में 'होगा', लेकिन आम तौर पर यह कार्रवाई के एक विकल्प को इंगित करता है न कि एक कॉम

मान्ड। वर्तमान संदर्भ में, यह मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि इसका उपयोग इसके असाधारण अर्थ में किया गया है। यह महत्वपूर्ण है।यह ध्यान देने के लिए कि अनुच्छेद 124 के खंड (2) में न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित करते समय, परंतुक (बी) खंड (5) का उल्लेख किए बिना खंड (4) में प्रदान की गई तरीके से समय से पहले हटाने की अनुमति देता है। इसका महत्व

खंड (5) के लोप की सराहना अनुच्छेद 124 के खंड 2 (ए) की भाषा का उल्लेख करके की जा सकती है जिसमें निर्देश दिया गया है कि "उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और उस तरीके से निर्धारित की जाएगी जो संसद कानून द्वारा प्रदान करे।"

सभी प्रासंगिक सामग्रियों की जांच करने पर, मेरा विचार है

कि खंड (4) के तहत शक्ति का प्रयोग खंड (5) के तहत एक कानून के अधिनियमन और जे. यू. डी. एल. पर उप-समिति डालने के कारण पर सशर्त नहीं बनाया गया था।

लेखा योग्यता v. यू. ओ. आई. [शर्मा, जे।] 89

अनुच्छेद 124 में खंड (5), जैसा कि सर अल्लादी द्वारा इंगित किया गया था, केवल प्रावधानों को विस्तृत करने के लिए था।

20. जिन अन्य प्रावधानों के संदर्भ में मामले की आगे जांच करने की आवश्यकता है, वे हैं संविधान का अनुच्छेद 121 और संविधान का अधिनियम।

21. यह सच है कि किसी अधिनियम के प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों को नियंत्रित या निर्धारित करते हैं, लेकिन जहां किसी अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट नहीं है, वहां अन्य प्रासंगिक सामग्रियों की सहायता लेने की अनुमति है। इसके अलावा, वर्तमान संदर्भ में, जहां अनुच्छेद 121 पर संविधान और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के गठन के प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है, अधिनियम उपयोगी सहायता प्रदान करता है और विद्वानों के तर्कों में आग्रह किए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसका महत्व बहुत बढ़ा दिया गया है। हमारे सामने पक्षकारों के लिए परामर्श। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ महान्यायवादी के सभी विद्वान अधिवक्ता इस बात को लेकर सकारात्मक हैं कि यह अधिनियम पूरी तरह से वैध कानून है और इसका कोई भी हिस्सा अवैध या अधिकार से बाहर नहीं है। यह 90 पर है

[1991] एसयूपीपी। 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह आधार है कि याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाएं दायर की गई हैं और

प्रावधानों की व्याख्या स्वीकार की जाती है जिसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है एक्ट करें। इसके अलावा, राहत की नींव, जो रिट याचिकाओं में मांगी गई थी,

क्या अधिनियम और उसके तहत जांच है और यदि अधिनियम स्वयं जाता है, तो संदर्भ जाँच समिति को स्वयं गैर के रूप में माना जाएगा

कानून की नजर में मौजूद है और रिट याचिकाओं को खारिज करना होगा उस जमीन पर अकेले। इसलिए, हमें इस उद्देश्य के लिए मान लेना चाहिए कि

किसी भी राहत के हकदार पाए जाने पर, इसे प्रदान किया जा सकता है। मैं इस पर जोर दे रहा हूं। पहलू के रूप में अधिनियम मुख्य प्रश्न का पूरा उत्तर देता है

क्या समिति लोकसभा के नियंत्रण के अधीन है, और

क्या प्रावधानों का यह निर्माण अनुच्छेद के उद्देश्य को विफल कर देता है

121 .

22. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 एक संक्षिप्त अधिनियम है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

केवल सात खंड। खंड 1 शीर्षक और शुरुआत की तारीख देता है।

धारा 2 में परिभाषाएँ हैं और धारा 7 शक्ति से संबंधित है

नियम बनाएँ। अभिव्यक्ति "गति" जिसे परिभाषित नहीं किया गया है

इस योजना में अधिनियम महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से यह विषय रहा है।

इन मामलों की सुनवाई के दौरान काफी चर्चा हुई। द लोक

संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए सभा नियम "मो" से संबंधित हैं।

अध्याय XIV में। आचरण के लिए प्रक्रियाओं के अलग नियम हैं।

राज्य सभा द्वारा अपनाए गए कार्य। इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, मैं

केवल लोकसभा रूफ्स को संदर्भित करने का प्रस्ताव है। न्यायाधीशों की धारा 3 (1)(जाँच) अधिनियम, 1968 में कहा गया है कि यदि वर्तमान में "प्रस्ताव" का नोटिस दिया जाता है

एक न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, हस्ताक्षरित लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस का मामला,

और राज्य सभा में दिए गए नोटिस के मामले में, 50 से कम नहीं

सदन के सदस्य, अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो,

ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद जिन्हें वह उचित समझता है, साथ ही ऐसी प्रासंगिक सामग्री भी। अन्य जो उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, या तो "प्रस्ताव" को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं

एक ही बात स्वीकार करें। जिस तरह से यह धारा स्पष्ट रूप से परिभाषा या परिचय के बिना पहली बार अधिनियम में "प्रस्ताव" को संदर्भित करती है।

यह इंगित करता है कि यह उस "प्रस्ताव" का उल्लेख कर रहा है जो आम तौर पर संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में उनके संबंधित नियमों को आकर्षित करता है। धारा 3 में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि "प्रस्ताव" के इस नोटिस को कैसे और किसे संबोधित किया जाना है या सौंपा जाना है और यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा के नियमों को ध्यान में रखे बिना अध्यक्ष अचानक तस्वीर में कैसे आते हैं। नियम 185 में कहा गया है कि "प्रस्ताव" की सूचना महासचिव को संबोधित लिखित रूप में दी जाएगी और इसकी स्वीकार्यता नियम 186 में विस्तृत शर्तों को पूरा करेगी।

नियम 187 जे. यू. डी. एल. पर उप-समिति को निर्देशित करता है। उत्तरदायित्व "। यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.] 91

अध्यक्ष किसी "प्रस्ताव" या उसके किसी भाग की स्वीकार्यता की जांच और निर्णय करेंगे। नियम 189 में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष किसी "प्रस्ताव" के नोटिस को स्वीकार करते हैं और ऐसे "प्रस्ताव" पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की जाती है, तो इसे बुलेटिन में "नहीं-दिन-अभी तक-नामित प्रस्ताव" शीर्षक के साथ अधिसूचित किया जाएगा। यह इस स्तर पर है कि 1968 का अधिनियम धारा 3 (1) द्वारा मामले को अपने हाथ में लेता है और अध्यक्ष से इस "प्रस्ताव" को स्वीकार करने या इसे अस्वीकार करने के लिए ऐसे व्यक्तियों और सामग्रियों से परामर्श करने के बाद निर्णय लेने के लिए कहता है जो वह उचित समझते हैं। यह निष्कर्ष अटूट है कि अधिनियम के प्रावधानों को लोकसभा के कुछ नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। नियम 185,186 और 187 को अधिनियम का पूरक माना जाना चाहिए। इसके बाद धारा 3 की उप-धारा (2) आती है जो वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट "प्रस्तावों" को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष "प्रस्ताव को लंबित रखेगा" और विधियों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक को मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से और दूसरे को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से चुना जाएगा।

23. जिस स्थिति में "प्रस्ताव" लंबित है, वह इस मुद्दे पर लगभग निर्णायक है कि सदन ने इसे जब्त कर लिया है या नहीं। जब तक "गति" नहीं है

जिसे लंबित रहना है, जैसा कि धारा 3 (2) द्वारा निर्देश दिया गया है, वह सदन के बाहर है और अध्यक्ष यह स्वीकार करते हुए कि यह एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है न कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, जैसा कि हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं का मामला है, याचिकाकर्ताओं के पास अपना मामला बनाने के लिए कोई आधार नहीं होगा। यदि अध्यक्ष ने अध्यक्ष के रूप में "प्रस्ताव" को स्वीकार कर लिया है और परिणामस्वरूप, सदन का प्रतिनिधित्व करते हुए एक समिति का गठन किया है, तो यह पूरी तरह से उनके लिए और उनके माध्यम से सदन के लिए होगा कि वे समिति के भविष्य के संचालन के बारे में कोई और आदेश पारित करें, न कि इस न्यायालय के लिए, क्योंकि समिति को दोहरे नियंत्रण के अधीन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह पूछने का सवाल है कि "प्रस्ताव" कहां लंबित है, जिसका अधिनियम के प्रावधानों द्वारा तुरंत जवाब दिया जाता है, यह घोषणा करते हुए कि यह सदन में लंबित है। धारा 6 से मामले से संबंधित है

जब समिति की रिपोर्ट तैयार हो और उप-धारा (1) में कहा गया हो कि यदि रिपोर्ट न्यायाधीश के पक्ष में कोई निष्कर्ष दर्ज करती है, तो "सदन में लंबित प्रस्ताव" के साथ आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि रिपोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ जाती है, तो "धारा 2 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव, समिति की रिपोर्ट के साथ, सदन या संसद के उन सदनों द्वारा विचार के लिए लिया जाएगा जिनमें यह लंबित है"। अतः अधिनियम इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि "प्रस्ताव" सदन में लंबित रहता है न कि इसके बाहर। इसे फिर से धारा 3 (2) के प्रावधान में उपयोग की गई भाषा द्वारा सहमान्यता दी गई है जो उन मामलों से संबंधित है जहां संसद के दोनों सदनों में धारा 3 (1) के तहत एक ही तारीख को "प्रस्ताव" की सूचना दी जाती है। इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में, किसी भी समिति का गठन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि "प्रस्ताव" को "सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] में स्वीकार नहीं किया गया हो।

2 एस सी आर।

92

दोनों सदनों में और जहां ऐसा "प्रस्ताव" दोनों सदनों में स्वीकार किया गया है, समिति का गठन अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

आदमी। धारा 7 में दी गई नियम बनाने की शक्ति सामान्य शब्दों में है।

सामान्य के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कुछ विषयों की गणना करना

इसकी शक्ति, और दोनों सदनों की संयुक्त समिति को अनुमति देता है नियम बनाने के लिए संसद और तदनुसार, न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 बनाए गए। इन नियमों के नियम 2 (ई) में "प्रस्ताव" को

अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत स्वीकार किए गए प्रस्ताव के रूप में वर्णित किया गया है। धारा 6 (2) के प्रावधानों का पूरक, नियम 16 (2) में प्रावधान है कि "धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्वीकार किए गए प्रस्ताव की एक प्रति को ऐसे पते के अनुलग्नक के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा"। उप-नियम (4) में कहा गया है कि "उप के तहत तैयार किया गया पता

नियम (1) और प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में एक साथ मतदान के लिए रखा जाएगा।

संसद "। यह स्पष्ट है कि यह सदन में लंबित "प्रस्ताव" के अधिनियम में एक अनजाने में संदर्भ नहीं है; प्रावधान स्पष्ट रूप से त्रुटिहीन हैं।

यह इंगित करता है कि अधिनियम और नियम एक "प्रस्ताव" की परिकल्पना करते हैं और उससे निपटते हैं।

जिसे सदन में दाखिल किया जाता है और वहां लंबित रहता है, जिस पर समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा तारीख तय किए जाने पर फिर से विचार किया जाएगा। पूरे अधिनियम में भाषा लगातार रही है

इस आधार पर उपयोग किया जाता है और अंतःस्थापित या समझाया जाने में सक्षम नहीं है

दूर। अधिनियम या नियमों में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं के रुख को कोई समर्थन दे सके।

24. अधिनियम और नियमों का दायरा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए गए "प्रस्ताव" के अनुसरण में जांच तक सीमित है। जाँच के निष्कर्ष पर समिति को रिपोर्ट भेजनी होती हैमूल प्रस्ताव की एक प्रति के साथ अध्यक्ष (या यथास्थिति अध्यक्ष)। यदि निष्कर्ष न्यायाधीश के खिलाफ जाता है, तो अधिनियम की धारा 6 (2) निर्देश देती है कि प्रस्ताव, वही मूल प्रस्ताव,

रिपोर्ट को उस सदन द्वारा विचार के लिए लिया जाए जहां प्रस्ताव लंबित है। धारा 6 (2) के सुसंगत भाग में उल्लेख किया गया है:

" धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव समिति की रिपोर्ट के साथ उस सदन द्वारा विचार के लिए लिया जाएगा जिसमें वह लंबित है।

नियम 16 (4) में कहा गया है कि अभिभाषण और प्रस्ताव पर संसद के प्रत्येक सदन में एक साथ मतदान किया जाएगा। अधिनियम और नियम क्या कहते हैं

प्रारूप सदन द्वारा विचार के लिए लिया जाने वाला मूल प्रस्ताव है, और यदि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने पर समाप्त हो गया है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर अधिनियम काम करेगा। मूल मो की अवधारणा

समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति पर बहस और मतदान के लिए सदन में लंबित होना अधिनियम का जीवन और आत्मा है, और यदि वह प्रस्ताव गायब हो जाता है तो अधिनियम को आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

यह सब-जे. यू. डी. एल. पर समिति। लेखा योग्यता v. यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.] 93

विचार पूरे अधिनियम और नियमों के माध्यम से चलता है, और इसे एक विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। में लंबित एक प्रस्ताव का अस्तित्व

अधिनियम के लागू होने के लिए घर एक आवश्यक शर्त है। उसी के बिना, अधिनियम जीवित नहीं रहता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के इस रुख के अनुरूप अधिनियम को पढ़ने की अनुमति नहीं है कि सदन प्रस्ताव से अभिगृहीत नहीं है और जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक समिति के समक्ष लंबित जांच से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यदि अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) का अर्थ याचिकाकर्ताओं की ओर से सुझाए गए सुझाव के अनुसार लगाया जाता है, तोअधिनियम को अधिकार से बाहर या किसी भी स्थिति में निष्क्रिय और निष्फल के रूप में निरस्त करना होगा और केवल इसी आधार पर रिट याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।

25. यह तर्क दिया गया है कि यदि प्रस्ताव को सदन में इसके प्रवेश पर लंबित माना जाता है, तो अनुच्छेद 121 का उद्देश्य विफल हो जाएगा। आशंका गलत धारणा प्रतीत होती है। सदन में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा के खिलाफ संविधान के आदेश का सम्मान करना सभी के लिए है, और इसे लागू करना अध्यक्ष का बाध्यकारी कर्तव्य है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुच्छेद 121 का संदर्भ और भावना से पालन किया जाए, और वास्तव में अंतिम अवधि के दौरान किसी भी दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है।

41 साल से अधिक। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या अध्यक्ष के लिए अनुशासन बनाए रखना संभव नहीं होगा, यदि प्रवेश पर प्रस्ताव

सदन में लंबित रहता है। 1968 के अधिनियम के पारित होने से पहले, प्रस्ताव, किसी भी अन्य प्रस्ताव की तरह, लोकसभा नियमों द्वारा शासित था, और नियम 189 ने अध्यक्ष को तारीख तय किए बिना इसे 'नहीं-दिन-अभी तक-नामित प्रस्ताव' के रूप में अधिसूचित करने और मामले पर केवल उचित स्तर पर चर्चा करने की अनुमति देने में सक्षम बनाया। अधिनियम के बाद, जो अध्यक्ष के विवेक के भीतर छोड़ दिया गया था, उसे अनिवार्य वैधानिक प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि प्रस्ताव सदन में लंबित रहेगा, जिसे न्यायाधीश के खिलाफ समिति के निष्कर्ष की प्राप्ति पर ही लिया जाएगा। इसलिए, सदन में प्रस्ताव की कोमलता अनुच्छेद 121 का उल्लंघन करने का आधार नहीं हो सकती है।

26. श्री सिब्बल ने हालांकि दावा किया कि सदन के सदस्य प्रारंभिक चरण से ही प्रस्तावित निर्णय पर अपनी राय व्यक्त करने के हकदार हैं और अपने तर्क के एक हिस्से के रूप में संयुक्त समिति के समक्ष श्री

सीतलवाड़ के बयान पर भरोसा करते हैं। श्री शांति भूषण ने श्री सीतलवाड़ के विचारों को इस आधार पर चुनौती दी कि वे अनुच्छेद 121 के साथ खिलवाड़ करेंगे। मुझे डर है कि ऊपर उल्लिखित श्री सीतलवाड़ के बयानों को दोनों पक्षों द्वारा ठीक से स्वीकार नहीं किया गया है। मैकिफाइड बिल, जिसके आधार पर 1968 का अधिनियम पारित किया गया था, तब तक मसौदा तैयार नहीं किया गया था और श्री सीतलवाड़ पहले के विधेयक पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, जिसने कार्यपालिका में एक न्यायाधीश को हटाने की शक्ति निहित की थी और [1991] एस. यू. पी. पी. पर एक रिपोर्ट प्राप्त होने तक संसद को तस्वीर से बाहर रखा था।

2 एस सी आर।

94

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता। यदि वह विधेयक पारित किया गया था, तो प्रभाव

यह होता कि जांच शुरू करने और रिपोर्ट के साथ समाप्त होने वाली पूरी कार्यवाही सदन के बाहर पूरी तरह से बनी रहती, एक व्याख्या जो हमारे सामने वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान अधिनियम पर भी करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यपालिका को शक्ति सौंपने पर आपत्ति मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि न्यायाधीश को हटाने का अनुच्छेद 124 का इरादा संसद के हाथों में छोड़ दिया जाना निराशाजनक होगा। समिति के अध्यक्ष के एक प्रश्न के उत्तर में श्री सीतलवाड़ ने कहा कि विधेयक (तब विचाराधीन) के प्रावधानों के परिणामस्वरूप संसद को तब तक पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा जब तक कि सदन को किसी अन्य निकाय का निष्कर्ष नहीं मिल जाता और यह संवैधानिक योजना के खिलाफ होगा। इस पृष्ठभूमि में जब उनका ध्यान अनुच्छेद 121 के बार की ओर खींचा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करके संसद में समय से पहले चर्चा को रोकना संभव है। उन्होंने इस संदर्भ में लोकसभा नियमों का उल्लेख किया और अध्यक्ष को अधिक शक्तियां देने की सिफारिश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक चरण में भी इस मामले को अध्यक्ष को नहीं सौंपा जाना चाहिए और उचित कदम उठाने के लिए इसे अध्यक्ष के हाथों में छोड़ दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के स्थान पर अध्यक्ष (और अध्यक्ष) के प्रतिस्थापन का सुझाव इस विचार के अनुसार था कि यह मामला संसद के दोनों सदनों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है जो संबंधित प्रतिनिधियों, अध्यक्ष और अध्यक्ष के माध्यम से अपने सदस्यों का निर्णय ले सकता है। श्री सीतलवाड़ के साक्षय के बारे में मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं उनकी राय को एक प्राधिकरण के रूप में नहीं ले रहा हूं, और मैंने 1964 के मूल विधेयक से शुरू होने वाले वर्तमान विधान के इतिहास में एक कदम के रूप में इसे ध्यान में रखा है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट (17 मई, 1966 को प्रस्तुत) विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियों को निर्धारित करती है।खंड (2) से संबंधित रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 में कहा गया है कि "विशेष न्यायाधिकरण" को "समिति" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और "अध्यक्ष" और "अध्यक्ष" को "यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि समिति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च

न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हो सकती है"। खंड (3) के संबंध में समिति की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

" समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करना और बनाए रखना

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका को होना चाहिए

जाँच प्रक्रिया के हर चरण से बाहर रखा गया

एक न्यायाधीश के कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता और वह

एक न्यायाधीश के खिलाफ किसी भी कार्यवाही की शुरुआत होनी चाहिए

संसद में एक प्रस्ताव के नोटिस द्वारा किया गया।

जे. यू. डी. एल. पर समिति-समिति: लेखा योग्यता v. यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.] 95

यह भी महसूस होता है कि किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले अध्यक्ष को संबोधित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना पर लोकसभा में प्रस्ताव के मामले में, उस सदन के कम से कम सौ सदस्यों द्वारा और राज्यसभा में प्रस्ताव के मामले में, उस सदन के कम से कम पचास सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, समिति की राय है कि अध्यक्ष या अध्यक्ष या दोनों, जो भी मामला हो, ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद जो वे उचित समझते हैं और ऐसी सामग्री पर विचार करने के बाद, जो भी उपलब्ध हो, प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं और यदि वे प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो उन्हें प्रस्ताव को लंबित रखना चाहिए और तीन सदस्यों वाली एक समिति का गठन करना चाहिए, जिसमें क्रमशः मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायविदों में से एक-एक को चुना जाए।

रिपोर्ट का पैराग्राफ 20 खंड (6) और प्रस्तावित परिवर्तनों से संबंधित है, जो सदन या सदनों में लंबित प्रस्ताव के साथ अधिक सुसंगत थे। अंततः, उपरोक्त संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए तर्ज पर एक और विधेयक का मसौदा तैयार किया गया और उसे अपनाया गया। श्री सीतलवाड़ की राय कानून के इस इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे इस रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

27. श्री सिब्बल द्वारा सामने रखा गया व्यापक प्रस्ताव कि सदन को मामले को इतने प्रभावी ढंग से जब्त कर लिया गया था कि प्रत्येक सदस्य को अधिकार प्राप्त हो

हालाँकि, किसी भी स्तर पर सदन में चर्चा की मांग स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह न केवल अनुच्छेद 121 का उल्लंघन करेगा, बल्कि 1968 के अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन करेगा। यह मान लेना सही नहीं है कि यदि व्यक्तिगत सदस्य के तत्काल चर्चा पर जोर देने के अधिकार से इनकार किया जाता है, तो इसका कारण संसद को प्रस्ताव के नियंत्रण से वंचित करना होगा। जब अध्यक्ष या तो

लोकसभा नियमों के तहत या 1968 के अधिनियम के तहत अधिकार का प्रयोग करता है, तो वह सदन की ओर से कार्य करता है। जैसे ही वह अध्यक्ष पद से हट जाता है, उसे इन सभी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता है। जब वह कार्य करता है तो सदन कार्य करता है। यह एक और बात है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर सकता है, और ऐसा करते समय, वह सदन के सदस्यों से भी परामर्श कर सकता है, लेकिन सदन में चर्चा की अनुमति दिए बिना। परामर्श, जिसकी अधिनियम अनुमति देता है, निजी प्रकृति का है, जो सार्वजनिक चर्चा के बराबर नहीं है, जबकि अनुच्छेद 121 का उद्देश्य सार्वजनिक बहस को रोकना है। अध्यक्ष के लिए यह भी खुला हो सकता है कि वह किसी कानूनी मुद्दे पर सदन से परामर्श करे जिसका उत्तर प्रश्नगत न्यायाधीश के आचरण के संदर्भ के बिना दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, मुद्दा (वर्तमान मामले में शामिल) कि क्या पुराने सदन के विघटन के कारण प्रस्ताव समाप्त हो गया है और

जाँच समिति निष्क्रिय है। जो वर्जित है वह सब कुछ नहीं है।

न्यायाधीश को हटाने के संबंध में; अवरोधक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश के आचरण के संबंध में चर्चा तक ही सीमित है।

28. श्री शांति भूषण ने दृढ़ता से तर्क दिया कि 1968 के अधिनियम का ऐसा भाग जो प्रारंभिक प्रस्ताव को निर्देशित या घोषित करता है

अध्यक्ष के सदन में लंबित रहने की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कानूनी कल्पना सीमित बनाने के रूप में की जानी चाहिए कि अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध समय से पहले नहीं हटाया गया है। मुझे इस निर्माण को अधिनियम पर रखने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। यह मुद्दा मूल विधेयक के संदर्भ में नहीं उठ सकता था, जिसे अंततः हटा दिया गया था, क्योंकि इसकी योजना के तहत मामला राष्ट्रपति के निर्देश के तहत सदनों के समक्ष विशेष न्यायाधिकरण की रिपोर्ट रखे जाने से पहले संसद तक नहीं पहुंच सकता था।

यह। याचिकाकर्ता वर्तमान अधिनियम पर एक व्याख्या रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वही निष्कर्ष निकल सकता है, यानी कि समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने तक संसद तस्वीर में नहीं आती है। यह मूल विधेयक के पक्ष में नहीं आने के साथ पूरी तरह से असंगत है।

संसद। लेकिन इस विचार के अलावा, हम मान लें कि याचिकाकर्ता सही हैं, और मामला संसद तक तब तक नहीं पहुंचता जब तक कि वह जांच रिपोर्ट के आधार पर विचार के लिए तैयार न हो जाए। यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि उस स्तर पर भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा बाधित है और इस स्तर तक पहुंचने से पहले चर्चा को रोकने के लिए अनुच्छेद 121 पर भरोसा करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए,

स्थिति को किसी भी कानूनी कल्पना की सहायता की आवश्यकता नहीं है। श्री शांति भूषण के तर्क को स्वीकार करने का परिणाम क़ानून के उपरोक्त प्रावधानों को पूरी तरह से अनावश्यक बनाना होगा। इसके अलावा, यदि यह एक कानूनी कल्पना का मामला होता जैसा कि सुझाव दिया गया था, तो यह ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड और फिन्सबरी बरो काउंसिल में लॉर्ड एस्क्विथ की टिप्पणियों को आकर्षित करेगा: 1952 ए. सी. 109, (कई मामलों में इस देश में इसका अनुसरण किया जाता है) इस प्रभाव के लिए कि यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए कहा जाता है, तो आपको उन परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक रूप से कल्पना करनी चाहिए जो, यदि अनुमानित स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से उससे उत्पन्न हुई होगी या उसके साथ हुई होगी; और यदि क़ानून कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए, तो यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, आपको उस स्थिति के अपरिहार्य परिणाम की बात आने पर अपनी कल्पना को चौंका देना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए। श्री शांति भूषण का वैकल्पिक सुझाव कि प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, और समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक सदस्य द्वारा फिर से एक नया प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए, इसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यदि प्रस्ताव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और इसलिए अस्तित्व में नहीं रहता है, तो अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध को उठाने के बारे में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि इसे कानूनी कल्पना की मदद से हल किया जा रहा है।

श्री शांति भूषण द्वारा जे. यू. डी. एल. पर उप-समिति को कुछ समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था।

अनुच्छेद 124 के खंड (4) के उस भाग से जिसमें दोनों सदनों में एक ही सत्र में मतदान की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान मुझे पूरी तरह से अप्रासंगिक लगता है। खंड में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि प्रस्ताव की सूचना के साथ शुरू होने वाली न्यायाधीश को हटाने के संबंध में पूरी कार्यवाही उसी सत्र के भीतर होनी चाहिए। यह केवल मतदान भाग को संदर्भित करता है। पूरे अधिनियम को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि उसमें वह भाषा, जो याचिकाकर्ताओं के मामले को पूरी तरह से ध्वस्त करती है, जानबूझकर सदन को मामले पर कब्जा करने के लिए चुनी गई थी, और परिणामस्वरूप समय से पहले चर्चा को रोकने के उद्देश्य से प्रस्ताव को लंबित रहने का निर्देश देने वाले प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार, अधिनियम ने अनुच्छेद 124 और 121 दोनों का उनकी वास्तविक भावना में बहुत सफलतापूर्वक सम्मान किया है, उन्हें बड़े करीने से सामंजस्य स्थापित किया है।

29. आइए हम याचिकाकर्ताओं के एक अन्य तर्क पर विचार करें कि अनुच्छेद 124 के खंड (4) में होने वाले "साबित दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर" अभिव्यक्ति के कारण यह माना जाना चाहिए कि जब तक किसी अन्य निकाय द्वारा दुर्व्यवहार या असमर्थता का प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक

सदन द्वारा प्राप्त, मामला उसके दायरे में नहीं आता है। खंड (4) के विचार में निकाय एक प्राधिकरण हो सकता है, जो संसद के किसी भी सदन या अध्यक्ष या अध्यक्ष के साथ पूरी तरह से असंबद्ध हो सकता है, और संसद का उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। ऐसा प्राधिकार विशुद्ध रूप से वैधानिक होगा, जो संसद के अनुशासन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। केवल इस कारण से कि खंड (5) के तहत एक क़ानून प्रारंभिक चरण में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को सौंपकर इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करता है, वह एक वैधानिक प्राधिकरण नहीं रह सकता है। दूसरे शब्दों में, वह कानून द्वारा निहित शक्ति के तहत अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करता है, न कि प्रतिनिधि के रूप में। मुझे खंड (4) और (5) का यह निर्माण स्वीकार्य नहीं लगता है। वस्तुतः, यह संसद को संविधान द्वारा विशेष रूप से निहित न्यायाधीश को हटाने की शक्ति से वंचित कर देगा। आइए हम वर्तमान अधिनियम की उपेक्षा करें और याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए स्पष्ट शब्दों में प्रावधानों के साथ एक अन्य क़ानून पर विचार करें, जो संसद, अध्यक्ष और अध्यक्ष से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण को हकदार बनाता है। यदि इसकी अनुमति दी जा सकती है तो यह संसद को एक असहाय दर्शक तक सीमित कर देगा, जो किसी शिकायत पर कार्रवाई करने या उसे नजरअंदाज करने के लिए वैधानिक लेखक पर निर्भर है। यह किसी न्यायाधीश को हटाने की शक्ति विशेष रूप से संसद को सौंपने के संविधान के इरादे का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि संसद प्रारंभ से अंत तक मामले के नियंत्रण में है और उसने उपरोक्त मूल विधेयक पर संयुक्त समिति की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए और 1968 के अधिनियम को पारित करते हुए ठीक से कार्य किया। अध्यक्ष की शुरूआत और मामले को शुरू करने के लिए किसी भी सदन के बड़ी संख्या में सदस्यों की आवश्यकता से, [1991] एस. यू. पी. पी.

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

98

सदन को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यवाही के नियंत्रण में लाया जाता है

अध्यक्ष या अध्यक्ष। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "साबित करने का आधारदुर्व्यवहार या अक्षमता "केवल मामले को सामने रखने के लिए आवश्यक है।

खंड (4) के तहत सदन में मतदान करें, और इसके लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है

इस संबंध में कार्यवाही शुरू करना और आगे कदम उठाना।

30. श्री सिब्बल ने तर्क देते हुए एक और चरम दृष्टिकोण पेश किया

कि न्यायाधीश के पक्ष में समिति का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता हैकिसी कानून के सीमित दायरे के कारण संसद पर बाध्यकारी होना

खंड (5) के तहत पारित किया गया। इस तर्क में कोई सार नहीं है। खंड

या असमर्थता और खंड (5) इसे निर्धारित करने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है जिस तरह से ऐसा करना संभव हो। यह सच है कि

संसद औपचारिक रूप से कानून बनाए बिना अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। द.

विचाराधीन सदन कानून के अभाव में प्रक्रिया पर निर्णय ले सकता है

किसी दिए गए मामले में इसका पालन किया जाना था, लेकिन यह पारित करने के लिए पूरी तरह से खुला था

एक सामान्य संहिता निर्धारित करने वाला अधिनियम जिसका पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि अधिनियम निरस्त नहीं हो जाता यासंशोधित किया गया। यह एक बड़े निकाय को सौंपने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है।

स्पष्ट व्यावहारिक कारणों से एक छोटे निकाय के लिए जांच, और इस तरह के एक अभ्यास को अधिकार के त्याग में लिप्त होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह.

संसदीय समिति से इस विवाद की जांच करने के लिए कहा जा सकता था

वह यहाँ आकर्षित होता है। उस मामले में उच्च की प्रशासनिक समिति न्यायालय के नियमों के तहत गठित न्यायालय ने निर्णय लिया कि जिला

न्यायाधीश को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए, और पंजीयक

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्णय से अवगत कराया और उसके बाद उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को उनके लिए वितरित किया गया

जानकारी दी। राज्य सरकार ने जिले को सेवानिवृत्त करने के आदेश पारित किए

एक पूर्ण पीठ द्वारा सुना गया और अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि रिट याचिकाकर्ता को राय पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था

प्रशासनिक समिति द्वारा दर्ज किया गया, क्योंकि पूर्ण न्यायालय नहीं था

सलाह ली। आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार एक रिट जारी की गई। राज्य सरकार की अपील पर इस न्यायालय ने निर्णय रोक को उलट दिया

यह मानते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को यह व्यवस्था बनाने के लिए अधिकृत करता है

जिस तरीके से उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना था, उसे निर्धारित करने के लिए नियम और यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि अनुच्छेद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण संवैधानिक

रूप से उच्च न्यायालय में निहित है, लेकिन यह इस बात का पालन नहीं करता है कि उच्च न्यायालय को उस तरीके को निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है जिसमें उस नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है; और वास्तव में, वही परिस्थिति जिसमें नियंत्रण की शक्ति, जो एक व्यापक प्राधिकरण के मामलों को समझती है, न्यायाधीशों के पूरे निकाय में निहित होती है।

यह अनिवार्य बनाता है कि नियम बनाए जाएं ताकि नियंत्रण का अभ्यास व्यवहार्य, सुविधाजनक और प्रभावी हो। संसद उच्च न्यायालय की तुलना में कहीं अधिक बड़ी संस्था है और टिप्पणियां उस पर अधिक बल के साथ लागू होती हैं। जब तक कानून सदन को सीधे या अध्यक्ष के माध्यम से अपना नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम बनाता है, तब तक जांच को सौंपना शक्ति का त्याग नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें संसद ने समिति के फैसले का सम्मान करने का निर्णय लिया है। न्यायाधीश के पक्ष में, खंड (4) के अनुरूप और कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

31. प्रत्यर्थियों की ओर से यह कहा गया है कि क्या प्रत्यर्थी के खिलाफ प्रस्ताव नहीं है। 3 इसके परिणामस्वरूप समाप्त हो गया है

पुराने सदन के भंग होने से लोकसभा के सदस्यों के मन में हलचल हो रही है और यह मुद्दा नए अध्यक्ष के विचाराधीन है। समर्थन में, उन्होंने सदन की कार्यवाही की एक प्रति प्रस्तुत की। यदि वर्तमान अध्यक्ष का मानना है कि प्रस्ताव समाप्त हो गया है और समिति का कोई कर्तव्य नहीं है, तो कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जवाब में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दावा किया कि मामला समिति को सौंपे जाने के बाद, न तो वह और न ही संसद इस स्तर पर पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने को रद्द कर सकते हैं, या जांच को वापस ले सकते हैं। यदि याचिकाकर्ता सही हैं, तो क्या होगा यदि समिति का कोई सदस्य किसी भी कारण से अनुपलब्ध हो जाता है, जो कोई भी या कोई अन्य सदस्य समिति के गठन के बाद संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ या पक्ष में अपने स्पष्ट और घोर पूर्वाग्रह के कारण समिति में होने के लिए खुद को अयोग्य ठहराता है? इसका उत्तर यह है कि जो सदन कार्यवाही के नियंत्रण में है, वह मामले में सभी आवश्यक और प्रासंगिक कदम उठाने का हकदार है, सिवाय न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने के जब तक कि चरण तक नहीं पहुंच जाता और अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटा नहीं लिया जाता। यदि दूसरी ओर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि समिति एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो सीधे या अध्यक्ष के माध्यम से सदन के नियंत्रण के अधीन नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं का सुझाव है, तो अधिनियम को अव्यवहारिक बना दिया जा सकता है। इसके अलावा, यह संसद पर यह आरोप लगाएगा कि उसने ठीक वैसा ही किया जैसा संविधान सभा ने सर अल्लादी की भावपूर्ण अपील को स्वीकार करके करने से इनकार कर दिया था, जिसका उल्लेख पैरा ग्राफ 19 में ऊपर किया गया है, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की गरिमा को कम करने के लिए उन पर अपील करने के लिए 5 या 4 न्यायाधीशों की एक मशीनरी प्रदान करके। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान ने लोक सेवा के किसी सदस्य के कथित दुर्व्यवहार की जांच को सौंपना उचित समझा है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या निम्न पद के किसी अन्य व्यक्ति को संबद्ध किए बिना सर्वोच्च न्यायालय में आयोग, एक संवैधानिक पदाधिकारी लेकिन एस. यू. प्रीमे न्यायालय से कम रैंक का होता है। यदि समिति को सदन में लंबित कार्यवाही के उद्देश्य के लिए सहायता करने की दृष्टि से संसद की देखरेख और नियंत्रण में कार्य करते हुए माना जाता है, तो यह संसद होगी जो कार्यवाही के नियंत्रण में होगी, न कि समिति।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] एस. यू. पी. 2 एस सी आर।

. 100

32. श्री जेठमलानी ने इसका अर्थ निकालने के लिए उत्साहपूर्वक आह्वान किया

संविधान और अधिनियम इस तरह से जो स्वतंत्रता की रक्षा करेगा राजनेताओं से न्यायपालिका की, और यह, उनके अनुसार, संभव है

केवल तभी जब यह न्यायालय प्रश्न पर सकारात्मक निष्कर्ष पर आता है

न्यायसंगतता। एक की आवश्यकता पर दो राय नहीं हो सकती हैं

हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निडर न्यायपालिका, लेकिन यह

इससे आगे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता

जब तक उच्चतम स्तर पर भी न्यायाधीशों को हटाने का मामला न्यायालयों के अंतिम नियंत्रण के अधीन नहीं है, तब तक यह खतरे में होगा। उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संविधान निर्माताओं द्वारा इस पहलू पर बहुत सावधानी बरती गई थी और योजना को अपनाने से पहले मामले की हर संभव कोण से जांच की गई थी, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था। जहाँ तक

जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों का संबंध है, नियंत्रण हैउच्च न्यायालय में निहित किया गया था, लेकिन जब यह उच्च न्यायालय में आया और

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, यह रखरखाव के लिए पर्याप्त माना जाता था

जैसा कि हम पाते हैं, संविधान को अपनाने और लागू करने की उनकी स्वतंत्रता। मैं करता हूँ।

संविधान सभा के विवेक पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता है इस मामले को विशेष रूप से संसद के हाथों में सौंपना और मैं करता हूँ

सन्देह का कोई आधार नहीं है कि संसद के सदस्य या उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष और अध्यक्ष, में कार्य नहीं करेंगे

संवैधानिक प्रावधानों की वास्तविक भावना। इसी तरह, अधिनियमित करने का कार्य

खंड (5) के तहत एक कानून को प्रत्येक संबंध पर विचार करके गंभीरता से लिया गया था। अधिनियम पारित होने से पहले इस प्रक्रिया में कई साल लग गए।

मैं इस मुद्दे पर आगे यह कहने से परे बात करने का प्रस्ताव नहीं करता किसंविधान का जनादेश हम सभी के लिए बाध्यकारी है, और मैं इसे समाप्त करूँगा

हैमिल्टन के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत करते हुए:

" यदि मानव जाति सरकार की किसी भी संस्था में सहमत नहीं होने का संकल्प लेती, जब तक कि इसके हर हिस्से को पूर्णता के सबसे सटीक मानक के साथ समायोजित नहीं किया जाता, तो समाज जल्द ही अराजकता का एक सामान्य दृश्य और दुनिया एक रेगिस्तान बन जाएगी। पूर्णता का मानक कहाँ पाया जा सकता है? कौन जिम्मेदारी लेगा

एक पूरे समुदाय की असंगत राय को उसके एक ही निर्णय में एकजुट करना; और अपने अधिक घमंडी पड़ोसी के दोषपूर्ण मानदंड के लिए अपने अचूक मानदंड को त्यागने के लिए एक घमंडी परियोजना पर जोर देना? संविधान के विरोधियों के उद्देश्य का जवाब देने के लिए, उन्हें यह साबित करना चाहिए, न कि केवल यह कि इसमें विशेष प्रावधान सबसे अच्छे नहीं हैं।

कल्पना की गई है, लेकिन कुल मिलाकर यह योजना खराब और विनाशकारी है।

33. याचिकाकर्ताओं की ओर से या उनके द्वारा इसका सुझाव नहीं दिया गया है।

कोई अन्य व्यक्ति कि खंड (4) के तहत संसद द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय की वैधता की जांच करना न्यायालय के लिए खुला है।

फैसले के बाद भी सब-कमेटी ऑन JUDL.ACCOUNTABILITY v। यू. ओ. 1. [शर्मा, जे।] 101

न्यायाधीश के खिलाफ समिति, संसद या उस मामले के लिए दोनों सदनों में से कोई भी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने से इनकार कर सकता है, और न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। क्या इन परिस्थितियों में यह कल्पना की जा सकती है कि जाँच के मध्यवर्ती चरण में न्यायालय को हस्तक्षेप करने की शक्ति मिली है? जवाब एक से अधिक कारणों से नकारात्मक है। यदि सदन का नियंत्रण कार्यवाही पर जारी रहता है, जिसका प्रयोग अध्यक्ष के माध्यम से किया जा सकता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि न्यायालय के पास एक समानांतर अधिकार क्षेत्र है, जिसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा, अदालत से कदम सहायता की प्रकृति में आदेश पारित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जहां अंतिम परिणाम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश या जारी किए गए निर्देश के परिणामस्वरूप केवल व्यर्थता की कवायद हो सकती है, और देश के सर्वोच्च न्यायिक

और विधायी प्राधिकरणों दोनों के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो सकती है। संविधान को इस तरह के इरादे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, मेरा मानना है कि उच्चतम न्यायालय सहित न्यायालयों के पास उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही के संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

34. कई अन्य देशों के संविधानों के पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा संदर्भ दिया गया था, लेकिन मैं इसे आवश्यक नहीं मानता।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान को छोड़कर उन पर चर्चा करने के लिए क्योंकि वे बिल्कुल भी सहायक नहीं हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 124 (4) की भाषा राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया संविधान अधिनियम (1900) की धारा 72 (ii) के समान है, सिवाय इस अंतर के कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान अधिनियम विशेष रूप से प्रक्रिया और जांच को विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने का प्रावधान नहीं करता है। हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया में संवैधानिक और कानूनी स्थिति हमारे सामने वर्तमान विवाद को हल करने में सहायक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया संविधान अधिनियम (1900) ने कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के कठोर पृथक्करण को अपनाया है (जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर देखा गया है, जिसमें श्रीमती के पृष्ठ 415 पर भी शामिल है। इंदिरा गांधी। राज नारायण, [1976] 2 एस. सी. आर. 347, पैराग्राफ 9 में ऊपर उल्लिखित है। पी. एच. लेन ने ऑस्ट्रेलियाई संविधान पर अपनी टिप्पणी में संविधान अधिनियम की धारा 72 (ii) के तहत श्री न्यायमूर्ति मर्फी को हटाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही का संदर्भ दिया है। सीनेट की प्रवर समिति के सदस्यों के बीच तीखे मतभेद के कारण ए. पी. ने मामले की जांच करने और दूसरी समिति की स्थापना करके स्थिति को हल करने में और विफलता की ओर इशारा किया और कुछ अन्य तथ्यों को देखते हुए संसदीय जांच आयोग अधिनियम, 1986 के नाम से एक तदर्थ कानून पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत आगे के कदम उठाए जा रहे थे जब न्यायमूर्ति मर्फी ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले निषेधाज्ञा के आदेश के लिए ऑस्ट्रेला के उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि अधिनियम (ए [1991] एस. यू. पी. पी. के तहत गठित आयोग के सदस्यों में से एक।

2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

102

सेवानिवृत्त न्यायाधीश) को पक्षपात के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह था आवेदन

न्यायसंगतता के प्रश्न पर ध्यान दिए बिना गुण-दोष पर खारिज कर दिया गया।

मेरे विचार से यह निर्णय हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं के लिए कोई मददगार नहीं है।

मुख्य रूप से संवैधानिक योजना में अंतर के कारण

1900 का संविधान अधिनियम। लेन ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 372 पर कहा है किधारा 72 (ii) गैर-न्यायोचित हो सकती है, क्योंकि यह अभ्यास को स्थान देती प्रतीत होती है।

संसद में ही धारा के तहत। हालाँकि, वह आगे बढ़ता है कहते हैं कि संसद उच्च न्यायालय की मदद ले सकती है, उदाहरण के लिए,

दुर्व्यवहार या अक्षमता के अर्थ की परिधीय बात

धारा 72 (ii)। उन्होंने कुछ अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया हैसंविधान अधिनियम, और अपने साथ संसद और न्यायालय की भूमिकाओं का विश्लेषण किया

टिप्पणियाँ करें। मैं कहने से आगे बढ़ना आवश्यक नहीं समझता।

कि श्री न्यायमूर्ति मर्फी का मामला निर्णय लेने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है हमारे सामने मामलों में मुद्दा। हालाँकि हमारा संविधान उसके बाद बनाया गया था

कई अन्य देशों के संविधानों की जांच करते हुए, इसने एक

अपना खुद का पैटर्न। विद्वान वकील ने भी बड़ी संख्या में

भारतीय और विदेशी दोनों तरह के निर्णय और जब से मैंने उन्हें संबंधित नहीं पाया हैहालाँकि, मैंने उन पर चर्चा करने से परहेज किया है। कोई मामला नहीं जिसमें

इस न्यायालय ने या तो सदन के निर्णय में हस्तक्षेप किया है या किया हैएक न्यायाधीश को हटाने के लिए एक कार्यवाही से संबंधित, ऐसा करने से इनकार कर दिया, और हैं

ऊपर व्यक्त की गई मेरी राय को देखते हुए स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है। मैं भी हूँ।

श्री सिब्बल द्वारा आग्रह किए गए अन्य बिंदुओं पर विचार नहीं करना, क्योंकि मैं उनसे सहमत हूं।

न्यायसंगतता के मुख्य मुद्दे पर। मैं कोई भी राय व्यक्त करने से बच रहा हूं।

इस विवाद पर कि क्या पूर्ववर्ती सदन के विघटन पर प्रस्ताव समाप्त हो गया या नहीं, क्योंकि यह मुद्दा लोकसभा को तय करना है।

35. उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए यह न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।

चाहे वह इस प्रार्थना पर स्थायी हो या अस्थायी कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। 1991 की स्थानांतरण याचिका संख्या 278 में 1991 की रिट याचिका संख्या 1061 के हस्तांतरण के लिए अनुरोध की अनुमति है और उस रिट याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

एन. पी. वी